मूल्य 30/-

मार्च 2018

डायलॉग इंडिया

परिवर्तन की चाह संवाद की राह

लोन की लूट और

कारपोरेट वॉर

Career Magazine
DIALOGUEINDIA
Dialogue for Change in Education

Portal for Current News & Analysis :
www.dialogueindia.in

डायलॉग इंडिया

Portal for Career & Competition
www.dialogueindiaacademia.com

4th DIALOGUE INDIA Academia Conclave 2018

PM Modi Vision "Youth for New India"

Confrence & Exhibition on Innovative Design

In association with Industrial Design Section

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
Indian Institute of Technology Delhi

9th DIALOGUE INDIA National Ranking 2018

6th DIALOGUE INDIA Academia Awards 2018

AWARD CATEGORIES :

Top Private Universities of India • Top Private Medical Colleges of India • Top Private Dental Colleges of India • Top Private Engineering Colleges of India • Top Private Management Colleges of India • Top Colleges of all categories on Infrastructure / Placement / Innovation / Upcoming wise • Best V.C. / Director / Principal of Universities / Institutes / Colleges of India • Best Engineering Colleges : State/Zone/National wise • Best Management Colleges : State/Zone/National wise • Editor Choice Education Excellency Award

In the month of April, May & June at Delhi, Calcutta, Pune & Banglore

For Business Enquiry Please Contact
dialogueindia.in@gmail.com
08860787583

OUR ASSOCIATES

CONSORTIUM FOR INNOVATION

ENGINEERS ZONE
IES GATE PSUs

FMA DIGITAL

axima
Adopt Today, Lead Tomorrow

विषय सूची

डायलॉग इंडिया

मार्च, 2018

राष्ट्रनीति बनाम राजनीति

14

लोन की लूट और कॉर्पोरेट वॉर

26

आधी आबादी की नई जंग

42

20

राफेल युद्धक विमान : तथाकथित स्कैम सच्चाई और तर्क

52

व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की उपयोगिता बढ़ाने के पांच सूत्र

06 मध्य पूर्व में डंका, पड़ोस में डंडा

10 मौलिक भारत ने की केजरी के खिलाफ कार्यवाही की मांग

24 पहाड़ों में गूंजा सूफीवाद का संदेश

25 जान माल को लीलती हाइवे की 31 विसंगतिया

40 जीवन के स्वाध्याय का विज्ञान – आयुर्वेद

51 मौलिक भारत का राष्ट्रीय अधिवेशन व स्थापना दिवस

58 उपभोकता जागरूकता से ही बदलेगी स्वास्थ्य सेवा की तस्वीर

54 नेपाल के अरबपति बिनोद चौधरी की आत्मकथा का विमोचन

हमारे बारे में

डायलॉग इंडिया

वर्ष- 9 अंक- 7

संपादक
अनुज कुमार अग्रवाल

प्रबंध संपादक
डॉ. सारिका अग्रवाल

विशिष्ट संपादक
अभिषेक गुप्ता, अमित त्यागी

विशेष संवाददाता
शरीफ भारती, आर.एन. द्विवेदी, आदित्य गोयल
डॉ विजय अग्रवाल, हिमाद्रिश सुवान

उप संपादक
सोनाली मिश्रा

मुख्य प्रबंधक (विज्ञापन, वितरण एवं प्रसार)
विजय कुमार

जन सम्पर्क अधिकारी
पंकज कुशवाहा

ब्यूरोचीफ
उत्तर प्रदेश - एस.पी. सिंह
मध्य प्रदेश - संजीव चोकोटिया
हरियाणा एवं पंजाब - नवीन कांगो
हिमाचल प्रदेश - संजीव वर्मा
राजस्थान - रामस्वरूप रावतसरे
उत्तराखंड - राजेश गुप्ता
उड़ीसा - अश्विनी जैना
दिल्ली - जितेन्द्र तिवारी
महाराष्ट्र - तेजेन्द्र सिंह

डिजाइन एवं ग्राफिक्स
विकास, मनीष, दीपक

मुख्य कार्यालय : 301/ए, 37-38-39
अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स
मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन : 011-27652829, 08860787583
फैक्स : 011-27654588
ई-मेल : dialogueindia@yahoo.in
dialogueindia.in@gmail.com
ई-पत्रिका : **www.dialogueindia.in**

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक अनुज कुमार अग्रवाल द्वारा स्टेलेंट प्रिंट एन पैक, ए-1, डीएसआईडीसी कॉम्पलैक्स, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली से मुद्रित एवं 301, 37-38-39, अंसल बिल्डिंग, कॉमर्शियल कॉम्पलैक्स, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009 से प्रकाशित

© सर्वाधिकार सुरक्षित

मार्च, 2018 माह के लिए प्रकाशित

- डायलॉग इंडिया में प्रकाशित सभी लेख एवं सामग्री लेखकों के स्वयं के हैं, इससे प्रकाशक व सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।
- किसी भी विवाद की स्थिति में हमारा न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

प्रतिक्रियाएं

भूल सुधार

डायलॉग इंडिया के फरवरी अंक में नेशनल मेडिकल कमिशन बिल और आईएमए द्वारा उसका विरोध नामक लेख में लेखक के स्थान पर अरूण तिवारी का नाम भूलवश प्रकाशित हो गया था जबकि इसके मूल लेखक आशुतोष कुमार सिंह हैं। इस संपादकीय त्रुटि हेतु हमें खेद है।

बात बस चुनाव की है

चूंकि जुलाई में पाकिस्तान में आम चुनाव होने जा है और सत्तारूढ़ दल ने कुछ खास करा नहीं, ऐसे में जनता का ध्यान विकास व स्थानीय मुद्दों से हटा भारत व हिंदुओं से दुश्मनी पर केंद्रित करना है इसलिए जम्मू कश्मीर व सीमाओं पर झड़प, घुसपैठ, गोलाबारी व आतंकी घटनाएं बढ़ गयी हैं। फिलहाल पाक सेना ने सर्वोच्च न्यायालय की मदद से भारत प्रेमी नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर अपने अनुरूप सरकार का पुनर्गठन कराया हुआ है और आम चुनावों में वो एक कट्टरपंथी व अपनी पिट्ठू सरकार बनाना चाहती है, इसलिए भी उन्मादी माहौल पैदा किया जा रहा है। पाक सेना व आईएसआई को लगता है कि भारत तीव्र विकास की दौड़ में है और युद्ध आदि में नहीं उलझेगा। इसलिए केल्कुलेटेड रिस्क लिया जा रहा है। मगर पाक सेना यह भूल रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी इसी साल दिसंबर में भारत मे लोकसभा चुनाव कराने के मूड में है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक या छोटा मोटा आक्रमण ही पाकिस्तान पर न कर दिया जाए। देशभक्ति के ज्वार में मोदी जी के लिए भी चुनावी नैय्या पार कराने में आसानी होगी किंतु पाकिस्तान की हालत पतली व पाक सेना के दाव उल्टे पड़ सकते हैं। दक्षिण एशिया में अशांति से अमेरिका, रूस व चीन की बांछे खिलना तय है। एक तो कूटनीतिक हस्तक्षेप के बहाने वे पुन: इस क्षेत्र में बड़ा खेल खेल सकते हैं, साथ ही अपने हथियारों की बड़ी मात्रा में बिक्री भी।

डायलॉग इंडिया के समूह संपादक केन्द्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के साथ

तू देख तमाशा दुनिया का

कहने को तो लोकसभा चुनाव मई 2019 में होने है किंतु पक्ष और विपक्ष इन्हें सन 2018 के अंत में होने के हिसाब से मान अपनी चाले चलने लगा है। संसद में राष्ट्रपति के भाषण पर होने वाली बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार विपक्ष विशेषकर कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला किया व आरोपों की बारिश की उससे स्पष्ट हो गया कि वे अब अपने पुराने कथन की चार वर्ष राष्ट्रनीति व एक बर्ष राजनीति के अनुरूप राष्ट्रनीति पर रख विशुद्ध राजनीति पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने सोची समझी रणनीति के तहत आरोप लगाया कि यूपीए के काल मे बैंकों ने यूपीए नेताओं के इशारे पर गलत तरीके से लाखों करोड़ रुपयों के ऋण बांटे और उनपर ब्याज सहित लगभग 52 लाख करोड़ रूपयों का बैंकों व देश को चूना लगा। यह हैरान कर देने वाली रकम है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में विलफुल डिफॉल्टरों की बड़ी लंबी सूची भी जारी की है जिससे प्रधानमंत्री के कथन की पुष्टि होती है।अब मोदी सरकार के चार वर्ष पूरे होने वाले हैं और ऐन चुनावों से पूर्व उनका यह खुलासा और इसके बाद अंबानी परिवार के नजदीकी नीरव मोदी और मेहुल चौकसे एवं अडानी परिवार के नजदीकी विक्रम कोठारी के विरुद्ध ऋण घोटाले में कार्यवाही को राजनीतिक खेल के रूप में अधिक देखा जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार पर विपक्ष अंबानी – अडानी की सरकार होने का आरोप लगाता रहा है। देखा जाए तो बैंकों के इनसे भी बड़े बड़े डिफाल्टर देश मे पड़े है और हज़ारों देश छोड़ भाग चुके हैं किंतु आजतक सरकार ने उनके खिलाफ कोई बड़ी या विशेष कार्यवाही नहीं की। हाँ, मोदी सरकार के विमुद्रिकरण करने व जीएसटी लगाने के कदमों से और दिवालिया अधिनियम में संशोधन से सरकारी धन व बैंकों की लूट पर प्रभावी रोक लगी है । अब सरकार से धोखाधड़ी आसान नहीं। परंतु नीरव मोदी के मामले में जिस प्रकार पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई और हाल फिलहाल तक लूट चलने के सबूत मिले उन्होंने सरकार के दावों की पोल खोल दी। सच्चाई यह है कि नोटबंदी के दौरान ही देश की बैंकिंग व्यवस्था के खोखलेपन देश व सरकार के सामने आ गए थे और बैंककर्मियों द्वारा अनेक स्तरों पर की गई गड़बड़ियों के कारण नोटबंदी के बांछित परिणाम नहीं आ सके परंतु अनेक आंतरिक कारणों व दबाव के कारण सरकार बैंकिंग व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कुछ खास नहीं कर सकी। बैंकों द्वारा बड़े ऋण देने, उनकी वापसी व रिस्ट्रेकचरिंग की व्यवस्था में कुछ वरिष्ठ लोगों की ही प्रमुख भूमिका है और पूरी व्यवस्था बहुत संदिग्घ व अपारदर्शी है। वर्तमान में भी स्वायत्तता की तमाम बातों के बीच बैंकों पर सरकार के दबाव से इंकार नहीं किया जा सकता। जनता को लग रहा है कि सत्ता के पहले चार वर्षों में अंबानी – अडानी से गलबहियां सरकार की राष्ट्रनीति है और आखिर के वर्ष उनके प्यादों पर कार्यवाही राजनीति।

निश्चित रूप से मोदी सरकार व कॉरपोरेट घरानों के बीच नोटबंदी व जीएसटी के बाद संबंध सहज नहीं और कारपोरेट जगत का एक हिस्सा मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए परोक्ष रूप से विपक्ष के साथ मिल गया है व लोकसभा चुनावों में मोदी के तख्त पलट की कोशिश कर रहा है। इन सबके बीच पूरे देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में जिस प्रकार एक के बाद एक इन्वेस्टर्स समिट हो रही हैं व उनमे औद्योगिक घरानों की भागीदारी बढ़ती जा रही है यह मोदी सरकार की धारा की स्वीकृति के बड़े संकेत हैं। उम्मीद है सरकार का विरोध करने वाला कॉरपोरेट जगत का हिस्सा भी मूलधारा में लौट राष्ट्र निर्माण के कार्य मे हाथ बँटायेगा। निश्चित रूप से संघ परिवार व मोदी सरकार के लिए यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। इसी वर्ष पाकिस्तान में भी आम चुनाव है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की सेना व चीन की अवांछित गतिविधियां सीमा पर बढ़ गयी हैं ,यह चिंताजनक है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मध्य एशिया के देशों से जो प्रगाढ़ संबंध बनाए वे प्रशंसनीय व आश्चर्यजनक भी है, विशेषकर फिलिस्तीन व इजरायल दोनो को एक साथ साधना। किंतु भारत की अपने पड़ोसी देशों से दूरी बढ़ी है जो ठीक नहीं। घरेलू स्तर पर सामाजिक बदलावो की बड़ी बयार चल रही है। मोदी सरकार ने जो सैद्धान्तिक ढांचा खींचा है उसको व्यवहार में उतारने की कवायद अब जन आंदोलन का रूप लेने जा रही है। अब जनता शिक्षा, स्वास्थ्य , न्याय के क्षेत्र में बड़े बदलाव की मांग कर रही है। कुशासन, अराजकता व भ्रष्टाचार के खिलाफ आमजन खासा मुखर हो चला है। अप्रैल 2018 से जीएसटी पूर्ण रूप से लागू होने व ई गवर्नेन्स के बाद देश का आर्थिक व प्रशासनिक परिदृश्य पूरी तरह बदलने की उम्मीद है। इससे सरकारी योजनाओं को आमजन तक सही रूप में पहुंचना संभव हो जाएगा। मोदी सरकार के दीर्घकालिक योजनाओं के भी परिणाम आने शुरू हो चुके है ,चुनावी वर्ष में इनकी गति और बढ़ने की उम्मीद है। इस पूरे परिदृश्य में हम उम्मीद कर सकते हैं कि सन 2024 के लोकसभा चुनावों में राजनीतिक दलों को राजनीति करने की जरूरत कम ही पड़ेगी। कौन अधिक राष्ट्रनीति कर रहा है यही मुद्दा होगा। तब तक, हे मतदाता तू देख तमाशा दुनिया का।

अनुज अग्रवाल
संपादक

विदेश नीति

मध्य पूर्व में डंका, पड़ोस में डंडा

● उमेश चतुर्वेदी

भारतीय जनता पार्टी की छवि आमतौर पर मुस्लिम विरोधी रही है। जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, तब तक आम तौर पर माना जाता था कि अगर वह सत्ता में आई तो मुस्लिम देशों से उसके रिश्ते शायद ही अच्छे रह सकें। लेकिन सत्ता संभालते ही जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति के मोर्चे पर काम किया, उससे अपने सहोदर और इस्लामिक देश पाकिस्तान के मुकाबले भारत के रिश्ते मुस्लिम देशों से कहीं ज्यादा बेहतर बने हैं। इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन के अंत के पहले तक अरब जगत के तीन नेताओं की बदौलत भारत के रिश्ते लीबिया, फिलीस्तीन और इराक से कहीं ज्यादा गहरे रहे। इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन कश्मीर के मसले पर जहां हमेशा भारत के साथ रहे, वहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बदौलत फिलीस्तीन के नेता यासिर अराफात और लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी के साथ भारत के रिश्ते बेहतर रहे। लेकिन बाकी अरब देश या तो पाकिस्तान का राग अलापते थे ये भारत को किनारे रखते थे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। मध्यपूर्व में भारत की जहां पूछ बढ़ रही है, भारतीय विदेश नीति का वहां डंका बज रहा है, वहीं पड़ोस के मालदीव जैसे छोटे से देश भारत को अपने ठेंगे पर रख रहे हैं। शुफ है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है, अन्यथा वहां भी आए दिन भारत विरोधी गतिविधियां परवान चढ़ती रही हैं। जिस हिंदू राष्ट्र नेपाल से रोटी और बेटी के रिश्ते को लेकर उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए बंगाल तक की सीमा के लोग सहानुभूति रखते रहे हैं, वह नेपाल भी भारत विरोधी गतिविधियों को अपनी सरजमीं से बढ़ावा देने की कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष कोशिश करने से बाज नहीं आता। पाकिस्तान से तो उम्मीद भी करना कई बार बेकार लगता है, क्योंकि इस राष्ट्र का गठन ही नफरत की बुनियाद पर हुआ है, जिसे लाख कोशिशों के बावजूद दूर नहीं किया जा सका है।

इस्लामिक कानूनों और परंपरा से चलने वाले मध्य पूर्व के देशों की छवि कट्टरवादी रही है। लेकिन 11 फरवरी को ओमान के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के शासकों ने जिस तरह स्वागत किया, उससे यह छवि दरकती नजर आई। इस्लामी परंपरा में बुत पूजा स्वीकार्य नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ओमान में स्वामीनारायण संप्रदाय के मंदिर की नींव रखी और उसे जबर्दस्त समर्थन हासिल हुआ। इससे ओमान की अलग ही छवि बनी। यह कैसे संभव है कि बुत पूजा की परंपरा के विरोधी देश में वहां के शासक की अनुमति के बिना वहां मंदिर का निर्माण हो सके। इतना ही नहीं, ओमान से ऐसी भी खबरें आईं कि खुद हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर वहां के शासक परिवार की महिलाओं ने सम्मान सहित यात्रा भी की। इस मंदिर के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उमड़ी भीड़ इस बात की गवाही दे रही थी कि वहां भारत और मौजूदा सरकार को लेकर कैसी सोच है। इस दौरान भारत और ओमान के बीच आठ समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। जिनमें से सिविल और कारोबारी मामलों में कानूनी और न्यायिक सहयोग, विशेष सेवा, कूटनीतिक और आधिकारिक पासपोर्ट और वीजा के लिए आपसी सहयोग, स्वास्थ्य, अपनी सीमाओं का शांतिपूर्ण सहयोग, विदेश सेवा संस्थान और ओमान डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूट के बीच सहयोग, भारतीय रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान एवं नेशनल डिफेंस कॉलेज ऑफ ओमान के बीच सहयोग के साथ ही पर्यटन और रक्षा सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच सहयोग हुए। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते से भारत की स्थिति मध्य पूर्व में जहां मजबूत होने की संभावना बढ़ गई है, वहीं ओमान से सैनिक सहयोग के जरिए भारत मध्य पूर्व में भी अपनी गंभीर और प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है।

ओमान से पहले प्रधानमंत्री सऊदी अरब और फिलीस्तीन की भी यात्रा पर गए थे। नौ फरवरी को जब वे फिलीस्तीन गए तो उसकी ओर पूरी दुनिया का ध्यान था। यह तथ्य पूरी दुनिया जानती है कि फिलीस्तीन और इजरायल के बीच रिश्ते कैसे हैं? ऐसे हालात में मजबूत से मजबूत दिल वाले नेता फिलीस्तीन या गाजापट्टी की यात्रा करने से हिचकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहां की यात्रा करके साबित

कर दिया कि वे किसी और मिट्टी के बने हैं। उनकी यात्रा की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिलीस्तीन में वे जार्डन के हेलिकॉप्टर से पहुंचे और उनकी हवाई सुरक्षा का जिम्मा फिलीस्तीन के दुश्मन देश इजरायल की एयरफोर्स संभाले हुए थी। एक साथ फिलीस्तीन और इजरायल को साधना आसान काम नहीं है। लेकिन भारतीय विदेश नीति के कर्णधारों ने ऐसा कर दिखाया। फिलीस्तीन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में छह समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत भारत ने बेथलेहम में तीन करोड़ डॉलर की लागत से सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने, पचास लाख डॉलर की लागत से महिला सशक्तीकरण के लिए तुराथी केंद्र बनाने, रामल्ला में पचास लाख डॉलर की मदद से प्रिंटिंग प्रेस लगाने, दस लाख डालर की मदद से मुताल्ह अल शुहादा गांव में स्कूल बनाने, तमून गांव में 11 लाख डालर की मदद से स्कूल बनाने और अबूदीस संस्थान की लड़कों के लिए एक मंजिल बनाने के लिए ढाई लाख डालर की मदद का समझौता किया। एक तरफ भारत जहां इजरायल से सैनिक सहयोग और कृषि की तकनीक साझा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने फिलीस्तीन के निर्माण में मदद का हाथ बढ़ाया है। दिलचस्प यह है कि इसे लेकर इजरायल में कोई विरोध नहीं है। वैसे यहां याद दिला देना जरूरी है कि भारत ने 1988 से ही फिलीस्तीन को बतौर एक देश मान्यता दे रखी है।

हालिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात भी गए और वहां के शासकों से मुलाकात करके द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया। मध्य पूर्व में इजरायल का एक बड़ा दुश्मन ईरान भी है। लेकिन भारत का ईरान से भी रिश्ता बेहतर रहा है। ईरान के तेल के बड़े खरीददारों में से भारत भी रहा है। हालांकि कई बार भारत को इस मुद्दे पर अमेरिकी दबाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन भारत ने अपने संबंधों में संतुलन बनाए रखा है। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट भी कहती है कि भारत ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को लागू करने में आम तौर पर सहयोग ही किया है। वैसे जब ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगे थे, तब भी ईरान के साथ आंशिक रूप से भारत के आर्थिक रिश्ते बने रहे।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इजरायल से दोस्ती पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। भारतीय रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान की रिसर्च फेलो स्मृति पटनायक का कहना है, ईरान और भारत के बीच संबंधों की रणनीतिक वजहें हैं। इनका इस्राएल के साथ संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच 17 फरवरी को तीन दिन के दौरे पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी आए। ईरान और भारत के बीच इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही सुरक्षा, व्यापार एवं ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से बातचीत की, जिसके बाद दोनों पक्षों ने नौ समझौतों पर दस्तखत किए जिसमें दोहरे कराधान से जुड़ा एक समझौता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में ईरान का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने ईरान और पाकिस्तान सीमा पर स्थित चाबहार बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए पचास करोड़ डालर का सहयोग देने का ऐलान किया था। पाकिस्तान की अड़ंगेबाजी के चलते मध्य पूर्व से भारत के संपर्क के लिए आने वाले दिनों में यह बंदरगाह बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। इससे भारत की समृद्धि के लिए राह खुलेगी। चाबहार के जरिए अफ़ग़ानिस्तान के साथ ही केंद्रीय एशिया, रूस और केंद्रीय एशिया का लैंड लॉक्ड इलाक़े तक से भारत जुड़ जाएगा। भारत को अपनी जरूरतों के लिए ओमान से 1,100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन लानी है। भारत की तरफ से ईरान को तैयार करने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच सितंबर 2018 से चाबहार के संचालन की जिम्मेदारी भारत को मिल जाएगी। जाहिर है कि भारत अमेरिकी विदेश नीति के दबाव में आने की बजाय अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जरूरतों के मुताबिक अपनी विदेश नीति तय करने लगा है। इसे नरेंद्र मोदी की कामयाबी के तौर पर ही देखा जा रहा है।

लेकिन भारत के लिए समस्या उसके पड़ोसी वे छोटे देश हैं, जिनकी आर्थिक और राजनीतिक हैसियत बहुत छोटी है। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को भारत विरोध की चिंता ही नहीं और उन्होंने भारत की चिंताओं को दरकिनार करते हुए देश में आपातकाल तीस दिनों के लिए बढ़ा दिया। वहां संविधान का उल्लंघन आम हो गया है और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल गयूम समेत मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला सईद, सुप्रीम कोर्ट के जज अली हमीद और न्यायिक प्रशासक हसन सईद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल को उनसे अलग हो चुके सौतेले भाई और राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन द्वारा देश में आपातकाल लगाए जाने के कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। माना जा रहा है कि अब्दुल्ला यामीन चीन के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। दरअसल चीन भारत को घेरने की दिशा में मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के जरिए घेरने की कोशिश की है। श्रीलंका में हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन नेपाल की मौजूदा कम्युनिस्ट सरकार भी चीन की इच्छाओं के मुताबिक काम कर रही है, वहीं मालदीव को भारत की परवाह ही नहीं है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति नईम इन दिनों श्रीलंका में निर्वासित जीवन गुजार रहे हैं। उन्होंने वहां से अमेरिका और भारत से मालदीव के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। यह बात और है कि अभी तक भारत प्रभावी कार्रवाई करने से हिचक रहा है। 1988 में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम का तख्ता पलटने की कोशिश को भारतीय नौसेना ने नेस्तनाबूद किया था। पूर्व राष्ट्रपति नईम शायद इसी वजह से भारत से उम्मीद जताएं हुए थे। भारत के सामने बड़ी चुनौती यह है कि छोटे पड़ोसी देशों के खिलाफ कड़ा रवैया अख्तियार नहीं करना चाहता, ताकि उसकी छवि दादा जैसी नहीं बन सके। लेकिन उसे अगर प्रभावी भूमिका निभानी है तो इसके लिए उसे ऐसी राह अख्तियार करनी ही पड़ेगी, ताकि उसका प्रभाव भी बना रहे और छोटे देश उस पर आरोप भी नहीं लगा सके। ■

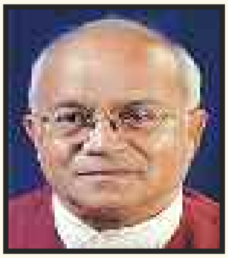

वेद प्रताप
वैदिक

बातों की उस्ताद : भारत-पाक सरकारें

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश पर दस्तखत करके सरकार को यह अधिकार दिया है कि वहां सक्रिय आतंकवादी गिरोहों पर वह प्रतिबंध लगाए, उनके दफ्तर बंद करे और उनके बैंक खाते रद्द करे। जाहिर है कि अमेरिकी दबाव के कारण पाक सरकार को मजबूर होकर यह करना पड़ रहा है। पहले भी कुछ आतंकवादी सरगनाओं पर वह मुकदमे चला चुकी है और कुछ को वह नजरबंद और गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें शक नहीं है कि इन आतंकवादियों के कारण पाकिस्तान सारी दुनिया में बदनाम हो गया है। इस्लाम की इज्जत भी खतरे में पड़ गई है। जितने लोग अफगानिस्तान और भारत में मारे जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा खुद पाकिस्तान में शिकार होते हैं लेकिन फिर भी वहां आतंकवाद की जड़ें सदा हरी होती जाती हैं। यह अध्यादेश तो प्रशसंनीय है लेकिन इसे नाकाम करना भी काफी सरल है। ये आतंकवादी अपने संगठनों के नाम बदल लेंगे या नए संगठन खड़े कर लेंगे। बैंक खाते भी नए नामों से खुल जाएंगे। जब तक पाकिस्तान की फौज इन गिरोहों के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ेगी, कोई सरकार इनका बाल भी बाका नहीं कर सकेगी। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, वह हर आतंकवादी हमले का जवाब बयानबाजी से देती है। सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री आजकल जुमलेबाजी को अपनी लाठी बनाए हुए हैं। बयानों और जुमलों की लाठियों के सहारे उन्होंने चार साल काट दिए हैं। कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि पाकिस्तान से बात किए बिना कश्मीर हल नहीं होगा। मोदी सरकार यही तो कर रही है। बातें बनाने में उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान और भारत, दोनों का चरित्र एक-जैसा सिद्ध हो रहा है। दोनों सरकारें बातों की उस्ताद हैं।

यामीन कब कहेंगे आमीन ?

मालदीव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी ने आपस में बात की है, यही काफी है, राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की अकड़ ढीली करने के लिए। दोनों के बीच बात क्या हुई, यह पता चलने की भी जरुरत नहीं है। यह पता चलना ही काफी है कि दोनों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के बारे में चिंता की है। अमेरिका और भारत, दोनों की सांझी चिंता चीन के लिए चिंता का विषय हो गया है। अब चीन मालदीव की संप्रभुता और उसके आतंरिक मामले की रट लगाने की बजाय अपने प्रेमी यामीन को सलाह दे रहा है कि वे विरोधी नेताओं से बात करें। चीन से कोई पूछे कि उन नेताओं को जेल में बंद रखकर और मोहम्मद नशीद को देश-निकाला देकर यामीन उनसे बात कैसे करेंगे ? अब चीन भारत से भी संपर्क कर रहा है। यह तो अच्छी बात है। यदि भारत को चीन आगे रखता है और यह मानता है कि दक्षेस का संपूर्ण इलाका भारत का प्रभाव-क्षेत्र है तो फिर समस्या का हल अपने आप निकल जाएगा। यामीन के इतने ज्यादा पंख इसीलिए उग आए हैं कि चीन उनकी पीठ थप-थपाता रहा है। अब चीन ने यह ठीक किया कि मालदीव में अपने प्रवासी नागरिकों की रक्षा के बहाने अपनी फौज भेजने से मना कर दिया है। चीन अपनी फौज भेज देता तो अन्य सभी महाशक्तियां एकजुट होकर मालदीव में हस्तक्षेप करतीं। जर्मनी और ब्रिटेन के राजदूत, जो कोलंबो से माले गए थे, यामीन ने उनसे मिलने से मना कर दिया। वे इस समय सउदी अरब और पाकिस्तान के चरण-चुंबन में लगे हुए हैं। वे 'इस्लाम खतरे में' का राग अलाप रहे हैं लेकिन क्या उन्हें पता नहीं है कि सउदी अरब अमेरिका का चेला है और पाकिस्तान की डोर आजकल अमेरिका ने खेंच रखी है ? भारत का इस्लाम से कुछ लेना-देना नहीं है। वह तो मालदीव के लोकतंत्र और संविधान पर आए खतरे को देख रहा है। यामीन जिन लोगों के खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं, वे भी मुसलमान हैं और अच्छे मुसलमान हैं। भारत चाहे तो इस समय संयुक्तराष्ट्र संघ और दक्षेस-राष्ट्रों से संयुक्त अपील जारी करने के लिए कह सकता है। सारे दांव-पेच आजमाने के बाद यदि यामीन, आमीन कहने को तैयार हों तो फौज भेजने की जरुरत ही क्यों पड़ेगी ?

ईरान को लाएं दक्षेस में

ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी की यह भारत-यात्रा दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में विशेष योगदान देगी। रुहानी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच दांत कटी रोटी है लेकिन इसके बावजूद रुहानी ने नई दिल्ली में भारत के प्रति अप्रतिम प्रेम का प्रदर्शन किया। उन्होंने न सिर्फ आतंकवाद का हर तरह से मुकाबला करने में भारत को साथ देने का वादा किया बल्कि अमेरिका को ऐसी झिड़की लगाई है, जो आज तक किसी भी विदेशी नेता ने नहीं लगाई ! रुहानी ने अमेरिका से पूछा कि आप पांच महाशक्तियां सुरक्षा परिषद में बैठी हैं लेकिन आप भारत को छठी महाशक्ति क्यों नहीं मानते ? आपके पास परमाणु बम है तो भारत के पास भी है और उसके पास सवा अरब लोग भी हैं। रुहानी ने अमेरिका से पूछा है कि वह भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों नहीं बनवाता ? ईरान और इस्राइल के संबंध कटुतम हैं लेकिन भारत ने दोनों को साध रखा है। रुहानी ने हैदराबाद की सुन्नी मक्का मस्जिद में जाकर भारत के शिया और सुन्नी मुसलमानों को पारस्परिक सदभाव का संदेश तो दिया ही, सीरिया, इँराक और अफगानिस्तान का जिक्र करके इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी करने का भी कड़ा विरोध किया। उनकी इस यात्रा के दौरान भारत-ईरान सामरिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को उच्चतर स्तर पर ले जानेवाले नौ समझौतों पर दस्तखत भी हुए। चाबहार के शाहिद बहिश्ती बंदरगाह के संचालन का ठेका अब भारत को डेढ़ साल के लिए मिल गया है। यह बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से सिर्फ 80 किमी दूर है। अब भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के पांचों राष्ट्रों तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की जरुरत नहीं रहेगी। मुंबई से हमारे जहाज अब सीधे चाबहार पहुंचेंगे। ईरान और अफगानिस्तान के बीच भारत अब रेल भी बनाएगा। कोई आश्चर्य नहीं कि मध्य एशिया से तेल और गैस की पाइपलाइनें भी समुद्री मार्ग से सीधे भारत आ जाएं। ईरान के साथ स्वास्थ्य, चिकित्सा, दवाइयों, खेती, विनिवेश आदि के समझौते तो हुए हैं, प्रत्यर्पण संधि और राजनयिकों की वीजा-मुक्ति पर भी समुचित प्रावधान हुए हैं। ईरान में भारत-विद्या और भारत में फारसी के पठन-पाठन पर भी विचार किया गया है। मेरी राय तो यह है कि ईरान को दक्षेस (सार्क) का भी सदस्य बनाया जाना चाहिए। यदि हम संपूर्ण दक्षिण एशिया (याने प्राचीन आर्यावर्त) में एक महासंघ खड़ा करना चाहते हैं तो ईरान उसके सबसे सशक्त स्तंभों में से एक होगा।

मोदी की सार्थक विदेश यात्राएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन-दिवसीय पश्चिम एशियाई यात्रा भारत के लिए काफी लाभदायक रही। वास्तव में यह चार-देशीय यात्रा हो गई, क्योंकि फलस्तीन की राजधानी रमल्लाह जाने के लिए जोर्डन की राजधानी अम्मान से उन्हें हेलिकॉप्टर लेना पड़ा। अम्मान में बादशाह अब्दुल्लाह से उन्होंने आतंकवाद आदि पर बात की। जब वे फलस्तीन पहुंचे तो उसके राष्ट्रपति महमूद अब्बास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने मोदी को फलस्तीन का सर्वोच्च सम्मान ग्रांड कॉलर प्रदान किया और मोदी ने 5 करोड़ डॉलर की सहायता की घोषणा की। मोदी ने फलस्तीनियों के हितों की रक्षा का वादा तो किया लेकिन पूर्वी येरुशलम को फलस्तीन की राजधानी बनाने और उस क्षेत्र में दो स्वतंत्र, सार्वभौम राष्ट्रों की बात को वे टाल गए। इन मुद्दों को उठाकर इस्राइल के घावों पर वे नमक क्यों छिड़कते, हालांकि भारत इन मुद्दों पर हमेशा दो-टूक राय रखता रहा है। मेरी राय है कि मोदी ने चुप रहकर ठीक किया, क्योंकि मोदी उन रायों को दोहराते तो इस्राइल नाराज़ हो जाता और फलस्तीन का कोई फायदा नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत ने अपनी राय बदल दी है बल्कि कुछ मामलों में सार्वजनिक तौर पर चुप रहकर परस्पर बोलना बेहतर कूटनीति होती है। जैसा कि इस यात्रा के पहले मैंने कहा था कि मोदी चाहें तो इस्राइल और फलस्तीन के बीच भारत मध्यस्थता कर सकता है। राष्ट्रपति अब्बास ने इस बात को बयान देकर दोहराया है। देखना है कि हमारा नेतृत्व इस मामले में सिर्फ प्रचार और नौटंकी से संतुष्ट हो जाता है या कुछ ठोस पहल भी करता है ? जहां तक संयुक्त अरब अमारात का सवाल है, वहां यह मोदी की दूसरी यात्रा है। उसके साथ रेल, ऊर्जा, सड़क, वित्त तथा अन्य क्षेत्रों में कई समझौते हुए हैं। अबूधाबी की तेल कंपनी में भारत ने 10 प्रतिशत का हिस्सा ले लिया है। मोदी ने एक मंदिर का भी उद्घाटन किया। संयुक्त वक्तव्य में आतंकवाद के विरुद्ध भी खुलकर मोर्चा लिया गया। सबसे महत्वपूर्ण यात्रा ओमान की रही। ओमान से भारत के संबंध पहले से ही घनिष्ट हैं लेकिन इस बार अदन की खाड़ी के मुहाने पर बसे दुक्म बंदरगाह की सुविधाओं के लिए जो समझौता हुआ है, वह पाकिस्तानी बंदरगाह ग्वादर पर होनेवाली चीनी दादागीरी का तगड़ा जवाब होगा। ओमान से यदि तेल और गैस की पाइपलाइन जल-मार्ग से सीधी भारत आ सके तो दक्षिण एशिया की शक्ल ही बदल सकती है। अब ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी की होनेवाली भारत-यात्रा मोदी की इन यात्राओं के संदर्भ में काफी प्रासंगिक रहेगी।

मौलिक भारत ने की केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही की मांग

प्रतिष्ठा में,

आयुक्त

दिल्ली पुलिस

दिल्ली

विषय : मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के विरुद्ध आपराधिक षडयंत्र के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही के संबंध में

महोदय,

मौलिक भारत सुशासन, पारदर्शिता, चुनाव सुधार, विकेंद्रीकरण व व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्षरत राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। देश के अनेकों प्रबुद्ध लोग संस्था से जुड़े हैं। संस्था के कार्यो के बारे में निम्न लिंक पर जाकर जान सकते हैं- संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की पुस्तिका-http://maulikb-harat.co.in/activity/

महोदय, मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा 19 फरवरी, 2018 की मध्यरात्रि को दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को अपने घर बुलाकर स्वयं व पार्टी विधायकों के द्वारा डराया धमकाया व पीटा गया। सरकारी अस्पताल द्वारा की गई मेडिकल जांच में भी मारपीट को पुष्टि हुई है।ऐसा कृत्य अत्यंत निंदनीय व अक्षम्य है। देश की राजधानी में राज्य सरकार के सबसे बड़े अधिकारी ही जब सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी। ऐसे में मौलिक भारत की मांग है कि सुनियोजित तरीके से आपराधिक षडयंत्र व साजिश कर अपनी ही सरकार के मुख्य सचिव को आधी रात अपने घर बुलाकर स्वयं व अपने ही विधायको से धमकाने व पिटवाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। उनका यह कृत्य असाधारण अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए तुरंत उनकी गिरफ्तारी व उनकी सरकार की बर्खास्तगी भी होनी चाहिए। यह आश्चर्यजनक है कि दिल्ली पुलिस ने मुख्य अपराधी व षडयंत्रकर्ता से अभी तक न ही कोई पूछताछ की और न ही उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज की। हमारा मानना है कि संवैधानिक पद की आड़ में केजरीवाल की पार्टी एक संगठित गिरोह बनती जा रही है। उनकी।पार्टी दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनोती बन गयी है। केजरीवाल व उनकी पार्टी के विघायको के विरूद्ध विभिन्न अदालतों में बहुत अधिक मात्रा में आपराधिक मुकदमें चल रहे हैं व स्वयं केजरीवाल अनेकों मामलों में जमानत करवाए हुए हैं। मौलिक भारत ने भी केजरीवाल द्वारा चुनावों के समय भरे जाने वाले शपथपत्र को पटियाला हाउस कोर्ट में चुनोती दी हुई है ,जिसमे प्रथम द्रष्टयता आरोप सही पाए गए व केजरीवाल को जमानत लेनी पड़ी है।

ऐसे में पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की ढिलाई या छूट एक बड़ी परेशानी बन सकती है। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र उचित कार्यवाही की जाए।

धन्यवाद।

भवदीय

अनुज अग्रवाल

महासचिव, मौलिक भारत

बर्खास्त हो गुंडई पर उतरी केजरीवाल सरकार

आर.के. सिन्हा

दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को मुख्यमंत्री आवास पर बुलवाकर अपने आम आदमी पार्टी(आप) के गुंडा चरित्र के विधायकों से सामने पिटवा कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली की शासन व्यवस्था को पूरी तरह ठप्प कर दिया है। यह तथ्य तो अब जगजाहिर हो ही चुका है। सवाल यह है कि आख़िरकार क्यों केन्द्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं?जनता इस यक्ष प्रश्न का उत्तर जानना चाहती है। इस सवाल का उत्तर तब ही मिलेगा जब हम दिल्ली विधानसभा और दिल्ली की सरकारों के इतिहास को थोड़ा सा खंगाल लेंगे।

दरअसल आजादी के बाद दिल्ली में 1952 में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे । दिल्ली के पहले यशस्वी मुख्यमंत्री कांग्रेस के चौधरी ब्रह्मप्रकाश बने। वे दिग्गज नेता थे। चौधरी साहब 1952 से 1955 तक मुख्यमंत्री रहे। 1956 में दिल्ली विधानसभा को भंग कर इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। 1966 में दिल्ली को एक महानगर पालिका का रूप दे दिया गया। उस समय विधान सभा को मेट्रोपोलिटन काउंसिल और, मुख्यमंत्री के समकक्ष चुने हुए नेता को चीफ मेट्रोपोलिटन काउंसिलर का पदनाम दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को पुन: 1991 में संविधान में संशोधन करके इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। नए परिसीमन के तहत एक नई विधानसभा का गठन भी किया गया। दिल्ली विधानसभा की बात होते ही लोग 1993 में गठित विधानसभा को पहली विधानसभा मानते हैं। हालांकि यह सच नहीं है। सन 1952 से ही दिल्ली में मुख्यमंत्री और 1967 के बाद 1991 तक लगातार चीफ मेट्रोपोलिटन कौंसिलर (मुख्यमंत्री के समकक्ष) और पुन: 1991 के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री बनते आये हैं। मुझे याद है कि जब 1967 में दिल्ली में मेट्रोपोलिटन काउंसिल के चुनाव में भारतीय जनसंघ की शानदार विजय हुई थी तब विजय कुमार मल्होत्रा चीफ मेट्रोपोलिटन काउंसिलर और लालकृष्ण आडवानी स्पीकर बने थे । उस समय केंद्र में इंदिरा गाँधी की सरकार थी।

नरसिंह राव के साथ खुराना

वर्ष 1991 में 69वें संविधान संशोधन के अनुसार दिल्ली को 70 सदस्यों की एक विधानसभा दे दी गई जिसमें 12 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थीं। तो दिल्ली विधान सभा के लिए वर्ष 1993 में फिर चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बहुमत मिला। मदन लाल खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। तब केन्द्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी,जिसके प्रधानमंत्री पी.वी.नरसिंह राव थे। तब से लेकर वर्ष 2014 तक दिल्ली में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार सामान्य ढंग से मिल-जुलकर ही काम कर रहे थे। आपस में कोई अनावश्यक तकरार नहीं था । यहां का विकास हो रहा था। न कभी यह मसला ही उभरकर आया कि केन्द्र और राज्य में किन दलोंकी सरकारें हैं। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थीं, तब वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर दिल्ली का विकास कर रही थीं। कहीं कोई विवाद ही नहीं था।

OFFICE OF THE CHIEF SECRETARY, DELHI

Yesterday, i.e. on 19.2.2018, I was informed on telephone around 8.45 p.m. by Advisor to Chief Minister Shri V.K. Jain that I have to reach CM's Residence at 12.00 midnight to discuss with Chief Minister and Deputy Chief Minister the issue of difficulty in release of certain TV Advertisements relating to completion of three years of current Government in Delhi. I suggested that meeting could be held on 20.02.2018 in the morning. However, it was informed by Advisor to CM at 9.00 p.m. and again at around 10.00 p.m. that the meeting has been scheduled by CM at 12 midnight. Prior to this message from Advisor to CM, the Dy. CM had also called me at around 6:55 p.m. and had informed that if the matter of release of TV Advertisement is not resolved by the evening, I should reach CM Residence at 12.00 midnight to discuss the issue. I had already explained to Dy. CM earlier that any advertisement to be released should not be in contravention of Supreme Court guidelines.

2. Advisor to CM again called me around 11.20 p.m. to confirm that I had left for CM's residence for the meeting. Thereafter, I left my residence in my official car and driver along with my PSO and reached CM Residence at midnight.

3. On arrival at CM's Residence, I met Shri V.K. Jain, Advisor to CM and thereafter both of us were taken to the front room where Chief Minister (Shri Arvind Kejriwal) and Deputy Chief Minister (Shri Manish Sisodia) and around 11 MLAs / persons were present. CM told me that persons present in the room were MLAs and they had come to ask him about Government's publicity programme on completion of three years. One of the MLAs firmly shut the door of the room. I was made to sit in between Shri Amanatullah Khan and another person/ MLA on a 3 seater sofa. CM directed me to answer the MLAs and explain the reasons for delay in release of the TV Campaign. I explained to them that the officers were bound by guidelines laid down by Hon'ble Supreme Court and any advertisement to be released must be in consonance with the said guidelines.

4. The MLAs started shouting at me and abused me while blaming me and the bureaucracy for not doing enough for publicity of the Government. One MLA, whom I can identify, threatened that I will be confined in the room for the entire night unless I agree to release TV campaign. A threat was made that I will be implicated in false cases including under the SC/ST Act. The MLAs whom I can identify became more aggressive and abusive extending threat to my life. Then suddenly Shri Amanatullah Khan, MLA and the person / MLA on my left side, whom I can identify, without any provocation from my side, started hitting and assaulting me and hit several blows with fists on my head and temple. My spectacles fell on the ground. I was in a state of shock. With difficulty I was able to leave the room and get into my official car and leave CM residence. At no stage did I retaliate or provoke any person in the room despite confinement, criminal intimidation by extending threat to my life, and assault by several MLAs while I was discharging my official duties.

5. I request you to take action as per law as the assault was premeditated and in conspiracy of all present with intention to criminally intimidate, cause hurt with motive to deter me from discharge of my lawful duty and compel me to follow unlawful directions. None of the persons present in the room made any effort to save me.

(Anshu Prakash)
Chief Secretary
20.02.2018

DCP (North)

सारे काम आपसी बातचीत से हल हो रहे थे।

'आप' आई- अराजकता लाई

पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के सत्तासीन होते ही अराजकता और अव्यवस्था फैलने लगी। और हद तो तब हो गई जब दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की मुख्यमंत्री ने अपने निजी सहायक द्वारा सरकारी आवास पर मध्य रात्रि में बुलवाकर गुंडे किस्म के हिस्ट्रीशीटर विधायकों द्वारा लात- घूँसों से पिटाई करवा दी। ऐसा शर्मनाक वाकया पहले कभी नहीं सुना था कि देशभर में कहीं भी किसी मुख्यमंत्री के आवास पर किसी वरिष्ठ आई.ए.एस अफसर को सत्तासीन दल के विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर बुलवाकर मध्य रात्रि में घूँसों और लातों से पिटवाया जाय। यह तो तानाशाह का स्वरुप माने जाने वाले मायावती, लालू, जयललिता या बंसीलाल तक ने नहीं किया। लोकतंत्र का इससे बड़ा मखौल क्या हो सकता है? विधानसभा का नेता की कार्यपालिका के मुखिया से न बने, यदि कार्यपालिका उसके शुद्ध राजनीतिक निर्णयों को न माने तो उसे मध्य रात्रि में बुलवा कर अपने सामने विधायकों से पिटवा दे। ऐसा तो विश्व भर के किसी भी लोकतंत्र में न कभी देखा न सुना! आखिर दिल्ली कहां जा रही है? क्या यह सब अब देश की राजधानी में घटित होगा? आखिर हम सारी दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं? पूरी दुनिया दिल्ली सरकार पर थू-थू कर रही है। मोटा-मोटी संकेत मिल चुके हैं कि घोर अराजक हो चुकी दिल्ली सरकार अब केन्द्र सरकार से लेकर सरकारी अफसरों से लड़ने के मूड में ही नहीं है, बल्कि; सीधे-सीधे मारपीट और गुंडई पर उतारू है। वो सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे तो बस शोर मचाना है, हल्ला करना है। यदि कोई सरकार ही गुंडई पर उतारू हो जाये तो उससे भी तो फिर वैसे ही निपटना होगा जैसे कि किसी गुंडे-मवाली से निपटा जाता है?

राष्ट्रपति शासन लगे

तो अब विकल्प ही क्या बचा हैं? विकल्प अब सिर्फ एक ही है कि दिल्ली सरकार को तुरंत बर्खास्त करके यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो। फिर जब स्थितियां अनुकूल हो जायें, शांति-व्यवस्था दुरुस्त हो जाये, तभी चुनाव करवा दिए जाएं नये विधान सभा के लिए। वैसे तो अभी इस सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल शेष है। यानी इस दौरान अब और कुछ होने वाला भी नहीं। हां, दावें और वादें खूब होंगे।अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अब एफएम रेडियो पर बड़े-बड़े वादे और प्रवचन (पर-वचन) देते हुए सुना जा सकता है क्योंकि, स्व-कार्य तो स्वीकार्य ही नहीं है किसी भी सही दिमाग के व्यक्ति को । इन दोनों को लगता है कि एफएम रेडियों पर जनता से मुखातिब होना ही जनता की सेवा है। इसीसे वे फिर से चुनाब जीत जायेंगे, ऐसा गलतफहमी पल रखा है उन्होंने।

केजरीवाल के खाने और दिखाने के दांत अलग-अलग हैं। केजरीवाल सरकार में एक के बादएक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के आरोप लगते आये हैं। इसी का नतीजा है किसरकार बनने के बाद से लेकर अब तक कईमंत्रियों को हटाना भी पड़ा। हालाँकि, केजरीवाल जी ने भरसक भ्रष्टाचारियों को बचाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। ज्यादातर विधायकों पर गुंडागर्दी, बलात्कार, अपहरण और रंगदारी बसूलने जैसे गंभीर आरोप हैं। केजरीवाल ने अपनेमंत्रियों के भ्रष्टाचार के मुद्दों को नकारने के भरसक प्रयास किए हैं, लेकिन मंत्री सत्येंद्र जैन की हवाला मामले में संलिप्तता के आरोप तथा उसके नजदीकी रिश्तेदार डॉ.निकुंज अग्रवाल को सरकारी नियुक्ति में पैसे वसूलने के मामले इतने गंभीर हैं कि उन्हे नजरअंदाज ही नहीं किया जा सकता। केजरीवाल का भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष तो दिसंबर2013 के मध्यमें समाप्त हो गया था।दिल्ली की जनता तो अब भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल के दोहरे मापदंड को खूब अच्छी तरह समझने लग गई है। वह यह भी बखूबी समझती है कि केजरीवाल पहले अपनेसाथियों की गलतियों का बचाव करते हैं, लेकिन, जब वह पूरी तरह फंस जाते हैं तो सफाई देने से कन्नी काट जाते हैं।

कतई लोकतांत्रिक नहीं

अंशु प्रकाश जैसे सज्जन और कर्मठ अफसर की सरे आम पिटाई की घटना के बाद अब किसी को यह संदेह नहीं होना चाहिए कि केजरीवाल एंड कंपनी किसी के साथ मिलकर लोकतांत्रिक ढंग से काम कर ही नहीं सकते। उनकी लोकतंत्र में आस्था है ही नहीं। वे नवोदित तानाशाह हैं। न उप राज्यपाल के साथ,ना केन्द्र सरकार के साथ और न ही नौकरशाहों के साथ। किसी के साथ इनका तालमेल बैठ ही नहीं सकता। क्योंकि इनकी नजरों में सब के सब खराब हैं, बस सिर्फ ये ही दूध के धुले हैं। ये नजीब जंग के साथ काम नहीं कर सके, अब अनिल बैजल से भी रोज लड़ते ही रहते हैं। अब मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को मारा, इससे पहले दिल्ली की महिला कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन को सरेआम भ्रष्ट बता डाला । गैमलिन पूर्वोत्तर राज्य से आती हैं। वो बेहद जुझारू अफसर हैं। केजरीवाल खुद तो कभी आई.ए.एस. नहीं बन सके। इस जनम में अब बन भी नहीं सकते। अगले जनम में ही कोशिश करनी होगी। लेकिन, अंशु प्रकाश जी यदि चुनाब लड़ जायें, तो वे जरूर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। केजरीवाल जी भी आई.ए.एस.बनने की तमन्ना लेकर ही परीक्षा में वैठे थे लेकिन, न तो आई.ए.एस. बने न आई.एफ.एस. न ही आई.पी.एस. चुने गये। चुने भी गए तो आयकर अधिकारी। आयकर अधिकारी के बारे में जितना कम कहा जाय उतना की ठीक है। क्या यह केजरीवाल की हीन भावना तो नहीं काम कर रही कि वे लगातार ईमानदार आई.ए.एस. और आई.पी. एस. अधिकारीयों को बेवजह बेइज्जत करते चले आ रहे है?

केजरीवाल ने सच में बहुत लोगों को निराश किया है अपने आचरण से भी व्यवहार से भी । वे पहली बार जब दिल्ली में सत्तासीन हुए तो उनके विरोधियों को भी एक उम्मीद तो बंधी ही थी कि वे एक वैकल्पिक राजनीति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।लेकिन, वे अन्ना के आन्दोलन से निकले हुए। रंगे सियारों की टोली के सरगना निकले। लेकिन, जब रंगा सियार पकड़ा जाता है तो उसका जनता क्या उपचार करती है यह भी जगजाहिर है ही। वही अब केजरीवाल जी उनके साथ होने वाला है ऐसा लगता है । उन्होंने वैकल्पिक राजनीतिकी बात करने वाले लोगों को एक उम्मीद जरूर दिखाई थी । पर वे तो नकारात्मक राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। केजरीवाल ने भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक तक पर सवालिया निशान खड़े किये। वे भूल गए कि देश अपने शूरवीरों को लेकर सियासत नहीं करता। बटाला कांड को फेक एनकाउंटर कहा उन्होंने करप्शन को चोट पहुंचाने के लिए उठाए गए नोटबंदी के कदम तक का पूरजोर विरोध किया। अब उनके सामने के सारे विकल्प खत्म हो चुके हैं। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसे फूटने में देर नहीं लगती।

(लेखक राज्य सभा सदस्य हैं)

बदलता प्रदेश-बढ़ता निवेश

● एस.पी. सिंह

उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश निवेशक समिट का आयोजन किया. इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया। इस समिट के जरिये उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में निवेश और रोज़गार बढ़ाने ध्यान देने के वादे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रही है। इस समिट में कई उद्योगपतियों ने निवेश की घोषणा की जैसे-

मुकेश अंबानी करेंगे 10,000 करोड़ का निवेश

मुकेश अम्बानी में ने उत्तर प्रदेश में 10 000 करोड़ का करोड़ का निवेश करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। इसके साथ ही डिजिटल क्रांति की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे दिसंबर 2018 तक प्रदेश के छोटे से छोटे गांव तक जियो नेटवर्क को पहुँचा देंगे।

कुमार मंगलम बिड़ला

कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरल व्यापार के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। यहां उद्योगों का विस्तार होता देखकर खुशी हो रही है। उन्होंने अगले पांच वर्षों में प्रदेश में 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की।

जी ग्रुप

एसेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने प्रदेश में पहले से काफी निवेश कर रखा है, उन्होंने कहा कि हमारे ग्रुप ने पिछली सरकार में 30,000 करोड़ रुपये का एमओयू किया था, लेकिन काम सिर्फ 3000 करोड़ रुपये का हुआ। जी ग्रुप आने वाले समय में यूपी में 18500 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश एक नए ही रूप में आ रहा है।

अडाणी समूह

अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी ने प्रदेश में 35,000 करोड़ का निवेश करने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे प्रदेश में रोजगार देने के लिए कृषि और उद्योग दोनों के ही क्षेत्र में निवेश करेंगे। इसके अलावा उन्होंने सड़क और मेट्रो के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार को हर संभव सहयोग देने का वादा किया। इसके साथ ही उन्होंने कौशल विकास केन्द्रों को खोलने की भी बात कही।

प्रदेश में बन रहा है निवेश का माहौल

अपनी बात रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में कानून राज कायम होने की वजह से निवेश बन रहा है। प्रदेश में किसानों के लिए सिंचाईं व्यवस्था सही होने से कृषि के क्षेत्र में भी संभावना बढ़ी है। प्रदेश में नये उद्योग को स्थापित करने के लिए भी काम किया जा रहा है। प्रदेश अब बीमारू राज्य से बाहर निकल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में क़ानून व्यवस्था का पालन किया जाएगा और क़ानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा जिससे राज्य में निवेशकों के लिए भयहीन माहौल का निर्माण किया जा सके।

मोदी ने की योगी सरकार की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की विशेषताओं की भी बात की। उन्होंने कहा कि जब परिवर्तन होता है तो सामने दिखने लगता है, यूपी में इतने व्यापक स्तर पर इन्वेस्टर्स समिट होना और इतने निवेशकों और उद्यमियों का उपस्थित होना अपने आप में अपने बहुत बड़ा परिवर्तन है।

क़ानून व्यवस्था की तारीफ़ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले की स्थितियां क्या थी यह यूपी के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। नकारात्मकता भरे माहौल से पॉजिटिविटी की तरफ लाना, प्रदेश में न्यू उत्तर प्रदेश की बुनियाद तैयार हो चुकी है।

प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की तारीफ करना नहीं भूले। उत्तर प्रदेश की विशेषताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा,लखनऊ के चिकन का काम मशहूर है तो मलिहाबाद के आम पूरे देश में प्रसिद्ध, भदोही की कालीन, फिरोजाबाद का कांच चमक दिखाकर ही रहता है। यहां आगरे का पेठा है तो कन्नौज का एक कवि, यहां सुबह बनारस है तो अवध की शाम में भी है। यहां ताजमहल और सारनाथ है या मथुरा और काशी भी है, यहां राम की लीला है तो कृष्ण की रास भी है। यहां गंगा है, यमुना है तो सरयूजी का आशीर्वाद भी है।

कन्ट्री पार्टनर के रूप में फिनलैण्ड, नीदरलैण्ड, जापान, चेक गणराज्य, थाईलैण्ड, स्लोवाकिया तथा मारीशस के प्रतिनिधि और उद्योगपतियों ने इस सम्मलेन में भाग लिया।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस सम्मलेन में उत्तर प्रदेश की आर्थिक क्षमता की प्रशंसा करते हुये कहा कि राज्य भारत की प्रगति में महत्तवपूर्ण भूमिका निभा सकता है और यह देश के विकास का इंजन बन सकता है। राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश निवेश सम्मेलन-2018 में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही व्यापारिक माहौल बनाकर यूपी को निवेशकों के लिए व्यवस्थित करने की दिशा में काम चल रहा है। राजनाथ सिंह ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी उत्तर प्रदेश अग्रणी प्रदेश हुआ करता था, लेकिन कुछ कारणों से पिछले कुछ सालों में यह पिछड़ गया लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि एक बार फिर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर होगा। अपराधों के प्रति मुख्यमंत्री की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है। राज्य सरकार ने संगठित अपराध के विरुद्ध जो नीति अपनाई है, यह व्यापार एवं उद्योग को प्रोत्साहित करने वाली है।

इसी के साथ डिफेन्स कोरिडोर बनाने की भी बात इस सम्मेलन में उभर कर आई। ■

बजट में लोकलुभावन प्रावधान देकर भाजपा शासित केंद्र सरकार ने जनता को लुभाने की कोशिश की है। क्या सिर्फ लोकलुभावन बजट जीत का आधार बन सकता है? राम मंदिर, 370, कश्मीर समस्या, गौ हत्या, गंगा स्वच्छता एवं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भाजपा ने कोई उल्लेखनीय काम अभी तक नहीं किए हैं। जो किये हैं वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। इसके बीच उत्तर प्रदेश वर्तमान में भाजपा की नयी प्रयोगशाला है और यहाँ का विकास मॉडल देश का मॉडल बनता दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गौ, गंगा और गाँव की बात कर रहे हैं। जिस तरह से निवेशक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उसके हिसाब से उनकी कथनी और करनी एक दिख रही है।

राष्ट्रनीति बनाम राजनीति

● **अमित त्यागी**

सारे प्रश्नों से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाजपा जिन मुद्दों पर सत्ता में आई थी उस पर उसने कितनी उपलब्धि हासिल की है ? जनता ने भाजपा को हिन्दुत्व के मुद्दों पर वोट किया था। भाजपा को कश्मीर समस्या के समाधान के लिये वोट किया गया था तो भाजपा ने महबूबा मुफ्ती के साथ वहाँ सरकार बना ली। कश्मीर में पत्थरबाजी बढ़ी तो पूरे देश का खून खौल गया। पत्थरबाज गिरफ्तार हुये तो जनता को मोदी सक्रिय लगे। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने जब पत्थर बाजों को छोड़ने का फरमान जारी किया तो जनता का खून खौल गया। राज्यसभा में बहुमत न होने के एवं 370 हटाने के जिस बहाने को भाजपा अब तक बनाती रही थी वह भी आगामी महीनो में खत्म होने जा रहा है। गंगा स्वच्छता में जितनी ज्यादा कागजी कार्यवाही हुयी है उतना काम जमीन पर नहीं हुआ है। सरकार चार साल में गंगा और उसकी सहायक नदियों में गिरने वाले रसायन और प्रदूषित पानी को नहीं रोक पायी है। यानि कि जिन जिन मुद्दों पर भाजपा ने जनता से वोट मांगे थे वह संपूर्णता तक नहीं पहुँचें हैं। भाजपा का हालांकि तर्क है कि अभी उसको कम समय मिला है और वह बेहतर परिणामों की तरफ बढ़ चुकी है।

गौ-हत्या पर केन्द्रीय कानून कब ?

भाजपा का प्रमुख मुद्दा गाय रही है। गौ संरक्षण के लिए भाजपा द्वारा कुछ काम तो हुये हैं किन्तु बीफ निर्यात में भारत पहले नंबर में भी उच्च पायदान पर पहुँच गया है। गौ हत्या कुछ राज्यों में प्रतिबंधित है तो कुछ राज्यों में खुले आम बीफ की छूट है। विपक्षी भाजपा पर लगातार

आरोप लगते हैं कि कुछ राज्यों में भाजपा के लिए गाय मम्मी है तो कुछ में यम्मी। गौ हत्या पर केन्द्रीय कानून की लगातार मांग के बाद भी भाजपा की प्रचंड बहुमत सरकार ने कुछ भी ठोस नहीं किया। चार साल में गौ-हत्या पर कोई केंद्रीय क़ानून नहीं बन पाया है। हालांकि, अलग राज्यों में अलग-अलग स्तर की रोक दशकों से लागू है। भारत के 29 में से 10 राज्य ऐसे हैं जहां गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस को काटने और उनका गोश्त खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 18 राज्यों में गौ-हत्या पर पूरी या आंशिक रोक है। भारत की 80 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी हिंदू है फिर भी 'बीफ़' का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले देशों में से भारत एक क्यों है ? हिन्दुत्व की सरकार भाजपा से यह प्रश्न जायज भी है और लाजमी भी।

इसकी व्यवहारिक वजह आपको बताता हूँ। 'बीफ़' का मांस बकरे, मुर्ग़े और मछली के गोश्त से सस्ता होता है। यह मुस्लिम, ईसाई, दलित और आदिवासी जनजातियों के ग़रीब तबक़ों में रोज़ के भोजन का हिस्सा है। भारत के ग्यारह राज्यों कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और दो केन्द्शासित राज्यों दिल्ली, चंडीगढ़ में बीफ पर पूर्ण प्रतिबंध है। आठ राज्यों जिनमे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और चार केंद्र शासित राज्यों दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ऐसे प्रदेश हैं जहां आंशिक प्रतिबंध लागू है। आंशिक प्रतिबंध का अर्थ है कि गाय और बछड़े की हत्या पर तो प्रतिबंध है लेकिन बैल, सांड और भैंस को काटने और खाने की इजाज़त है।

इन सबके बीच में एक महत्वपूर्ण प्रश्न संबन्धित सरकार के लिये यह है कि जिन प्रदेशों में बीफ पर पाबंदी है वहाँ क्यों गौवंश सुरक्षित नहीं है। जहां गौहत्या पर पाबंदी है वहाँ उसका पालन कड़ाई से क्यों नहीं होता है ? मुनाफे के इस खेल में कानून और उसका पालन करवाने वाले पैसों की चमक की चकाचौंध में खो जाते हैं जिसकी वजह से गौहत्याएँ नहीं रुकती हैं। यदि सजा की बात करें तो हरियाणा में एक लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है। महाराष्ट्र में गो-हत्या पर 10,000 रुपए का जुर्माना और पांच साल की जेल की सज़ा है। न तो यह तो सजा कम है न ही कानून कमजोर है। कहीं न कहीं मुनाफे के इस खेल में इच्छा शक्ति कमजोर है। योगी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़ खानों पर रोक लगी और इस कारोबार में काफी कमी आई है। पर जब तक गौ हत्या पर प्रतिबंध का कोई केन्द्रीय कानून नहीं बनता है तब तक सिर्फ गाय की बातें करने से हत्या नहीं रुकेगी।

भारत के 29 में से 10 राज्य ऐसे हैं जहां गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस को काटने और उनका गोश्त खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 18 राज्यों में गौ-हत्या पर पूरी या आंशिक रोक है।

पाकिस्तान में चुनाव- सीमा पर तनाव का कारण

मशहूर शायर राहत इंदोरी का एक शेर है। सरहद पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता करो चुनाव है क्या ॥

जुलाई 2018 में पाकिस्तान में चुनाव प्रस्तावित है और जिस तरह से रूपरेखा बन रही है पाकिस्तानी सेना अपनी पसंद की सरकार बनवाने के लिए भारतीय सीमा पर गोलाबारी तेजी के साथ करवा रही हैं इसके द्वारा वह पाकिस्तानी अवाम को यह संदेश देने में कामयाब रहेंगे कि उन्हें भारत से खतरा है। इस भारत विरोधी माहौल का फायदा उनको चुनाव में मिलेगा। पाकिस्तान की क्रिया पर सर्जीकल स्ट्राइक जैसी प्रतिक्रिया भारत की तरफ से भी हो सकती है ? क्योंकि भारत में भी चुनावी माहौल तैयार हो रहा है। नवंबर 2018 में भारत में भी चुनाव की रूपरेखा बन रही है। हालांकि, भारत और पाकिस्तान की सेनाओं में एक बुनियादी अंतर है। पाकिस्तान की सेना का वजूद आतंकवादियों को प्रश्रय देने पर टिका है जबकि भारत की सेना आत्मरक्षा के सिद्धान्त पर काम करती है।

वर्ल्ड डेवपमेंट रिपोर्ट-2013 के अनुसार भारत का सैन्य बजट 28.6 प्रतिशत, शिक्षा बजट 19.3 प्रतिशत एवं स्वास्थ्य बजट 4.2 प्रतिशत है। इसकी तुलना में पाकिस्तान का रक्षा बजट 36.5 प्रतिशत एवं शिक्षा बजट 3.5 प्रतिशत है। अब जिस देश में इतनी बड़ी राशि सेना के लिये खर्च की जाती हो वहाँ तरक्की की बात सोचना भी बेमानी हो जाता है। उस देश की सेना अगर सक्रिय नहीं होगी तो इस बजट को खर्च कहाँ करेगी। अगर बजट खर्च नहीं होगा तो अगले साल बजट में कटौती कर दी जाएगी। बस यही एक छोटी सी बात पाकिस्तान की सेना को आक्रामक बनाये रखती है। पाकिस्तान की सेना कभी भारत से उलझती है तो कभी खुद अपने ही हुक्मरानो से। कभी खुद भारत से लड़ाई के प्रपंच रचती है तो कभी आतंकवादियों को भेजकर अपनी आक्रामकता दिखाती है। चुनावों के समय पाकिस्तानी सेना और ज्यादा आक्रामक हो जाती है ताकि वह अपनी जनता में अपनी हीरो की छवि पेश कर सके। भारत से खतरा दिखाकर अपने पसंद के राजनैतिक दल को सत्ता पर काबिज करवा सकें। पाकिस्तान की सेना और नीति निर्धारक यही चाहते हैं कि उनके उकसावे की कार्यवाही पर भारत कोई कार्यवाही करे और पाकिस्तानी सेना इसको दुष्प्रचारित करके अपना हित साध सके। इसलिए पाकिस्तान हमेशा आक्रामक रहता है।

आक्रामकता और पराक्रम दो शब्द है। कमजोर सदा आक्रामक होता है और मजबूत पराक्रमी। आक्रामकता के द्वारा दूसरों को भयक्रांत किया जाता है। पराक्रम के द्वारा वर्चस्व स्थापित किया जाता है। सदियों से इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि आक्रामक जमींदोज हुये हैं और पराक्रमी ने विश्व पर अपनी विजय पताका फहराई है। भारत जिस पराक्रम के साथ आज वैश्विक परिदृश्य में उभरा है उसके अनुसार पाकिस्तान की कार्यवाहियों पर अब मोदी सरकार के सर्जिकल अटैक होते रहेंगे। गुंडे बदमाशों के साथ उसकी ही औकात पर उतर कर बात करना मूर्खतापूर्ण बात होती है। उसकी समय समय पर पिटाइ करते रहना ही समझदारी होती है।

संतों के आशीर्वाद की अपेक्षा मोदी सरकार न करे

भारत में हिन्दू संविधान होना चाहिए

-महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानन्द गिरि महाराज (जूना अखाड़ा)

चार साल पुरानी भाजपा सरकार हिन्दुत्व के मुद्दे पर सत्ता में आई थी। राम मंदिर, 370, कश्मीर समस्या, गंगा सफाई, गौ रक्षा जैसे विषय भाजपा के अजेंडे में शामिल थे। संत समाज भाजपा से हिन्दुत्व के अजेंडे पर खुलकर काम करने की मांग करता दिख रहा है। संत समाज का स्पष्ट कहना है कि अगर भाजपा राम मंदिर विषय पर कड़ा निर्णय नहीं करती है तो 2019 में वह संतों से किसी तरह की कोई अपेक्षा न रखे। संत समाज में सम्मानित अखाड़े जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानन्द गिरि जी से विस्तृत बात की विशिष्ट संपादक अमित त्यागी ने।

मोदी सरकार को चार साल हो गए हैं। गंगा एवं सहयोगी नदियों की सफाई के अभियान को आप कैसे देखते हैं?

विषय सिर्फ गंगा का नहीं है। प्राय: सभी नदियों का है। पूरे विश्व में जल का है। प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि जल घट रहा है। कई देशों ने अपने देश की नदियों को स्वच्छ किया है। चार वर्ष के कार्यकाल के दौरान बातें बहुत बड़ी बड़ी हुयी हैं किन्तु धरातल पर काम नहीं दिख रहा है। कोई भी नदी जब हम उसके प्राकृतिक मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे तो प्राकृतिक संरचना से वह भटक जाएगी। नदियों पर जो बड़े बड़े बांध हमने बनायें हैं उसकी वजह से कहीं न कहीं गंगा जैसी पवित्र नदी जिसकी पूरे विश्व में अलग मान्यता है वह अपने मौलिक स्वभाव से दूर हो गयी है। गंगा ही नहीं अन्य नदियां भी नालों में परिवर्तित हो गयी है। सरकार में नदियों के लिए संवेदना का नितांत अभाव है। केवल भाषण देने, सेमिनार करने और गंगा रक्षक दल बनाने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोगों को समिति बनाकर उनका पदाधिकारी बना दिया और वह लोग बड़े खुश हैं कि हम गंगा सेवा कर रहे हैं। इससे गंगा शुद्ध नहीं होगी।

स्वामी जी यह बताएं कि राम मंदिर भाजपा के प्रमुख अजेंडे में था। हिन्दुओं ने इसी वजह से भाजपा को वोट दिया था। न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण अभी तक मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया है ? क्या कहेंगे आप ?

मुस्लिम समाज अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दे पाया है कि यह भूमि कभी भी इस्लाम के लिए या इस्लाम की पूजा के लिए स्थानांतरित की गयी है। सारे के सारे साक्ष्य मिले हैं कि यह राम जन्मभूमि है। जब मुस्लिम लोगों ने कहा इसके क्या प्रमाण हैं? तो अदालत ने कहा कि खोद कर देखो और वहाँ मंदिर भी निकल आया।

अब तो केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकारें हैं? तो अब क्यों देर हो रही है ?

हम तो कह रहे हैं कि जो भारत का न्यायालय एक पिक्चर की पीआईएल को दो दिन में फाइनल कर देता है वह कैसे वर्षों से लंबित इस मामले की तेजी से सुनवाई नहीं करता है। हम चाहते हैं न्यायालय तेजी से इस पर सुनवाई करे और न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर तुरंत इस पर निर्णय दे। न्यायालय नहीं देता है तो हम मोदी सरकार से निवेदन करते हैं कि वह तेजी से इस पर कानून लाएँ। यदि मोदी कानून लाकर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर 2019 के लिए संतों का आशीर्वाद उन्हे मिलेगा। और नहीं करते हैं तो संतों के आशीर्वाद की अपेक्षा मोदी सरकार न करे।

लखनऊ में उर्वशी नाम की बालिका ने सूचना के अधिकार के तहत मांगा है कि जिस देश में हम रहते हैं उसे हम किस नाम से पुकारें?

ये हमने भी सुना है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसके इस पत्र को गृह मंत्रालय भेजा। गृह मंत्रालय ने संस्कृति विभाग को भेजा है। लेकिन आज तक उत्तर नहीं मिला। किसी भी देश के दो नाम नहीं ही सकते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं और भारत सरकार भी। वैधानिक रूप से किसी देश में ऐसा नहीं होता है। यह भारत का दुर्भाग्य है। इंडिया एक लैटिन शब्द है। और अंग्रेजों ने यह शब्द आज के अमेरिका के मूल नागरिकों को कहना शुरू किया। बाद में उन्हें रेड इंडियन कहा गया। लैटिन में इस शब्द का अर्थ है 'असभ्य, अनपढ़ एवं गंवार'। अमेरिका के ट्राईबल्स और हमें अंग्रेजों ने इंडियन कहा।

जैसे आप हिन्दुत्व की बात करते हैं और इस्लामीकरण पर आपके बयान आए हैं ?

दुर्भाग्य से इस देश का बंटवारा हुआ। मैं तो इस

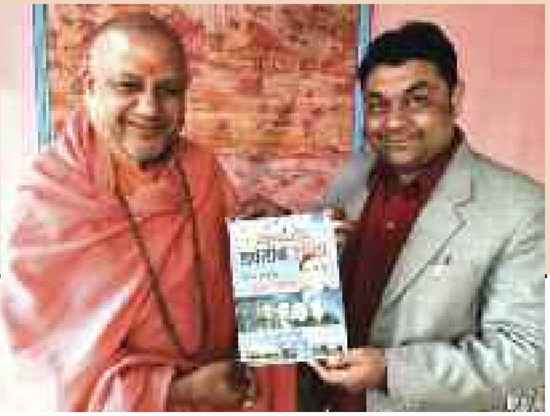

बँटवारे का पूरा का पूरा श्रेय महात्मा गांधी जी को दूंगा। हर चौराहे पर उनकी प्रतिमा खड़ी रहती है। वह सबमे झुके हुये हैं। अगर वह उस समय तन जाते तो अंग्रेज तो क्या उनके बाप की हिम्मत भी नहीं थी कि भारत को बाँट देते। अकेले महात्मा गांधी इतने समर्थ थे कि अगर वह डट कर खड़े हो जाते तो देश का बंटवारा नहीं होता। भारत का विभाजन कोई भौगोलिक विभाजन नहीं है। एतेहासिक विभाजन नहीं है। यह इस बात पर था कि दो भाई हिन्दू मुसलमान मिल कर नहीं रहते हैं तो दोनों के बीच बंटवारा कर दिया जाया। मुसलमानों को पाकिस्तान मिला। बांग्लादेश मिला। हिन्दुओं को क्या मिला? आखिर भारत में तो हिन्दू संविधान होना चाहिए था। जब विभाजन हिन्दू मुस्लिम के आधार पर था तो इसे भौगोलिक विभाजन क्यों बना दिया गया।

आपका कहना है तुष्टीकरण के तहत विभाजन किया गया? कश्मीर में अभी भी पत्थरबाजी हो रही है। आतंकवादियों को शरण दी जा रही है?

कश्मीर में इस समय निश्चित रूप से वहाँ का अलगाववादी तत्व बुरी तरह बिलबिलाया हुआ है। मैं पिछले दिनों कश्मीर गया था। पाकिस्तान अब हम पर सीधे हमले की गलती नहीं कर सकता है। वह हमें अंदर से घेरना चाहता है। आज अगर कश्मीर की समस्या का समाधान करना है तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिबद्धता है कि 370 को समाप्त करना है उसे तुरंत किया जाये। आज कश्मीरी चार रुपये किलो में चीनी ले रहा है। दो तीन रुपये में अच्छा वाला बासमती चावल, जो भारतीयों को नहीं मिलता है, वह ले रहा है। केंद्र का काफी पैसा इसमें खर्च होता है। वहाँ के उपद्रवी इसलिए ही ये सब करते हैं कि हम उपद्रव करते रहेंगे और केंद्र सरकार हमें यह सब देती रहेगी। जिस दिन केंद्र सरकार कश्मीर को यह सहायता देना बंद कर देगी, कश्मीर में पत्थरबाजी खुद बंद हो जाएगी।

कश्मीर की समस्या का क्या समाधान है? अब तो वहाँ हिन्दुत्व की भाजपा सरकार है। वह न तो पत्थरबाजों को नियंत्रित कर पा रही है और न ही सीमा पार आतंकवादियों को। अब तो महबूबा मुफ्ती ने पत्थरबाजों को भी छोड़ दिया है?

यह सिर्फ कश्मीर की समस्या नहीं है यह मौलिक समस्या है। आज तक देश की राष्ट्रियता तय नहीं हो पायी है। हमें बाहर के घुसपैठियों से ज्यादा खतरा घर में बैठे घुसपैठियों से हैं जो उनका समर्थन करते हैं। आंतंकवादियों और अलगाववादियों की सोच के पोषक लोग भारत के दुश्मन हैं। जैसे मणिशंकर अय्यर को भारत में भय लगता है उन्हे पाकिस्तान में प्रेम मिलता है। ऐसे नेताओं को तो उठा कर पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए।

भारत में बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है। क्या केंद्र सरकार को इस पर कोई केन्द्रीय कानून लाना चाहिए। दो बच्चों के कानून पर आप क्या कहेंगे?

जनसंख्या के मामले पर विश्व में आज हम चीन के बराबर हैं किन्तु चीन के पास हमसे चार गुना ज्यादा भूमि है। दुनिया में सिर्फ पाँच देश ऐसे हैं जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या इस्लाम का एक आक्रमण है। इस्लाम इस अजेंडे पर चल रहा है कि कैसे भारत को इस्लामिक देश बनाया जाये। लोकतन्त्र में वोट गिने जाते हैं जिसके जितने ज्यादा वोट होंगे वह उतना शक्तिशाली होता है। अगर भारत की संस्कृति और सभ्यता को बचाना है तो दो बच्चों का कठोर कानून जो सभी पर लागू हो तुरंत लागू कर देना चाहिए। सरकार को संविधान में तुरंत संशोधन करना चाहिए। इसमे कोई जाति और धर्म का विभेद नहीं होना चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में भारत नहीं रहेगा। इसके साथ पूरे भारत में समान नागरिक आचार संहिता तुरंत लागू होनी चाहिए।

आपके हिसाब से ज्यादा खतरा इस्लाम से हैं या ईसाई मिशनरियों से ?

दोनों से बराबर का खतरा हैं। दोनों की मानसिकता इनके जन्म से ही भारत विरोधी हैं। अगर कोई भारत माता की जय बोलता है तो उसे मार दिया जाता है। सेना पर पत्थर फेंके जाते हैं। जब एक मौलाना ने कहा कि हमें पाकिस्तान नहीं बनाना चाहिए था बल्कि भारत को ही मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहिए था। तब मुस्लिम समाज द्वारा ऐसे मौलाना का न विरोध हुआ और न ही आलोचना हुयी। इसका अर्थ है कि मुस्लिम समाज का उनको समर्थन है।

राम मंदिर पर सख्त फैसले चाहती जनभावना

राम मंदिर विवाद डेढ़ सौ साल पुराना है। सबसे पहले 1853 में हिंदुओं द्वारा आरोप लगाया गया कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसके बाद 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित भूमि की बैरी कैटिंग करवा दी। मसले का अस्थायी हल निकलते हुये तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिन्दुओं को अलग अलग प्रार्थना करने की इजाजत दे दी। इसके बाद 1885 का वर्ष वह वर्ष था जब पहली बार यह मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। यह वाद महंत रघुवर दास द्वारा दायर किया गया था। 1944 में शिया बोर्ड द्वारा इसका हस्तांतरण सुन्नी बोर्ड को कर दिया गया। 1944 का यह हस्तांतरण अब इस वाद का प्रमुख बिन्दु होने जा रहा है। 23 दिसम्बर 1949 को करीब 50 हिन्दुओ ने केन्द्रीय स्थल में रामलला की प्रतिमा स्थापित कर दी। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में रामलला की पूजा अर्चना करने की विशेष इजाजत मांगते हुये मूर्ति हटाने पर न्यायिक रोक की मांग की। 5 दिसम्बर 1950 को महंत परमहंस रामचन्द्र दास ने हिन्दू प्रार्थनाएँ जारी रखने और विवादित परिसर में मूर्ति को रखने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। इस तरह से कई चरणों से गुजरते हुये प्रारम्भिक सौ सालों में यह विवाद आगे बढ़ता चला गया। वर्तमान विवाद के एक बड़े एवं अहम मोड़ के रूप में एक फरवरी 1986 का दिन माना जाता है जिस दिन फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिन्दुओ को पूजा की इजाजत देते हुये ताले खोलने का आदेश दिया।

इस फैसले का राजनैतिक प्रभाव हुआ। नाराज मुस्लिम समाज ने विरोध स्वरूप बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी का गठन किया। ताले खोले गए तो जून 1989 में भाजपा ने मंदिर आंदोलन को गति प्रदान की तो उसी साल नवंबर में राजीव गांधी ने

शिक्षा व्यवस्था में होगा सुधार - अनुपमा जाइसवाल

(प्राथमिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार)

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस समय पूरे एक्शन में है। उत्तर प्रदेश का नकल माफिया इस सरकार ने तो दिया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जब विपक्ष में थे तब भी वह नकल माफिया पर सख्ती की बात कहते थे। जून 2015 में डाइलॉग इंडिया में प्रकाशित सुरेश खन्ना के साक्षात्कार में आपने कल्याण सिंह सरकार के समय नकल माफिया की सख्ती का जिक्र किया था जिसे ज्योति बसु द्वारा भी सराहा गया था। आज जब फिर से भाजपा की सरकार सत्ता में हैं तो कल्याण सिंह सरकार वाली तेी योगी सरकार में दुहराई जा रही है। परीक्षा केन्द्रों की निगरानी सीसीटीवी से की जा रही है। प्रशासनिक अमला मुस्तैद है। सभी जिलों में जिलाधिकारी अपने दल बल के साथ सुबह सुबह परीक्षा केन्द्रों में पहुँच जाते हैं। भारी सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी के कारण इस बार लाखों नकलची परीक्षार्थियों ने अपनी परीक्षा छोड़ दी है। मेधावी छात्र खुश हैं। नकल माफिया की कमर टूटना सिर्फ परीक्षा सुधार तक सीमित नहीं है। इसके बे मायने हैं। नकल से ़यादा नंबर लाने वाले छात्र बेसिक शिक्षा में मेरिट के आधार पर होने वाली भर्तियों में स्थान पा जाते हैं। मेधावी छात्र बाहर रह जाता है और ये नकलची व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं। व्यवस्था में स्थापित होने के बाद जब ये नकलची बच्चों को प ाने जाते हैं तो ज्ञान के अभाव में यह शिक्षा का स्तर गिरा देते हैं। वहाँ राजनीति शुरू कर देते हैं। देश का निर्माण करने वाली नयी पौध को तैयार करने के स्थान पर ये नकलची पौध को अधूरी, अपूर्ण शिक्षा देने लगते हैं। यानि कि पूरा का पूरा ढांचा सिर्फ नकल माफिया के द्वारा चरमरा जाता है। बेसिक शिक्षा से जुड़े कुछ विषयों पर डाइलॉग इंडिया के विशिष्ट संपादक अमित त्यागी की उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री श्रीमति अनुपमा जाइसवाल से संक्षिप्त बात हुयी।

बेसिक शिक्षा में सुधार की प्रक्रि या बहुत धीमे चल रही है?

जो व्यवस्था चरमराई हुयी है उसे सुधारने में समय लगता है। पहले से सुधार हुआ है। धीरे धीरे और भी सुधार होगा।

आपकी सरकार ने स्वेटर बांटने की योजना बनाई थी। पूरी ठंड बीतने के बाद भी स्वेटर नहीं बाँट सके आप लोग ?

मैंने प्रण लिया है जब तक बच्चों को स्वेटर नहीं बंट जाते हैं मैं भी स्वेटर नहीं पहनूँगी। बच्चों की चिंता है मुझे।

बेसिक शिक्षा में तबादले के लिए लोगों का जोर रहता है। पिछले कुछ सालों में भर्ती शिक्षक अपने चुनिन्दा जिलों में तबादले की मांग करते रहे हैं?

नयी तबादला नीति लाने जा रहे हैं। इसमे सभी नियम एवं प्रकि याओं का पालन किया जाएगा।

विवादित स्थल के पास शिलान्यास की इजाजत भी दे दी। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल आया और दिसम्बर 1992 को विवादित ढांचा ढहा दिया गया। इस एक घटना के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति चरमरा गयी और हिन्दू मुस्लिम के बीच बड़ी खाई को राजनैतिक दलों ने खूब भुनाया। एक भाजपा ने हिन्दू समाज को अपना वोट बैंक बना लिया तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह ने मुस्लिमों के रहनुमा के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। कई घटनाक्रमों से गुजरते हुये 30 सितंबर 2010 को उच्च न्यायालय ने अपना एतेहासिक फैसला सुनाया एवं इसके बाद 21 मार्च 2017 को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इसमे मध्यस्थता की पेशकश की।

भाजपा का उत्थान ही राम मंदिर के विषय पर हुआ था। अटल बिहारी के दौर में यही मुद्दा भाजपा को सत्ता तक पहुचाता था। अब जब लोकसभा के बाद राज्य सभा में भी पूर्ण बहुमत सरकार को मिलने जा रहा है तो जनभावना राम मंदिर निर्माण के पक्ष में आकर खड़ी हो गयी हैं। भाजपा का वोट बैंक चाहता है कि अब बहुत हो चुका है। चाहें न्यायालय से या केन्द्रीय कानून से हो। राम मंदिर का निर्माण हो ही जाना चाहिए।

भाजपा की प्रयोगशाला के रूप में उभरता उत्तर प्रदेश :

उत्तर प्रदेश मॉडल अब भाजपा की नयी प्रयोगशाला है। गुजरात मॉडल के बाद शायद अब उत्तर प्रदेश भाजपा का नया मॉडल प्रदेश बनेगा। जिस उत्तर प्रदेश में माफिया, गुंडे कानून का मखौल बनाया करते थे वहाँ आजकल धड़ाधड़ एंकाउंटर हो रहे हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में डर भी है और मुख्यमंत्री का खौफ भी। यह एक ऐसा बड़ा बदलाव है जिसकी कल्पना एक साल पहले उत्तर प्रदेश में नहीं की जा सकती थी। मुख्यमंत्री जब स्वयं दीवाली के मौके पर अयोध्या में लाखों दीप जलाकर आए तो उनका हिन्दुत्व का अजेंडा साफ हो गया। जैसे ही उन्होंने अवैध बूचड़खाने बंद करवाएँ। उनका गौ हत्या रोकने का कथन करनी में बदल गया। नकल माफिया की कमर टूटी तो

प्रधानमंत्री की कौशल विकास की संकल्पना पूर्ण हुयी। मेरिट के आधार पर लगने वाली सरकारी नौकरियों में बेहतर मेधा पहुचने की नींव पड़ी। सरकारी विभागों में गुटखे खाने पर पाबंदी लगी तो कार्यालय साफ दिखने लगे। अधिकारी सुबह 9 बजे अपने ऑफिस में दिखने लगे। अपनी सरकार के एक साल होने के पहले ही उत्तर प्रदेश में निवेशक आने शुरू हो गए। पूरे देश के निवेशक उत्तर प्रदेश की इन्वेस्टर्स समिट में आए और एक लाख करोड़ से ज्यादा के नए निवेश का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस समिट में उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी इंवेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुये कहा कि इंवेस्टर्स समिट बहुत बड़ा परिवर्तन है। पिछले माहौल से अब उत्तर प्रदेश निकल चुका है। बदलाव दिख रहा है। यहां अब वो नींव तैयार हो चुकी है, जिस पर नए उत्तर प्रदेश की दीवार तैयार होगी। हमारे यहां पर कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी की कहावत है। यहां पर मलीहाबाद के आम प्रसिद्ध है तो मुरादाबाद के पीतल के बर्तन। फिरोजाबाद का कांच चमक दिखाता है तो आगरा का पेठा और कन्नौज का इत्र भी है। यहां आईआईटी कानपुर है तो बीएचयू भी है। पिछले साल कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अनमोल धरोहर बताया है। अगले साल होने वाला कुंभ मेला यूपी सरकार के लिए बड़ा मौका है। देश में दो डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है इनमें एक उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। ये कॉरिडोर बुंदेलखंड में आगरा-अलीगढ़-कानपुर-झांसी-चित्रकूट में बनेगा। इससे करीब ढाई लाख लोगों रोजगार मिलेगा। वहीं पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से काफी फायदा मिलेगा। इसके लिए 20000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आने वाले तीन सालों में 40 लाख रोजगार की बात कह रहे हैं। सुनने में यह आंकड़ा दिलचस्प लग रहा है। फिल्म टेलीविजन, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रानिक उत्पाद जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में निवेश आना एक नए उत्तर प्रदेश का स्वप्न दिखाने लगा है। योगी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनस पर खरी उतरती दिखने लगी है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के क्रम में वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्टकी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के पलायन को रोकने वाली साबित होगी। मुकेश अंबानी जियो के माध्यम से प्रदेश में दस हजार करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। अडानी ग्रुप 35 हजार करोड़ का निवेश करने जा रहा है। महिंद्रा ग्रुप बनारस में इलेक्ट्रिक वाहन की फैक्ट्री लगाने जा रहा है।अब उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड क्लास फूड एवं लोजिस्टिक पार्क, सोलर पावर स्टेशन, मेट्रो और यूनिवर्सिटी बनाने के लिये निवेशक आ चुके हैं। यह अब नए तरह का उत्तर प्रदेश है। यह भाजपा की नयी प्रयोगशाला है। लोकसभा चुनावों में यह प्रयोशाला और इस प्रयोगशाला का नया वैज्ञानिक(योगी आदित्यनाथ) बड़ा गुल खिलाने जा रहे हैं। ■

मौलिक भारत के चुनाव सुधार अभियान की सबसे बड़ी जीत

मौलिक भारत, लोक प्रहरी, एडीआर, इलेक्शन वाच व अश्वनी उपाध्याय ये ही गिने चुने नाम है जो देश मे चुनाव सुधारों के लिए संघर्षरत है। एडीआर के प्रयासों से उम्मीदवारों के लिए चुनाव में शपथपत्रों का भरना अनिवार्य हुआ था । मौलिक भारत के नीरज सक्सेना व अनुज अग्रवाल ने शपथपत्रों में दी सूचनाओं को चुनोती देने के मुद्दे को जन आंदोलन बनाया व मौलिक भारत के प्रयासों से ही चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आयोग को सांसदों व विधायकों के शपथ पत्र में वर्णित संपत्ति की जांच के आदेश दिए। जांच में संदिग्घ पाए गए इन जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग लोक प्रहरी ने उच्चतम न्यायालय से की जिसमें मौलिक भारत ने उच्चतम न्यायालय को शपथपत्रों की जांच की स्थायी व्यवस्था बनाने की मांग की थी, इस पत्र को न्यायालय ने लेटर पिटीशन के रूप में स्वीकार कर लिया था। अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर कोर्ट दागी जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के आदेश पहले ही दे चुकी है जो अप्रैल 2018 से शुरू होने जा रहे हैं। सभी के संयुक्त प्रयासों का ही नतीजा है जो उच्चतम न्यायालय ने कल यह आदेश दिया कि चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को अपनी व परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति के स्रोत भी बताने होंगे व सरकार को आदेश दिया कि चुनाव लड़ने व जीतने वालों के शपथपत्रों की जांच के लिए स्थायी व्यवस्था करे। जनहित व लोकतंत्र की दिशा में यह अब तक कि सबसे बड़ी जीत है।

● विनय झा

राफेल युद्धक विमान : तथाकथित स्कैम सच्चाई और तर्क

हाल ही में फ्रांस से खरीदे जाने वाले लड़ाकू विमान राफेल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर विपक्षी नेता राहुल गाँधी द्वारा मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लेकिन चूँकि भ्रष्टाचार के मामले में काँग्रेस की साख इतनी बेहतरीन है कि अब राहुल गाँधी के आरोपों पर कुछ कहना बेकार ही है। परन्तु जनता के बीच गलत सन्देश और दुष्प्रचार की पहुँच न हो। सही बात तथ्यों और तर्कों के साथ पहुँचे इसलिए यह लेख प्रस्तुत है। इसमें बिन्दुवार तथाकथित राफेल विमान घोटाले के बारे में बताया गया है।

राफेल डील में खर्च बढ़ा है, जिसके कारण स्पष्ट कर रहा हूँ। पहला कारण है राफेल में अतिरिक्त अत्याधुनिक उपकरण भी अब सम्मिलित किये गए हैं जो पहले नहीं थे, किन्तु इनकी जानकारी भारत सरकार चाहे भी तो नहीं दे सकती है क्योंकि कांग्रेस के शासन में ही फ्रांस से 2008 में समझौता हुआ था कि फ्रांस द्वारा दिए गए क्लासिफाइड जानकारी को भारत गुप्त रखेगा। राफेल संसार के सर्वश्रेष्ठ युद्धक विमानों में से है और इसके कुछ लक्षण तो सर्वोत्तम हैं। 2011 में छ कम्पनियों ने टेंडर भरे थे जिनके बारे में वायुसेना की तकनीकी समिति ने जनवरी 2012 में रिपोर्ट दी थी कि भारत की जो आवश्यकता है उसके लिए राफेल सबसे उत्तम है। राफेल की वह तकनीकी श्रेष्ठता क्या है, और भारत की क्या आवश्यकता है। यह भारत सरकार किसी को नहीं बता सकती कांग्रेस के ही शासन काल में ही ऐसा करार फ्रांस ने करवा लिया था। यह फ्रांस का सर्वोत्तम युद्धक विमान है। फ्रांस अपनी सर्वोत्तम तकनीक को गुप्त रखना चाहता है, तो इसमें किसे दिक्कत है?

राफेल की एक खासियत बता रहा हूँ -- एक राफेल विमान तीन ब्रह्मोस मिसाइल को एकसाथ लेकर चार हजार किलोमीटर तक उड़ सकता है, दो हजार किमी जाना और दो हजार वापस आना। भारत के पास हाइड्रोजन बम भी है। एक अकेला पायलट बीजिंग, शंघाई और हांगकांग-कैण्टन इन तीन क्षेत्रों को हाइड्रोजन बम से युक्त तीन ब्रह्मोस मिसाइल द्वारा अकेले स्वाहा कर सकता है। विएतनाम से चीन पर ब्रह्मोस छोड़ने की तैयारी भारत ने पहले ही कर ली थी, अब पनडुब्बी से भी छोड़ने की तैयारी हो रही है। यह बात विएतनाम भी खुलकर स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वहां भी कानून है कि किसी अन्य देश को वहां सैन्य अड्डा स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी, किन्तु विएतनाम पर भी चीन आक्रमण कर चुका है और भारत पर भी, अतः इस मुद्दे पर विएतनाम भारत का सहयोगी है। जब कांग्रेस ने राफेल डील को टलवा दिया तो वायुसेना ने मनमोहन सरकार को बिना बताये रूस के सुखोई विमान पर ही ब्रह्मोस मिसाइल लगाने पर कार्य आरम्भ कर दिया जो अब पूरा हुआ है। सुखोई की रेंज राफेल से भी डेढ़ गुनी अधिक है, किन्तु राफेल तीन ब्रह्मोस एकसाथ छोड़ सकता है -- वह भी तीन अलग-अलग ठिकानों पर। रूस ने सुखोई विमान बनाने की तकनीक तो भारत को सौंप दी थी किन्तु सुखोई पर ब्रह्मोस जैसा भारी और सूक्ष्म तकनीक वाला क्रूज मिसाइल कैसे लगेगा यह तकनीक रूस नहीं दे रहा था (या शायद कांग्रेस शासन में भारत ने माँगा ही नहीं? कांग्रेस राज में तो राफेल भी नहीं लिया गया)।

ये बातें फ्रांस या भारत यदि बताये तो कई अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के उल्लंघन का विवाद खड़ा हो जाएगा। चीन तो जानबूझकर हंगामा कराकर भारत के विरुद्ध हर प्रकार के प्रतिबन्ध लगाना चाहेगा ही। अतः राहुल इस मुद्दे पर चीन का काम कर रहा है, भारत का नहीं। कांग्रेस कहती है कि राफेल डील कांग्रेस ने सस्ते में किया था। सस्ता या मँहगा बाद में देखते हैं, डील किया था तो जनवरी 2012 में वायुसेना द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद भी कांग्रेस ने खरीदा क्यों नहीं? हमारी सेना को पाकिस्तान के मुकाबले कमजोर क्यों करना चाहती थी? अब सेना को मजबूत किया जा रहा है तो कांग्रेस को खुजली क्यों हो रही है? राफेल डील में क्या-क्या है यह जानकर राहुल क्या करेगा? चीन और पाकिस्तान को बताएगा? कांग्रेस का यह प्रचार झूठा है कि रक्षामन्त्री ने राफेल डील के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया 7 रक्षामन्त्री ने तो राफेल

की कीमत भी बता दी है, जो कांग्रेस द्वारा निर्धारित कीमत से डेढ़ गुनी कम है।

किन्तु राफेल विमान की कीमत में अन्य खर्चों को जोड़कर राहुल गांधी झूठा प्रचार कर रहा है कि विमान की कीमत बढ़ गयी है. अन्य खर्चे हैं भारत में तकनीक ट्रान्सफर करना, विमान में नवीनतम तकनीक वाले अनेक आयुधों को जोड़ना, और 2011 के टेन्डर के काल से मँहगाई में वृद्धि। अतिरिक्त खर्चों को छोड़ दें तो विमान की कीमत घटी है, जिसका अर्थ यह है कि घूस पहले सम्मिलित था, अब नहीं। कुल खर्चे को केवल विमानों का खर्चा बताकर कांग्रेस और मीडिया देश को गुमराह कर रही थी, जिस कारण मुझे भी लगता था कि सेना के अधिकारियों ने घूस खाया होगा तभी मूल्य इतना बढ़ गया! किन्तु पूरे डील की जांच से स्पष्ट होता है कि घूस की गुंजाइश नहीं है। आरम्भ में जब मोदी सरकार ने डील किया था तब सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भी घूसखोरी के आरोप लगाए थे। लेकिन जब सप्रमाण खण्डन स्वामी जी को भेजा गया तो स्वामी ने बयान बदल लिया। मिस्र की वायुसेना को मोदी-सरकार द्वारा तय कीमत से 33प्रतिशत अधिक कीमत पर राफेल दिया गया, जिसका अर्थ यह हुआ कि मिस्र के घूसखोर को 33प्रतिशत घूस दिया गया तब जाकर मिस्र राफेल खरीदने के लिए राजी हुआ।

राफेल डील में तकनीकी आयुध स्थानान्तरण का भी करार हुआ है जिस कारण खर्च बढ़ा है (इसी बढ़े खर्च को कांग्रेस घोटाला कह रही है), भारत में ही भविष्य में राफेल बन सके इसका भी करार हुआ है। 2012 में फ्रांस सम्पूर्ण तकनीकी स्थानान्तरण के लिए तैयार था किन्तु उसका कहना था कि हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स के कारखाने में राफेल बनाने की तकनीकी क्षमता नहीं है, उसका उपाय करना होगा। इस पर भारत सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया और मामले को टाल दिया, हालाँकि वायुसेना कह रही थी कि मिग विमान बहुत पुराने पड़ चुके हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान के पास आधुनिक विमान हैं।

अतएव कांग्रेस ने जितने बिन्दु राफेल पर उठाये हैं वे सब के सब झूठे है। राहुल को पता है कि राफेल डील की गोपनीयता वाली बातें भारत सरकार कभी नहीं खोल सकती, अत: इस बहाने मोदी को घूसखोर कहकर गरियाना सम्भव है!! यदि मोदी सरकार झूठी है तो राहुल संसद में इस मुद्दे पर बहस से क्यों कतराता है? केवल मीडिया में ही हंगामा क्यों करता है? अत: राफेल डील में घोटाला तो हुआ है, लेकिन यह घोटाला मनमोहन सरकार ने किया था जिसे अब सुधारा गया है। इस घोटाले के दो हिस्से हैं

गौण हिस्सा यह है कि कांग्रेस ने अधिक कीमत पर समझौता किया था, 67प्रतिशत के बदले 100प्रतिशत को आज निर्मला सीतारमण डेढ़ गुना बता रही है जो उचित ही है (67 का डेढ़ गुना 100 है), और अपने पुराने लेख में मैंने मिस्र की तुलना में 33प्रतिशत बताया था जो सही ही था (67 और 100 में 33 का अन्तर)। मिस्र द्वारा राफेल की खरीद में घूस की जो रकम दी गयी वही रकम कांग्रेस ने भी माँगी, क्योंकि इन्दिरा गांधी ने ही कह दिया था कि भ्रष्टाचार एक ग्लोबल फेनोमेनन है। अत: कांग्रेस को ग्लोबल रेट वाला घूस चाहिए! राजीव गांधी ने रेट घटाकर बोफोर्स में केवल 3प्रतिशत पर ला दिया, जिसे सोनिया राज में सुधारकर 33प्रतिशत

तक पंहुचाया गया। किन्तु इससे भी कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है इस घोटाले का दूसरा हिस्सा। इतना अधिक घूस देने के लिए फ्रांस की कम्पनी तैयार थी फिर भी कांग्रेस ने निर्णय टाल दिया जबकि वायुसेना के सारे विमान पुराने पड़ गए थे और नए विमान के लिए वायुसेना मांग कर रही थी, आये दिन पुराने युद्धक विमानों की दुर्घटनाएं हो रही थीं। स्पष्ट है कि भारत राफेल खरीदे इसके लिए फ्रेंच कम्पनी जितना घूस दे रही थी उससे बहुत अधिक घूस राफेल नहीं खरीदने के लिए कोई अन्य देश दे रहा था! पप्पू के मित्र देश कौन हैं यह आप लोग जानते ही हैं - चीन और पाकिस्तान, जिन्होंने स्विस बैंकों के कालेधन को अपने यहाँ शरण देकर इस पवित्र परिवार को बचाने में सहायता की। अभी गुलाम नबी आजाद ने संसद में गर्जना की है कि कांग्रेस राज की तुलना में पाकिस्तानी गोलाबारी बढ़ी है जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस राज बेहतर था! पाकिस्तान से यही सहायता माँगने तो मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान भेजा गया था ताकि गुलाम नबी गर्जना कर सकें!

यद्यपि भारत के वैज्ञानिकों ने सुखोई पर ब्रह्मोस लगाकर सफल परीक्षण कर लिया है और सुखोई की रेंज राफेल से डेढ़ गुनी अधिक है, आज भी ब्रह्मोस के लिए सुखोई से बहुत श्रेष्ठ राफेल ही है। इस मामले में और अनेक अन्य अतिरिक्त गुणों के कारण राफेल संसार का सर्वश्रेष्ठ विमान है यह भारतीय वायुसेना के तकनीकी कमिटी की रिपोर्ट है। ब्रह्मोस जैसा द्रुतगामी क्रूज मिसाइल अमरीका और चीन के पास भी नहीं है, समुद्रतल से केवल तीन मीटर की ऊँचाई पर यह उड़ सकता है! कल्पना कर सकते हैं कि कलाम साहब की टोली ने इतने तेज मिसाइल को राडार से बचाने के लिए इतनी कम ऊँचाई पर उड़ाने में कितनी सूक्ष्म और त्रुटिहीन नैनो तकनीक का प्रयोग किया होगा! ऐसे मिसाइल को लक्ष्य तक सही सलामत पँहुचाने के लिए किस प्रकार का अत्याधुनिक विमान चाहिए यह कल्पना करना कठिन नहीं है। वैसा विमान देने के लिए केवल फ्रांस तैयार है, इसमें राहुल और उसकी माँ बाधक रही है।

राफेल के बारे में भारत और फ्रांस की सरकारें किन कारणों से गोपनीयता की जिद कर रहे हैं यह जानना चाहते हैं? राहुल गांधी जो जानना चाहते हैं, वह अत्यन्त घातक देशविरोधी और निन्दनीय है। टाइम्स ऑफ इण्डिया के समाचार के अनुसार जनवरी 2012 में जब राफेल डील हुआ था तब 126 राफेल खरीदने की बात 526 करोड़ रूपये प्रति विमान में तय हुई थी, जिनमें से केवल 18 विमान फ्रांस से खरीदे जाते और शेष 108 विमान भारत में बनाए जाते। नरेन्द्र मोदी ने जो डील किया है उसके अनुसार 36 राफेल फ्रांस से खरीदे जायेंगे जिनकी कीमत (मँहगाई) के कारण अब 710 करोड़ रूपये प्रति विमान हो गयी है, किन्तु भारत 1640 करोड़ रूपये देने के लिए तैयार हो गया है। पाँच वर्षों में 35प्रतिशत की मूल्यवृद्धि तो समझ में आ सकती है, यद्यपि इसमें भी एक बहुत बड़ा पेंच है जिसका खुलासा इस लेख के अन्त में है। किन्तु अब यदि कीमत

710 करोड़ है तो 1640 करोड़ क्यों दिया जा रहा है। यही राहुल गांधी का मूल प्रश्न है जिसे घोटाला कहकर वे संसद को उड़ा देना चाहते हैं। टाइम्स ऑफ इण्डिया की खबर के अनुसार नए समझौते के अनुसार विमान 710 करोड़ की दर से ही लिया जा रहा है, अतिरिक्त खर्च के निम्न कारण हैं –

(1) deadly weapons package (घातक हथियारों से लैस विमान दिए जायेंगे, उन हथियारों का विस्तृत ब्यौरा भारत सरकार राहुल गांधी को क्यों दे? वह तो चीन को बता देगा! राफेल विमान में अधिकतम सम्भव कौन-कौन से घातक हथियार लगाए जा सकते हैं और किस प्रकार फिट होंगे यह हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स जानता है या राफेल बनाने वाले फ्रेंच कम्पनी ? फ्रांस हमारी सहायता कर रहा है तो हम कीमत भी नहीं देंगे?)।

(2) all spares (अतिरिक्त स्पेयर पार्ट-पुर्जे भी पहले से ही दिए जायेंगे ताकि युद्ध छिड़ने पर पुर्जों के कारण विमान रखे न रह जाएँ),

(3) costs for |z per cent fleet availability (हमेशा कम से कम 75प्रतिशत अर्थात 36 में से 27 विमान युद्ध हेतु पूर्ण तैयार रहें इसकी गारन्टी का खर्च; ऐसी गारन्टी मुफ्त में नहीं आती, चौबीसों घंटे हर विमान की पूरी देखरेख और मरम्मत आदि करनी पड़ती है।)

(4) performance-based logistics support for five years (पाँच वर्षों तक भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहारिक उड़ानों के लिए आवश्यक समस्त संरचनात्मक, तकनीकी, संचार, आदि मुहैय्या कराने का खर्च, ताकि 36 विमानों का पूरा बेड़ा वास्तविक युद्ध में भाग ले सके। logistics support का अर्थ होता है ≈– detailed organization and implementation of a comple& operation, the activity of organizing the movement, equipment, and accommodation of troops, आदि, अर्थात फ्रांस वास्तविक युद्ध हेतु सहायता दे रहा है, केवल सामान नहीं बेच रहा है।)

(5) other things – (अन्य बातें जिनका खुलासा नहीं किया गया , उन अन्य बातों में सबसे महत्वपूर्ण है हर विमान में तीन ब्रह्मोस मिसाइल फिट करना जो हाइड्रोजन बम से लैस रहेंगे)।

युद्ध की स्थिति में फ्रांस भारत को क्या दे रहा है इसका विस्तृत ब्यौरा राहुल गांधी लेकर क्या करेगा? 710 करोड़ में 930 करोड़ जोड़कर 1640 करोड़ में एक विमान लिया जा रहा है, राहुल गांधी इस 930 करोड़ रूपये का एक-एक मद में ब्यौरा चाहते हैं, ताकि वे किन घातक हथियारों और किस प्रकार के logistics support के खर्चे हैं और युद्ध छिड़ने पर कितने समय तक का स्पेयर पार्ट मिल रहा है यह गोपनीय जानकारी चीन को दी जा सके। तो घोटाला कौन कर रहा है? बिना अतिरिक्त सहायता के 526 करोड़ प्रति विमान का ब्यौरा भी झूठा है। पूरा डील 54000 करोड़ रूपये में कांग्रेस ने किया था – सेक्यूलर अखबार The Hindu अखबार की रिपोर्ट में इसका भी उल्लेख है। किन्तु बाद में जब डील कांग्रेस ने पूरा किया तब प्रति विमान 526 करोड़ रूपये में तय हुआ, अर्थात 126 विमानों की कीमत 54000 करोड़ से बढ़ाकर 66276 करोड़ रूपये देने के लिए कांग्रेस सरकार तैयार हुई थी।12276 करोड़ रूपये अतिरिक्त क्यों दिये जा रहे थे इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह घोटाला नहीं था? कांग्रेस सरकार के समय 526 करोड़ रूपये में डील हुई जबकि मोदी सरकार ने अन्य खर्चों को छोड़कर 710 करोड़ रूपये प्रति विमान की दर से डील की – इसका अर्थ लगता है कि मूल्य में 35त्न वृद्धि हुई। किन्तु यह सच्चाई नहीं है। 526 करोड़ में से 97 करोड़ प्रति विमान घूस था, तब तो वास्तविक मूल्यवृद्धि 429 करोड़ से बढ़कर 710 करोड़ हुई? 65.17प्रतिशत मूल्यवृद्धि? ये सेक्यूलर अखबार इस तथ्य को छुपाते हैं कि पुरानी डील में केवल 18, अर्थात 14त्न विमान ही फ्रांस में बनते और 86प्रतिशत विमान तकनीक-ट्रांसफर के बाद भारत में बनते, जबकि नयी डील के अनुसार सारे विमान फ्रांस से बने-बनाए लिए जायेंगे (क्योंकि चीन और पाकिस्तान से खतरे को देखते हुए भारत में बनाने की बात अभी व्यवहारिक नहीं है, उसमें बहुत समय लग जाएगा, उसकी बाद में सोची जायेगी)। फ्रांस से बने-बनाए लेंगे तो मँहगा पडेगा ही, फ्रांस में मजदूरी अधिक लगती है यह राहुल और प्रेस्टिट्यूटो के सिवा सबको पता है। जनवरी 2012 में भी फ्रांस में बने विमान की कीमत लगभग सात सौ करोड़ रूपये से कुछ ही कम थी, जबकि भारत में बनाने पर केवल चार सौ करोड़ ही खर्च होते, शेष 97 करोड़ घूस के थे, कुल 12276 करोड़ रूपये का मामूली घूस!

The Hindu अखबार की उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार भी राफेल में बहुत सी खूबियाँ हैं –

- air supremacy
- interdiction
- aerial reconnaissance
- ground support
- in-depth strike
- anti-ship strike
- nuclear deterrence

अन्तिम बिन्दु ध्यान देने योग्य है – इसका अर्थ यह है कि चीन जैसा शक्तिशाली शत्रुदेश आप पर नाभिकीय आक्रमण नहीं कर सकेगा, इसे राफेल सुनिश्चित करता है (https://www.dassault-aviation.com/)! इसका विस्तार से खुलासा करना देशहित में नहीं है। राफेल में कौन सी खूबियाँ हैं इसे विस्तार से देखना चाहें, तो उस कम्पनी के वेबसाइट पर जाएँ, इस वेबपेज पर अनेक लिंक भी हैं जिन्हें क्लिक करने पर सूक्ष्म विवरण मिलेंगे। इस वेबसाइट पर राफेल के बारे में आम लोगों के लायक पर्याप्त जानकारी है (जिन्हें यहाँ मैं दुहराना नहीं चाहता) जो सिद्ध करती है कि राफेल भारत को अजेय बनाने की क्षमता रखता है, बशर्ते भारत के पास पहले से हाइड्रोजन बम हो, ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल हों, बहादुर सैनिक तथा कुशल नेता हों। अभी भारत में ये सारे गुण हैं। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना में राफेल कार्य करना आरम्भ कर दे उससे पहले ही भारत का कुछ बिगाड़ दे इसके प्रयास में चीन और पाकिस्तान (तथा उनके भारतीय मित्रगण) जीजान से जुट गए हैं। इस वेबसाइट पर जितनी जानकारी है, उससे अधिक जानकारी चाहिए तो किसी देश का मुखिया बनकर राफेल खरीदना पड़ेगा तभी उसकी कम्पनी Dassault ब्यौरा देगी, वरना कठोर प्राणायाम करना पडेगा। राहुल दोनों में अक्षम हैं। लेकिन चीन को ब्यौरा चाहिए, जिसके लिए राहुल छटपटा रहे हैं। ■

तपाशील जाति अदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि बिकास शिल्प केन्द्र

● के.के. मिश्रा

तपशील जाति अदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि बिकास शिल्प केन्द्र पश्चिम बंगाल में मानव कल्याण के क्षेत्र में एक सशक्त अग्रणी संस्थान हैं । पश्चिम बंगाल के लगभग अठारह जिलों में स्थापित अपने संपर्क कार्यालयों के माध्यम से यह संस्था लोक कल्याणकारी योजनाओं को मूर्तरुप प्रदान करने में लगी हैं,ताकि विकास के जो सपने लोगों की आखों में हैं वो जमीन पर उतर सके ।

जब तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा बीस सूत्री कार्यक्रम की नींव रखी गई तब भी यह एहसास था कि शायद सरकारी प्रशासनिक तंत्र एकमेव समाज के समग्र विकास के सपने को साकार नहीं कर सकता । पश्चिम बंगाल में लगभग 37 वर्षो पूर्व इस संस्थान की स्थापना हुई और तत्समय बंगाल के लब्धप्रतिष्ठ और स्वनामधन्य समाजसेवी श्रीमन्त अतुल कुमार चक्रबर्ती ने इस संस्थान के प्रादुर्भाव और उत्थान में अपनी महती भूमिका निभाई ।

भगवान अवधूत बाबा तारकेश्वरनाथ की पवित्र भूमि में उनकी कृपा के छत्रछाया तले दिनांक 14 जनवरी 2018 को पावन मकरसंक्रांति के पुण्य काल मे संस्थान ने हुगली के हरीपल लोकमंच के प्रांगण मे सुस्वागतम् कार्यक्रम का आयोजनकिया। समारोह की मुख्य अतिथि डा. ममता जसंघमिता, सम्माननीय सांसद, लोक सभा (बर्धमान) एवं अन्य समस्त प्रतिष्ठित आगंतुक अतिथियों द्वारा दीपप्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ। मंगलाचरण और आगत स्वागत के उपरांत मुख्य अतिथि महोदया ने अपने उद्बोधन मे संस्थान और सामाजिक परिवर्तन में उसके महती लक्ष्य को रेखांकित किया। संस्थान के सचिव श्री सोमेन कोलेजी की तारीफ करते हुउए उन्होने कहा कि पश्चिम बंगाल के 204 ब्लाकों में अपनी उपस्थिति के माध्यम से यह संस्थान सर्वजन हिताय ,सर्वजन सुखाय के लक्ष्य को लेकर अग्रसर हैं। इस संस्था के सभी समर्पित कार्यकर्त्ता भी परोपकार की भावना से वंचित,पीड़ित ,शोषित और दिनदुखियों के दुख को दूर करने के लिए अपना समस्त उत्सर्ग कर रहे है। जहां एक ओर त्याग की भावना प्रबल है वही इस संस्थान के सचिव के नेतृत्व में समस्त कार्यकर्ता सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढाओ , स्वच्छ भारत अभियान , निर्मल बांग्ला ,सेफ ड्राइव सेव लाइफ आदि अभियान जैसी अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार.-प्रसार और क्रियान्वयन में अपनी सार्थक भूमिका निभा रहे हैं। सस्था के सचिव श्रीमन सोमेन कोलेने संस्था के गौरवपूर्ण अतीत और उज्वल वर्तमान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भविष्य मे हमें गौरव के शिखर पर पहुंचना है । उन्होने संस्था से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त किया कि वे इस संस्था से सम्बद्ध होकर इसके विकास मे अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने अतीत में झांकते हुए यह बताया कि अक्टूबर 2012 में जब हरीपल लोक मंच के प्रांगण में कार्यक्र म आयोजित किया गया था तब से अब तक इस संस्था की विकास यात्रा अद्भुत रही है। सचिव महोदय ने संस्था की उपलब्धियो पर प्रकाश डालते हुए यह अवगत कराया कि संस्था गरीब किसानों के बीच उन्नत किस्म के बीच का नि:शुल्क वितरण कर रही है। उन्हें कृषि की उन्नत तकनीकी से परिचित कराया जा रहा है ताकि उनके जीवन में आर्थिक उन्नति के माध्यम से परिवर्तन लाया जा सके। संस्था से अपने 18 वर्षो के दीर्घकालीन जुड़ाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय जिन पौधों को उन्होंने लगाया उसमें से कुछ तो सुख गए लेकिन कुछ खिल गए ,कुछ पुष्पित और पल्लवित हुए। वे आज टीजेएपीएसकेबीएसके के बाग में अलग अलग रंग ,रुप और गंध बिखेर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सुप्रसिद्ध सिने स्टार जनाब विश्वजीत चटर्जी साहब ने कार्यक्रम की शोभा बढाई । कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति, नागर विमानन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य, प्रख्यात समाजसेवी एंव टीजेएपीएसकेबीएसके की राष्ट्रीय परामर्शी परिषद के सम्मानित सदस्य दिल्ली से पधारे श्रीमान अभिषेक गुप्ता ने कार्यक्रम में पधार कर इसकी शोभा बढाई । अपने संबोधन में उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय से मानव कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात का विशेष रुप से उल्लेख किया कि संस्था के सचिव श्री सोमेन कोले ने मानव कल्याण और दिन द:ुखियों की सेवा का जो अभियान प्रारंभ किया है, उससे जुड़ना मेरे लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर दिल्ली से पधारे संस्था के राष्ट्रीय परिषद से सदस्य एंव सुविख्यात समाजसेवी श्री उमाकान्त राय जी ने सचिव श्री सोमेन कोले जी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि जिस प्रकार एकनिष्ठ समर्पण से वे संस्था का कार्य करते हैं उसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं।

कार्यक्रम के सफल संचालन के सूत्रधार श्री रामानन्द शर्मा जी ने आरंभ से अंत तक अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। अंततोगत्वआ वंदे मातरम्गान से उत्सव का विसर्जन हुआ।

लेखक *अपर निदेशक , राज्य सभा सचिवालय हैं*

पहाड़ों में गूंजा सूफीवाद का संदेश

● रफी खान

भारत देश दुनिया का वह एकलौता विशाल देश है जो विभिन्न भाषाओं, जातीय, वर्ग, धर्म में बंटे होने के बाबजूद आज भी दुनिया में इसकी विविधता में एकता के तोर पर पहचान कायम है, परन्तु समय समय पर जिस तरह से कुछ शरारती व कट्टरपंथियों द्वारा देश की विविधता और एकता में दरार बनाने का प्रयास किया जाता रहा हे और किया जा रहा है, उसको जल्द भरने की आवश्यकता है इसको देखते हुए अगर देश में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसी चीज की हे तो वह है कट्टरता को समाप्त कर एकता और अखंडता के मुरझाते बरगद को सींचने की ! जिस तरह से आज भारत देश के लोग धर्म और मजहब की गहरी खाई में लगातार बंटते चले जा रहें उसको देखते हुए आज फिर से जरुरत है एक ऐसा तराना सुनाने वालो किि जो मजहबों-धर्म से ऊपर उठकर लोग उसकी झंकार में मदमस्त होकर इंसानियत का चोला धारण कर सके !

हमारे देश के संत-सूफी और कवियों ने भी जात-पांत, धर्म और सम्प्रदाय से ऊपर उठकर, प्रेम के धागे से लोगों के दिलों को जोड़ने का काम बहुत ख़ूबसूरती से किया। यही नहीं हमारे ऋषियों, संतों और सूफियो ने अपने उपदेश,कलाम और शायरी से इंसानियत की भावना को पूरी दुनिया में पहुँचाने का नेक काम हमेशा किया। शायद इसी लिए इस्लाम के सूफीयत और हिंदुस्तान की संतवाणी दोनों का तसव्वुर एक ही है। दोनों आज से पहले कभी मज़हब में नहीं बंटे और यूनीवर्सल बने रहे। दोनों ने अपना रिश्ता अल्लाह से और ईश्वर से जोड़ा। सभी को एक जैसा मानने वाले इन सूफियों और संतों ने सभी इंसानों के लिए इंसानियत की ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी अमिट है।

सुफिज्म ने पूरी दुनिया को इश्को मुहब्बत का पैगाम दिया और अपने सूफ़ियाना कलामों के ज़रिए लोगों के दिलो में देशभक्ति के साथ साथ धर्म-मजहब का ऐसा तराना सुनाया की दुनिया में इशक और मोहब्बत को न भी समझने वालों के दिलों में मोहब्बत की झनकार पैदा हो गई। लोगों ने ईश्वर और ख़ुदा के साथ अपना ऐसा पाक और रुहानी रिश्ता जोड़ा कि उन्हें अपने दिल के आईने में सारी दुनिया का अक्स नज़र आने लगा।

पर आज यह किया हो रहा हे जैसे सुफिज्म को ग्रहण सा लग गया हे ! जरुरत है आज एकबार फिर से सुफिज्म को समझने की और उसको ऊपर लाने की इससे पहले हमें सूफीवाद को समझना होगा ! सूफी शब्द के मायने पवित्र (पाक) के हैं जिसको हिंदुस्तान में तेजी से प्रचार-प्रसार का श्रेय सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती (गरीब नवाज) को जाता हे यही नहीं सूफीवाद की ख़ुशबू पंजाब की

संतवाणी में भी नुमायां है। गुरुनानक से लेकर बुल्ले शाह, वारिस पाक,बाबा फरीद, देवमणि पांडेय और रामानंद,मालिक मोहम्मद जायसी सहित कई और नाम ऐसे हे जिन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में सूफिज्म को हिंदुस्तान में बढ़ावा देते हुए अपने सूफी कलाम से मुहब्बत की ऐसी बारिश की जिसमें हमारे देश का पूरा खित्ता तरबतर हो गया !

इसी लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2016 के दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड सूफी फोरम में शिरकत करते हुए जहाँ सूफीवाद को बढ़ावा देने की वकालत की थी तो वही उन्होंने

प्रथम विश्व सूफी मंच को संबोधित करते हुए कहा, ''मानवता के लिए इस महत्वपूर्ण समय पर इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन होना दुनिया के लिए अहम है। जब हिंसा की काली परछाईं बड़ी होती जा रही है तो उस समय आप उम्मीद का नूर या रोशनी हैं। जब जवान की हंसी को बंदूकें खामोश कर रही हैं तो आपकी (सूफिज्म) आवाज मरहम है।'' सूफीवाद के संदेश को आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ''आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ टकराव नहीं है यह मानवता के मूल्यों और अमानवीयता की ताकतों के बीच संघर्ष है। इस संघर्ष को सिर्फ सैन्य, खुफिया या कूटनीतिक तरीकों से नहीं लड़ा जा सकता। हाँ सूफीवाद को बढ़ावा दिए जाने से इसका खात्मा किया जा सकता है।

यह भी याद रहे सूफिज्म को बढ़ावा देने वाले धर्मगुरुओं का एकमात्र उद्देश्य यही था की सादा जीवन बिताते हुए मानवता की सेवा होती रही और आम जनमानस को ऐसी राह प्रदान की जाये जिसपर चलकर वह अपने धर्म के साथ साथ इंसानियत को भी पहचान सके ! आध्यात्मिक गुरु यानी सूफी संत (औलियाओ) की अल्लाह या ईश्वर से हुई बातों की सूफी कलाम में झलक साफ नजर आती है, सूफिज्म एक तड़प का नाम है ईश्वर-अल्लाह ने हमारे अंदर जो रूह और दिल रखा है उसमें रूहानी तड़प पैदा कर ईश्वर की पहचान कराने की ताकत और लोगों में इंसानियत का जज्बा पैदा करने की सलाहयियत सिर्फ सूफीवाद में ही है, अतएव आज हमारे देश में फिर से जरूरत है बाबा नानक,बाबा फरिद और रामानंद जेसो की जो देश को एक माला में पिरों सके जिससे हमारा यह विशाल देश विश्व की सबसे विशाल शक्ति के रूप में विकसित होकर उभर सके ! ■

जान माल को लीलती हाइवे की 31 विसंगतियां

● रामस्वरूप रावतसरे

लो जयपुर दिल्ली हाइवे के 4 लेन से 6 लेन में परिवर्तित करने की परियोजना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा गुड़गाँव जयपुर हाई वे को आदर्श हाई वे घोषित करते हुए भारी भरकम बजट राशि स्वीकृत की गई थी। लेकिन हाई वे का निर्माण सम्बन्धी कार्य गलत हाथों में चले जाने और केंद्र सरकार तथा निर्माणकर्ता कम्पनी के मध्य हुए एग्रीमेन्ट की विसंगतियों के चलते यह परियोजना राष्ट्र के विकास में भयंकर बाधा बनी हुई है। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं, ट्रैफिक जाम, प्रदूषण व धरना प्रदर्शन आदि समस्याओं को लेकर आम जन जीवन को रोज जुझना पड़ता है इस बात को लेकर जीवन बचाओं आंदोलन'' के मुख्य संयोजक नित्येन्द्र मानव ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

याचिका में 2012 से लंबित चल रही इस परियोजना के तहत मानेसर, धारूहेड़ा, कोटपूतली, पावटा, शाहपुरा व मनोहरपुर में बाईपास सड़कों के निर्माण करवाना, प्रति सौ किलोमीटर की दूरी पर इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रेस्क्यू सेंटर्स खोलने, आवश्यकतानुसार फायरब्रिगेड एंबुलेंस क्रेन की सुविधा उपलब्ध करवाने, सभी टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज बनवाने, आवश्यकतानुसार फ्लाईओवर वीयूपी पीयूपी का निर्माण करवाने का अनुरोध किया गया है।

छः लेनीकरण संबंधी निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही निर्माण कम्पनी द्वारा छः लेन को लेकर वसूले जा रहे टोल टैक्स पर प्रतिबंध लगवाने, हाईवे एवं टोल प्लाजा पर आमजन वास्ते आवश्यकतानुसार सुविधा उपलब्ध करवाने, आवश्यकतानुसार फुट ओवर ब्रिजों का निर्माण करवाने, किलर पॉइंट्स को चिन्हित कर उनकी तकनीकी और प्रशासनिक विसंगतियों को दुरुस्त किये जाने, टोल प्लाजा पर बूथों की संख्या बढ़ाने, पार्किंग स्थलों का निर्माण करवाने, सभी कस्बों में हाई वे के मध्य रेलिंग लगवाने, वृक्षारोपण करवाने, प्रत्येक दो किलोमीटर की दूरी पर टेलीफोन बूथ लगवाने, पूर्व में संचालित नियंत्रण कक्षों एवं सहायता केंद्रों को पुनः शुरू करवाने सहित 31 तकनीकी एवं प्रशासनिक विसंगतियों को शामिल किया गया है।

सर्वे के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाओं के चलते प्रति वर्ष लगभग एक लाख चालीस हजार लोगों की अकाल मृत्यु होती है। भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं दिल्ली जयपुर हाईवे पर होना बताया जा रहा हैं । गुड़गाँव जयपुर छह लेनीकरण परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वार हजारों करोड़ खर्च किये जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देशवासियों को आये दिन सड़क दुर्घटनाओं और जाम का सामना करना पड़ता है।

नित्येन्द्र मानव के अनुसार हाईवे पर जहां फ्लाईओवर, वीयूपी, पीयूपी बनना नितांत आवश्यक था। वहां निर्माण कंपनी द्वारा भारी कटौती करते हुए अनेकों फ्लाईओवर, वीयूपी व पीयूपी आदि को डीलिंक कर दिया गया है। जिसके कारण अब आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं, जाम संबंधी परेशानियों को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। हाईवे से सम्बन्धित समस्याओं को लेकर जयपुर ग्रामीण लोक सभा के सांसद केन्द्रीय खेल मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्य वर्धन सिहं राठौड़ भी केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं एनएचआईए के अधिकारियों से मिलकर बैठकें कर चुके है । जानकारी के अनुसार राजस्थान पुलिस को भी हाई वे पर यातायात कन्ट्रोल करने तथा जाम खुलवाने में भारी मस्कत करनी पड़ती है इसको लेकर पुलिस द्वारा राज्य सरकार और एनएचएआई को अनेकों बार पत्र लिख कर हाई वे की तकनीकी विसंगतियों को दुरुस्त किये बिना जाम एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में असमर्थता जताते हुए हाई वे के पुनः मापन की सलाह दी है। नित्येन्द्र मानव द्वारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दिल्ली के समक्ष भी जनहित याचिका दायर की गई थी। कमीशन द्वारा अनेकों बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी एनएचएआई द्वारा कमीशन के निर्देशों की पालना नही किये जाने पर नित्येन्द्र मानव ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

कीरतपुरा के कैलाश चौधरी को किसान वैज्ञानिक पुरस्कार

कोटपुतली तहसील के कीरतपुरा गांव निवासी प्रगतिशील किसान कैलाश चौधरी को जैविक खेती में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए उदयपुर के पेसिफिक यूनिवर्सिटी में आयोजित समारोह में किसान वैज्ञानिक पुरस्कार से नवाजा गया है।

उन्हें यह पुरस्कार महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उमाशंकर शर्मा, पशु विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉ एके गहलोत, पेसिफिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भगवती प्रसाद शर्मा व भारतीय कृषि अनुसंधान कृष्ण मुरारी व एनएस राठौड़ ने एक समारोह में संयुक्त रूप से दिया। इससे पहले प्रगतिशील किसान चौधरी की मेहनत व लगन को देखते हुए अब तक विभिन्न सरकारों ने दर्जनों बार इन्हें सम्मानित किया गया है। इन सम्मानों के बीच सबसे बड़ा सम्मान उन्हें तब मिला जब राजस्थान सरकार ने उनका नाम प्रगतिशील किसान प्रतिनिधि के रूप में पेश किया और केंद्र सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उनका नाम शामिल कर लिया। उनकी इस उपलब्धि पर चौधरी को तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पंवार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब तक सम्मानित कर चुके है। ■

मोदी बनाम अंबानी

फिर छिड़ी कारपोरेट वार का मोहरा है नीरव मोदी

● अनुज अग्रवाल

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने में यूपीए सरकार के समय में सरकार और कारपोरेट जगत में छिड़ी लड़ाई का महत्वपूर्ण योगदान था। यू तो उस समय हुए लाखों करोड़ के घोटाले यूपीए के नेताओं व कारपोरेट जगत की जुगलबंदी का परिणाम थे, मगर जब घोटाले उजागर हुए तो सरकार व नेता इनके लिए कारपोरेट जगत को दोषी ठहरा साफ बचने की कोशिश करने में लग गए। उच्चतम न्यायालय द्वारा उस समय कोयला व टूजी स्पेक्ट्रम आबंटन रद्द करने से अनेक राजनेता, नौकरशाह, मीडिया हाउस, दलाल आदि भी कारपोरेट जगत के साथ ही सीबीआई व न्यायलय की जांच के रडार पर आ गए थे। इसी कारण कांग्रेस पार्टी में भी सोनिया व मनमोहन के बीच शीत युद्ध छिड़ गया था क्योंकि सोनिया मनमोहन को बलि का बकरा बना राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की फिराक में थीं। मनमोहन ने बलि का बकरा बनने की जगह घोटाले में फंसे कॉरपोरेट व अमेरिकी आईटी लॉबी की मदद से अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन खड़ा करवा सोनिया को बैकफुट पर ला दिया। संगठन, अनुभव व दूरदर्शिता के अभाव में अन्ना की टीम बिखर गयी और केंद्रीय राजनीति में तेजी से अपनी जगह बनाने को आतुर नरेंद्र मोदी ने संघ व भाजपा के मजबूत कैडर व संगठन और कांग्रेस से खार खाए कारपोरेट जगत (विशेषकर मुकेश अंबानी) की मदद से सन 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली।

सरकार बना लेने के बाद मोदी के सामने बड़ी चुनौतियाँ थीं। सबसे बड़ी दक्षिणपंथी यानि राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी अपने समर्थकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए कार्य करना दूसरी ओर उस कारपोरेट लॉबी जिसका नेतृत्व मुकेश अंबानी कर रहे थे को संतुष्ट करना और तीसरे भ्रष्टाचार से उकताई जनता को यह साबित करना कि उनकी सरकार सुशासन व पारदर्शिता में पूरा यकीन रखती है। इन सबसे भी बड़ी चुनौती देश की डूबी हुई अंतरराष्ट्रीय साख व खोखली अर्थव्यवस्था व बदहाल बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत कर उनकी साख बहाल करना।

निश्चित रूप से मोदी सरकार का पिछले चार सालों का सफर दुधारी तलवार पर चलने जैसा रहा। अगर परिणामो के रूप में आंकलन किया जाए तो मोदी सरकार में कुछ धीमे ही सही मगर हिंदुत्व व संघ के एजेंडे पर काम हुआ और इसी का परिणाम है कि वर्तमान में 19 राज्यों में भाजपा की सरकार है। मोदी सरकार ने संरक्षणवादी कांग्रेसी नीतियों को पीछे छोड़ पारदर्शी तरीके से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के द्रुत विकास का जो अभियान छेड़ा उससे देश की कारपोरेट लॉबी को जबरदस्त काम मिला और इसी कारण शेयर बाजार जबरदस्त ऊंचाईयों पर है। आपसी समझ के तहत मोदी सरकार ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ही बड़ी कानूनी कार्यवाही की व कॉरपोरेट घरानों को आगे ईमानदारी से काम करने के वादे के साथ बचाए भी रखा। यह एक व्यावहारिक रास्ता था जिसके एवज में भाजपा को बड़ा चंदा इन घरानों ने दिया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप मोदी सरकार ने बड़ी लड़ाई छेड़ी। देश से दलाल संस्कृति का सफाया ही कर दिया। फर्जी मीडिया संस्थानों पर रोक लगा दी, नौकरशाही की जबाबदेही तय करनी शुरू की, न्यायलय की जबाबदेही का बिल भी पास कराया, चुनावी चंदे की पारदर्शी व्यवस्था बनाई, ई टेंडरिंग की व्यवस्था व डिजीटलीकरण किया, हर व्यक्ति का आधार कार्ड व बैंक खाता बनवा सरकारी योजनाओं को उनसे जोड़ वहाँ पारदर्शिता लाए। पूरी दुनिया के दौरे किए और देश की छवि को बेहतर बना विदेशी निवेश व अप्रवासी भारतीयों को देश से जोड़ा। अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन का सबसे बड़ा काम मोदी सरकार ने नोटबन्दी व जीएसटी लागू करने के माध्यम से किया। ये कदम देश मे 67 बर्षों से सरकार को लूट रहे भ्रष्ट तंत्र व कॉरपोरेट जगत के सिंडिकेट के पांव पर सबसे बड़ी कुल्हाड़ी साबित हुए और एक ही झटके में देश में फैला काली अर्थव्यवस्था का ढांचा भरभराकर गिर गया। जनता के सर्वांगीण विकास व हितों की दृष्टि से यह आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा कदम रहा। इस कदम से विपक्षी दल व सरकार के तीनों अंगों के साथ ही उद्योग व व्यापार जगत के दिग्गजों की चूले ही हिल गयीं। बाजार में फैली लाखों करोड़ की नकली मुद्रा एक झटके से समाप्त हो गयी व लाखो फर्जी कम्पनियों को बंद कर दिया गया। अरबो खरबो के व्यापार पहली बार कर के दायरे में आ गए और काली अर्थव्यवस्था का दायरा सिकुड़ कर आधा रह गया जो आगे ओर भी सिमटना तय है। सरकारी खरीद व ठेकों से मजे लूटने वाले कारपोरेट जगत, ठेकेदारों, व्यापारियों व सरकारी कर्मचारियों के सिंडिकेट को पहली बार प्रतिस्पर्धा में उतरना पड़ा व गुणवत्तापूर्ण सेवाओं जैसी बातें होने लगी। भाजपा व संघ परिवार में भी मोदी विरोधियों व कांग्रेसी मानसिकता वाले लंपटों को मोदी की नीतियों से खासी परेशानी व नाराजगी होने लगी। कुल मिलाकर जिन जिन के हितों को चोट पहुँची वे सब मोदी के खिलाफ एकजुट होने लगे। रिलायंस समूह के मालिक मुकेश अंबानी जो स्वयं को किंगमेकर मानते हैं (अंदरखाने अपनी कम्पनियों पर बार बार पेनल्टी लगने, सरकार के संरक्षणवादी रवैये में परिवर्तन से कम काम मिलने व प्रतिस्पर्धा में पीछे राह जाने से, नोटबंदी के बाद अपनी बड़ी काली कमाई से हाथ धोने से परेशान व जीएसटी के कारण पहली बार टैक्स दायरे में आने से कुपित) मोदी के विरोध में आ गए और उनके संबंध यूपीए व कांग्रेस से पुन: मधुर हो चुके हैं। उठापटक के इस दौर में इसी लॉबी ने गुजरात चुनावों में भाजपा की सरकार को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माना जाता है कि राहुल गांधी के सारे कैम्पेन के पीछे अंबानी की ताकत लगी हुई थी जिसने गुजरात मे मोदी शाह की जोड़ी के होश उड़ा दिए थे। यह मोदी ही थे जिन्होंने विपरीत व लगभग असंभव सी परिस्थितियों में भी गुजरात मे फिर से भाजपा की सरकार बनवा दी और कांग्रेस - अंबानी कैम्प को धूल चटा दी।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप मोदी सरकार ने बड़ी लड़ाई छेड़ी। देश से दलाल संस्कृति का सफाया ही कर दिया।

गुजरात की जीत से आगे मोदी उत्तर पूर्व व कर्नाटक के चुनावों में तो लगे ही है साथ ही दिसंबर में लोकसभा चुनाव करा विरोधियों को धूल चटाने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। वे जानते हैं कि मुकेश अंबानी उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। इसीलिए उन्होंने रतन टाटा से अपने संबंध बेहतर किए। टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले में कॉरपोरेट वर्ग के दोषियों को निचली अदालत द्वारा दोषमुक्त होते रहने देना भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिससे कॉरपोरेट लॉबी का बड़ा हिस्सा उनके साथ रहे और ऊपरी अदालत में सीबीआई की अपील के माध्यम से नियंत्रण में भी रहे। यानि लोकसभा चुनावों में यह लोग उनकी राह में रोड़े नहीं अटका पाएं। मुकेश अम्बानी की मुश्के कसने के लिए ही नीरव मोदी व उनके मामा चौकसे जो मुकेश अंबानी के रिश्तेदार भी और गुजरात चुनावों में मोदी के खिलाफ सूरत के व्यापारियों को भड़काने वालों के नेता भी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गयी। इससे पूर्व ही संसद में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूपीए शासन में गलत तरीके से बांटे गए 52 लाख करोड़ रूपयों के बैंक लोन व उसके एनपीए में बदल जाने का रहस्य उजागर किया था और इस खुलासे का मतलब ही था कि बड़ी कार्यवाही होने जा रही हैं। मूकेश अंबानी के खास मामा भांजे की करतूतों की लिखित शिकायतों पर भी जानबूझकर कार्यवाही नही करने की रणनीति बनाई गई थी और सबूतों को इकट्ठा कर अंतत: एक झटके में सही समय पर बड़ी कार्यवाही की गई और कांग्रेस - अंबानी गठजोड़ को आगे ज्यादा बड़ीऔर सीधी कार्यवाही के संकेत भी दे दिए हैं । पूंछ पर पड़ी जोरदार चोट के कारण ही मोदी विरोधी गठजोड़ बिलबिला गया है और सोशल मीडिया व अपने पिट्ठू चैनलो की मदद से अंटशंट आरोप व अभियान चला रहा है, मगर असली बौखलाहट 52 लाख करोड़ की लूट में मोदी सरकार की संभावित अगली बड़ी कार्यवाही को लेकर है। देश का कोई बड़ा नाम नहीं जो इस खेल में नहीं फंसेगा। इसलिए इन सबको मोदी का संदेश स्पष्ट है अगर वह मोदी

मुकेश अंबानी का भांजा विपुल अंबानी गिरफ्त में

सरकार का विरोध करेगा तो कानून की जद में आएगा व रहे सहे से भी हाथ धो बैठेगा और अगर राजनीति में न पड़ पारदर्शिता व ईमानदारी से काम धंधा करेगा तो खुद का और देश दोनो का भला करेगा।

कुल मिलाकर देश राष्ट्रनीति से निकलकर राजनीति पर आ गया है और कॉरपोरेट लॉबी भी दोफाड़ हो पक्ष व विपक्ष में बंट गयी है। कुल मिलाकर सन 2019 के लोकसभा की जंग निश्चित रूप से दिलचस्प होने जा रही है और पहले के अनुमान की तरह एकतरफा नरेंद्र मोदी के पक्ष नहीं। हालाँकि नरेंद्र मोदी को उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में वे इस खेल को पुनः एक तरफा कर लेंगे क्योंकि उनकी नीयत सही है और जनता उनके साथ है। मोदी का यह अनुमान उनके आने वाले दिनों में उठाये जाने वाले कदमों पर निर्भर करता है । क्योंकि अब हमले चौतरफा होने है विपक्ष, मुकेश अंबानी के नेतृत्व में शक्तिशाली कॉरपोरेट लॉबी के एक हिस्से की ओर से , संघ परिवार के भीतर के दुश्मनों के और सीमा पार से चीन व पाकिस्तान जैसे शत्रुओं की ओर से। अगर मोदी रक्षात्मक तरीके से खेले तो फंसने की पूरी संभावना है। अगर वे सच मे अच्छी नीयत के साथ जनहित में कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें इस रण को बहुत आक्रमण रूप से लड़ना होगा। तब जन भी उनका होगा और तंत्र भी और वे निश्चित रूप से चक्रवर्ती होंगे।

पीएनबी घोटाले में ताबड़तोड़ एक्शन

देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के बाद अब एक-एक करके बड़े खुलासे हो रहे हैं। देश के कई बड़े नेता, राजनीतिक पार्टियों और मशहूर हस्तियों के काले कारनामों का पर्दाफाश हो रहा है। लुटेरे देश को बेचने में लगे हुए थे, खोखला कर रहे थे, मगर मोदी सरकार ने इनकी सारी योजनाओं को धराशायी कर दिया। मामला अब केवल पीएनबी बैंक तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब इसके लिंक कागजी कंपनियों और हवाला नेटवर्क से होते हुए देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों से जुड़ गए हैं।

पीएनबी घोटाले के तार जुड़े आम आदमी पार्टी से

मोदी सरकार के सख्त आदेशों के बाद जांच एजेंसियां तेजी से एक्शन में हैं। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी, रिश्तेदारों और उनके सहयोगियों से जुड़ी 150 शैल कंपनियों का पता लगा है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और सीबीआई की कार्रवाई को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

दरअसल शैल कंपनियों का इस्तेमाल गैरकानूनी गतिविधियों और कालेधन को खपाने में किया जाता है। पूरे मामले के लिंक अब अरविन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से भी जुड़ गए हैं। जानकारी मिली है कि 2010 से लेकर 2014 के बीच पीएनबी और केनरा बैंक ने एक बेनामी कंपनी को 5,86,50,00,000 रुपये के लोन दिए।

मजे की बात ये है कि इस बेनामी कंपनी के डायरेक्टर हेम प्रकाश शर्मा वही हैं, जिसने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को हवाला के जरिये 2 करोड़ रुपये कालाधन बतौर चंदे के रूप में दिया था। ये खुलासा आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य रह चुके नील टेरेंस हसलम ने किया है।

कपिल सिब्बल भी घपले में शामिल ?

दरअसल जितने कोंग्रेसी, वामपंथी व् आम आदमी पार्टी के नेता पीएनबी घोटाले को लेकर पीएम मोदी पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उन सभी के नाम इस घोटाले से जुड़ रहे हैं। कोंग्रेसी नेता कपिल सिब्बल, जोकि राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, उन्होंने भी पीएम मोदी पर काफी कीचड़ उछाला, मगर अब उन्ही का नाम इस महाघोटाले से जुड़ गया है।

डाटा साइंटिस्ट गौरव प्रधान ने खुलासा किया है कि नीरव मोदी ने एमआर एमजीएफ में कपिल सिब्बल का घर खरीदने के लिए पैसे दिए थे, इस घर की कीमत करीब 200 करोड़ रुपये है और ये सिब्बल की बेनामी संपत्ति है। कपिल सिब्बल दिखाने के लिए इस घर में रहने के लिए एमआर एमजीएफ को 15 लाख रुपये महीने का किराया भी दे रहे थे, मगर गुपचुप तरीके से एमजीएफ वो पैसे कपिल को वापस कर देती थी।

उन्होंने बताया कि एमजीएफ का सम्बन्ध रोबर्ट वाड्रा के साथ है और एमआर को जब इस अवैध लेन-देन की जानकारी मिली तो उसने एमजीएफ के साथ पार्टनरशिप खत्म कर दी। एमजीएफ कनिष्क सिंह की कंपनी है, जो अब प्रियंका गाँधी के साथ काम कर रही है।

इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि सिस्टम में बैठे कॉंग्रेसियों ने नीरव मोदी के घोटाले के बाहर आने से पहले ही इसकी जानकारी वाड्रा तक पहुंचा दी। 3 जनवरी, 2018 को रोबर्ट वाड्रा ने नीरव मोदी को फोन किया और इसके फौरन बाद नीरव मोदी अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग गया।

गौरव प्रधान ने सवाल किया है कि राहुल गाँधी ने अपनी लंदन और बैंकाक यात्रा के दौरान नीरव मोदी से मुलाकात क्यों की थी, दोनों के बीच क्या डील हुई थी? इन यात्राओं के दौरान राहुल गाँधी ने एसपीजी को भी साथ में नहीं रखा था, ताकि किसी तरह का रिकॉर्ड ना रहे।

कोंग्रेसी नेता रेणुका चौधरी के दोस्त हस्सान अली खान ने नीरव मोदी के एक सहयोगी के स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट नंबर 35833342181 में 48 करोड़ रुपये क्यों जमा करवाए?

मेहुल चौकसी ने अपने सिंगापुर के बैंक अकाउंट से पी। चिदंबरम के दुबई के बैंक अकाउंट नंबर DBS 24007007 में 14.5 करोड़ रुपये क्यों जमा करवाए?

उन्होंने दावा किया पीएनबी घोटाले के जरिये यदि नीरव मोदी हत्थे चढ़ जाता तो हथियारों के डीलर अदनान खाशोग्गी, नीरव मोदी, हसन अली और पी। चिदंबरम के आपसी संबंधों का पर्दाफाश हो जाता, इसीलिए नीरव मोदी को भगा दिया गया।

वहीं उन्होंने दावा किया है कि पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का भी इस घपले में पूरा-पूरा हाथ है। जांच के बाद राजन भी जेल जा सकते है।

उन्होंने सवाल उठाया है कि गीतांजलि जेम्स, गिली इंडिया, नक्षत्रा, फॉरेस्टर डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये सभी पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की कंपनी मेसर्स चैस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के ग्राहक कैसे बन गए?

नीरव मोदी ने पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम को हीरे तोहफे में क्यों दिए? इसके बदले में चिदंबरम ने नीरव मोदी की क्या सहायता की थी?

कोंग्रेसी नेता अभिषेक सिंघवी की पत्नी अनीता सिंघवी, नीरव मोदी की कंपनी के मालिकाना हक वाली प्रॉपर्टी की डायरेक्टर कैसे बनी?

काले कारोबारियों व् भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर की कांग्रेस ने खुली लूट

इतने खुलासों से साफ है कि कांग्रेस के महाभ्रष्ट नेताओं ने पहले तो बैंकों के जरिये नीरव मोदी जैसे कुछ चुने हुए कारोबारियों को गैर कानूनी तरीके से लोन दिए, जिसमें आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी उनका साथ दिया. इसके बदले में नीरव मोदी जैसे इन कारोबारियों ने कोंग्रेसी नेताओं व् उनके परिजनों को करोड़ों-अरबों की घूस दी, उनके परिजनों को अपनी कंपनियों में ऊंचे ओहदे दिए.

कुल मिलाकर मिल बाँट कर सभी देश को लूटने में लिप्त रहे. मगर देश की जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर इनका खेल बिगाड़ दिया. जैसे ही पीएम मोदी ने नोटबंदी की, सभी भ्रष्टाचारी एक सुर में रोने-चिल्लाने लगे. रघुराम राजन ने भी पद छोड़ने के बाद मीडिया में जाकर नोटबंदी के खिलाफ खूब दुष्प्रचार किया. दरअसल इन सभी भ्रष्टाचारियों को पता था कि आज नहीं तो कल उनके पापों का पर्दाफाश होकर रहेगा.

बहरहाल अब जांच शुरू हो चुकी है और बैंक अधिकारियों के साथ-साथ वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारी भी जांच के घेरे में आ चुके हैं. धीरे-धीरे सारी पोल खुलती ही जायेगी, ऐसे में ये कहना बिलकुल भी गलत नहीं होगा कि देश के कई बे नेता व् कारोबारी इसी तरह से देश छोड़कर भाग सकते हैं। ■

लिखते लिखते घोटाला हो जाए!

लिखते लिखते लव कराने वाले विक्रम कोठारी लिखते लिखते घोटाला करा गए और बैंकों का ऋण न चुका पाने के कारण आज जेल में हैं। किसी समय में ब्रांड बना पेन रोटोमैक आज घोटाले की स्याही से घिरा हुआ है। रोटोमैक लोन घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने रोटोमैक कंपनी के प्रमोटर विक्रम कोठारी और उनके बेटे राहुल कोठारी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में 4 दिन की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। कोठारी पर 3700 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। इसके पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कोठारी और उनके परिजनों के जमीन, समुद्र और हवाई मार्ग से भारत छोड़ने पर रोक लगा दी थी। विक्रम के पिता कभी कानपुर में साइकल चलाकर पान मसाला बेचते थे। फिर कानपुर में पान मसाले के पहले ब्रैंड टबादशाह पसंद के बंद होने के बाद पान बहार को टक्कर देने के लिए मार्केट में कोठारी परिवार के द्वारा पान पराग की शुरुआत की गयी। जिस तरह पेन का पर्याय रोटोमैक बना था, उसी तरह पान मसाले का पर्याय ही पान पराग बन गया था।

घोटाला

अपने परिवार से अलग होकर विक्रम कोठारी ने कई कदम उठाए, मगर वे सफल नहीं हुए। उन पर बैंकों का पैसा वापस न करने का आरोप है। रोटोमैक कंपनी को पांच बैंकों- इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ने लोन दिया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मुंबई शाखा से 485 करोड़ रुपये जबकि इलाहाबाद बैंक की कोलकाता शाखा से 352 करोड़ रुपये लोन लिया था।

जब एक साल के बाद कम्पनी ने न ही तो ऋण वापस किया और न ही ब्याज दिया तो भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के मुताबिक एक ऑथराइज्ड कमिटी गठित की गई। इस समिति ने 7 फरवरी 2017 को रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लि। को विलफुल डिफॉल्टर (जानबूझकर कर्ज नहीं चुकानेवाला) घोषित कर दिया। कमिटी ने खासकर बैंक ऑफ बड़ौदा की पहल पर यह आदेश पारित किया था। अप्रेल 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को उसकी उन संपत्तियों या किस्तों का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा को भुगतान किया गया है। कंपनी की ओर से दलील दी गयी कि रोटोमैक द्वारा चूक की तिथि के बाद से इस बैंक को 300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों की पेशकश किए जाने के बावजूद बैंक ऑफ बड़ौदा ने उसे इरादतन चूककर्ता घोषित कर दिया। जबकि बैंक ने कहा कि कंपनी को अपने बकाए का निपटान करने के लिए 550 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि कंपनी के निदेशक लोन रीपेमेंट से बचने के लिए दूसरी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं।

इन्हीं आरोपों के बीच जब कानपुर में कंपनी के दफ्तर पर ताला मिला तो अफवाह उड़ गयी कि विक्रम कोठारी देश से भाग गए हैं। मगर बहुत जल्द ही कोठारी रविवार को सामने आए और कहा कि वह कानपुर में ही हैं। उन्होंने कहा, बैंकों ने मेरी कंपनी को नॉन-परफॉर्मिंग ऐसेट (एनपीए) घोषित किया है, न कि डिफॉल्टर। मामला अब भी नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) में है। मैंने लोन लिया है और इसे जल्द वापस करूंगा।
मगर हाल फिलहाल वे जेल में हैं।

बैंक लोन की लूट
तेरी लुटाई, हमारी मलाई

नीरव मोदी के मामले में जिस प्रकार पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई और हाल फिलहाल तक लूट चलने के सबूत मिले उन्होंने सरकार के दावों की पोल खोल दी। सच्चाई यह है कि नोटबंदी के दौरान ही देश की बैंकिंग व्यवस्था के खोखलेपन देश व सरकार के सामने आ गए थे और बैंककर्मियों द्वारा अनेक स्तरों पर की गई ग बयों के कारण नोटबंदी के बांछित परिणाम नहीं आ सके परंतु अनेक आंतरिक कारणों व दबाव के कारण सरकार बैंकिंग व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कुछ खास नहीं कर सकी। बैंकों द्वारा ब` ऋण देने, उनकी वापसी व रिस्ट्रेकचरिंग की व्यवस्था में कुछ वरिष्ठ लोगो की ही प्रमुख भूमिका है और पूरी व्यवस्था बहुत संदिग्ध व अपारदर्शी है।

● **अनुज अग्रवाल**

यह यूपीए व कांग्रेस के नेताओं के लिए घोर आश्चर्य था कि 2004 से 2009 के कुशासन के बाद भी कैसे वे पुन: 2009 में केंद्र सत्ता में आ गए। शायद इसमें तेजहीन हो चुके भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी का अधिक योगदान रहा। इसी कारण सोनिया गांधी का आडवाणी व चौकड़ी (जेटली, सुषमा, वेंकैया व अनंत) से खास लगाव रहा। मोदी खेमे ने जब राजनाथसिंह व मोहन भागवत को शीशे में उतारा तो चौकड़ी का चक्रव्यूह टूटा। किंतु जेटली का कांग्रेस प्रेम रह रह कर छलकता रहता है। हद तो इस बार बजट के बाद जेटली द्वारा अपने पिटठू इंडिया टीवी को दिए गए साक्षात्कार में हुई जब जेटली के पीछे दीवार पर नेहरू की फोटो टंगी थी।

यूपीए के नेताओं को भरोसा था कि वे सन 2014 को लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो लंपटों की फौज ने देश को हर स्तर पर लूटने का खेल रचा। हर क्षेत्र में घोटाले जगजाहिर है। सोनिया मिसेज 10 परसेंटेज बन गयी और जिसने हिस्सा दिया उसे लूट की खुली छूट दी गयी। 52 लाख करोड़ के बैंक लोन भी इसी नीति के तहत बांटे गए। जिस प्रकार पीएनबी घोटाले से जाहिर हुआ कि भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं द्वारा विशेषकर यूरोप में ऋण दिए गए ऐसे दर्जनों और खेल खेले गए और लाखों करोड़ रुपए यूरोप व अमेरिका की मंदी की शिकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इटेलियन सोनिया मेनिया ने बंटवाए। डायलॉग इंडिया ने जनवरी,सन 2013 में ही रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बताया था कि कैसे हम आयात आधारित अर्थव्यवस्था में बदल चीन, आसियान देशों, अफ्रीका, यूरोप व अमेरिका का भला कर रहे हैं। अपने संसाधन व लोन उन पर लुटा रहे हैं।साथ ही 12 लाख करोड़ के लोन इसी खेल के कारण NPA में बदलने जा रहे हैं, मगर किसी ने इसे मुद्दा नहीं बनाया।

मौलिक भारत की ओर से मैंने सन 2014 में मोदी सरकार आने के बाद मांग की थी कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी करे ताकि अर्थव्यवस्था ओर बैंकिंग

व्यवस्था की स्थितियां पारदर्शी रूप से देश की जनता के सामने आ सकें। किंतु मोदी- जेटली की जोड़ी ने ऐसा नहीं किया। मोदी जी विभिन्न साक्षात्कारों में तर्क देते रहे कि ऐसा करने से हमारी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग व छवि खराब हो जाएगी। मोदी सरकार ने इसकी जगह यूरोप की सरकारों (लोन के नाम पर) को दबाब में लिया व अपनी नीतियों का समर्थन करवाया। देशी व प्रवासी भारतीय उद्योगपतियों को कार्यवाही न करने का लालच दे अपने पाले में किया। ऐसा करने के साथ ही उन लोगों के सामने शर्त रखी कि कांग्रेस पार्टी व यूपीए को कोई चंदा नहीं देंगे (सिर्फ भाजपा को ही देंगे)। दूसरी ओर बैंकिंग सिस्टम के कानून सख्त बना आगे किसी घपले, घोटाले व लूट को मुश्किल बना दिया, बैंक कर्मियों की जबावदेही तय की और दबाब बनाकर डूबे हुए लोन का 25 से 30 प्रतिशत तक वसूल भी कर लिया। तीसरे नोटबंदी लागूकर बैंकिंग व्यवस्था को पुन: मजबूत बनाया और अब जीएसटी व डिजीटलीकरण से स्वच्छ व पारदर्शी बना रहे हैं।

बात पुराने पापियों की है जिन्होंने कांग्रेस व यूपीए के नेताओं के साथ मिलकर बैंकिंग सिस्टम को ध्वस्त किया और भाजपा व एनडीए नेताओं को उस लूट का हिस्सा देकर गलबहियां की। इन पापियों के पापों की फाइलें कांग्रेस नेताओं के पास भी है और मोदी सरकार के पास भी। कांग्रेस की रणनीति दबाब बना अपने पाले से छूटे इन पुराने पापियों से पुन: सेटिंग करने की है। इस कड़ी में देर सवेर इनमें से कुछ की पोल पट्टी जनता के सामने आनी ही है ताकि बाकी पर दबाव बना सौदेबाजी की जा सके। साथ ही चुनावी राजनीति में चुनावों के समय इन पापियों के पापों की पोल खोलकर राजनीतिक दल जनता को भ्रमित कर सत्ता हथियाने के खेल खेलते हैं और बाद में जनता की आंखों में धूल झोंककर इन्हीं पापियों से सौदेबाजी कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद को हाल ही में बताया था कि यूपीए सरकार ने कुल 52 लाख करोड़ रुपये ऐसे ही बांटे अपने 10 साल के कार्यकाल में। उन्होंने कहा था कि हमारे पास पूरी सूची है गड़बड़ी करने वालो की। यह लोकसभा चुनावों का वर्ष है व कांग्रेस इस लूट की जिम्मेदारी भाजपा पर डालेगी, ऐसे में अभी तो ऐसे अनेको बड़े बड़े घोटाले व मामले सामने लाएगी। बेहतर होता सरकार स्वयं ही घोटालेबाजों की सूची जारी करे और यूपीए के पापों को न ढोये। लुटेरों पर कड़ी कार्यवाही व उनसे किसी भी प्रकार की सहानुभूति न रखने में ही मोदी सरकार की भलाई है। जो प्यार भाजपा नेताओं ने पुराने पापियों से दिखाया है कुछ ऐसा ही प्यार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने प्रवासी गुप्ता बंधुओं से दिखाया था और हासिल ही में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा व सत्ता गवानी पड़ी।

जनता बेचारी वज्र मूर्ख ही रहनी है। अस्तित्व के संघर्ष में उलझे लोगों के लिए यह उसकी समझ से बाहर ही रहेगा कि रुपया आता कहां है और जाता कहां है और मजे लेने वाले मजे लेते रहेंगे। ■

पीएनबी घोटाला

खुलासे के अंदरूनी राज

● **सन्तोष पाण्डेय**

बिना किसी भूमिका के शुरू करता हूँ। नीरव मोदी जैसे फ्रॉड अपने चकाचौंध भरे चहक चाम से सामने वाले को प्रभावित कर ठग लेते हैं।अपने शिकार को पैसे,शराब,शबाब व कबाब से सम्मोहित कर अपने वश में कर लेते हैं।एक बार फंसने के बाद शिकार जाल में छटपटा सकता है, छूट नहीं सकता।

कहानी की शुरुआत-

नीरव का व्यवसायिक बैंकर पीएनबी था,जहाँ उसके तमाम लोन, ओडी खाते हैं और करोड़ों का लेन देन होता था।

नीरव को व्यवसाय विस्तार के लिए लोन चाहिए था।सन 2011 में उसने

800 करोड़ लोन के लिए बात की।मैनेजर ने कहा कि दे देंगे परन्तु ब्याज 12 प्रतिशत होगा और उसे इस लोन के एवज में 900 करोड़ की सम्पत्ति गिरवी रखनी होगी।

नीरव ने कहा कि,अगर मैं डॉलर में लोन लूंगा तो मुझे ये काफी सस्ता पड़ेगा।उसने कहा कि मुझे *लिबोर (LIBOR=London Interbank Offered Rate=A system to lend money globally one Bank to Other Bank on cheap interest rate.).*

किसी भी देश के बैंक को किसी भी देश का बैंक इस LIBOR सिस्टम के तहत अपनी करेंसी में लोन दे सकता है।परंतु उसके लिए दो बातें अहम होती हैं।

पहला,ये की जो बैंक लोन लेना चाहता है उसे दूसरे देश के बैंक को Lo (Letter of

Undertaking) देना होता है और इसकी मान्यता स्विफ्ट संदेश (SWIFT=Society for Worldwide Interbank Financial Telecomm-unication) के द्वारा प्राप्त होती है।चूंकि इसमें LIBOR द्वारा निर्धारित रेट जो बमुश्किल 2 से 3 प्रतिशत होता है तथा ऊपर से 2त्न और अर्थात ब्याज दर तकरीबन 5प्रतिशत बैठता है। स्न्ष्ठ देने वाला बैंक भी 2प्रतिशत के करीब ऋण राशि पर चार्ज लेता है।इस प्रकार कर्जदार को 5प्रतिशत से 6प्रतिशत ब्याज पर लोन मिल जाता है। LoU पर जो विदेशी बैंक लोन देता है,उसे लोन लेने वाले व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता है बल्कि अगर वो लोन नियत समय पर नहीं चुकाता है तो वो पैसा LoU देने वाला बैंक चुकाता है।

अब फिर पीछे लौटते हैं। नीरव ने 2011 में बैंक के बड़े अधिकारियों से मिलीभगत की और बिना कोई सम्पत्ति पीएनबी के पास गिरवी रखे, रु.800 करोड़ के लिए LoU इशू करा के पैसे ले लिए जिसको 180 दिन में ब्याज सहित वापस करना था।

ये था पहला ट्रांजैक्शन पांच माह बीत जाने पर ऋण वापसी की व्यवस्था न होने पर पुन: 1000 करोड़ LoU इशू करवा लिया गया,जिससे पूरा ऋण और ब्याज चुकता कर दिया गया।इस प्रकार ये जो टोपीबाज़ी का सिलसिला शुरू हुआ वह अनवरत चलता रहा।

हमेशा एक स्न्ष्ठ को चुकाने के लिए उससे बड़ा स्न्ष्ठ खुलता रहा।इसमें थोड़ी बहुत राशि जो बैंक चार्ज के रूप में होती थी हर क्वार्टर में जमा हो जाता था ताकि वित्तिय घपले का पता न चल। इस पूरे षडयंत्र में बैंक के उच्चाधिकारी,ऑडिटर भी घुसे हुए थे। ये खेल बदस्तूर जारी रहा चाहे कोई अधिकारी रहे या जाए। सबको अपने कट से मतलब थ।यहां तक कि इस सारे ट्रांजेक्शन को इस प्रकार छुपाया गया था कि कोर बैंकिंग सिस्टम में भी ये दिखता नहीं था। दिसम्बर 2017 में नए अधिकारी आये और उन्होंने जब ये घालमेल देखा तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। उन्होंने नीरव को संपर्क करके उसे ये सब क्लियर करने को कहा,पर वो आज,कल पर टालने लगा। अधिकारी को तो सिर्फ 250 करोड़ के बारे में ही पता था क्योंकि विदेशी बैंक ने LoU के अगेंस्ट ब्याज की डिमांड की थी।जब पूरे ट्रांजेक्शन को ट्रेल किया तो LoU तकरीबन 12 से 13 हज़ार करोड़ रुपये का निकला। नीरव के बैंक में बैठे लोगों ने उसे स्थिति से अवगत करा दिया।नीरव रातोंरात भारत से निकल गया।

इसकी सूचना तत्काल वित्त मंत्रालय को दी गयी और एफआईआर दर्ज करके छापेमारियाँ व धर पकड़ शुरू हो गयी।

वस्तुत: जितने भी राष्ट्रव्यापी बैंकिंग वित्तिय फ्रॉड हुए हैं उसमें सरकारों से ज्यादा बैंक अधिकारी और ऑडिटर संलिप्त पाये जाते हैं।

अत: सत्यता ये है कि ये फ्रॉड नितांत एक समूह द्वारा किया गया है और उस समूह में बैंक के लोग होने से मास्टरमाइंड को हमेशा e&it करने का मौका उपलब्ध था।

अब सवाल नीरव और उसके परिवार का एफआईआर के पहले ही भागने का है तो, सरकार को पता ही नहीं चला की इसने कोई फ्रॉड भी किया है। क्योंकि कंप्लेंट करनेवाले तो खुद ही मठाधीश थे।

अत: ये कहना कि चोरी कांग्रेस ने शुरू करवाई और भाजपा ने जानबूझकर 4 साल आंखें मूंदे रखा और नीरव को भागने का मौका दिया,ये बात कुछ जँचती नहीं। हकीकत ये है कि भाजपा सरकार ने माल्या, नीरव के खिलाफ त्वरित कार्यवाही करके उनकी परिसम्पत्तियों को जब्त तो किया। हां अब सरकार को यथाशीघ्र इन चोरों की परिसम्पत्तियों को बेचकर अधिकाधिक रकम की भरपाई की कोशिश करना चाहिए। ■

एनपीए और नीरव मोदी

● **पुष्कर अवस्थी**

देखा जाये तो सारे पब्लिक सेक्टर के बैंकों का एनपीए, 734,000 करोड़ है और उसमे से नीरव मोदी का सिर्फ 11,400 करोड़ है जो पूरे एनपीए का सिर्फ 1.5प्रतिशत है। मेरे लिये यह रकम ऊंट के मुँह में जीरे के बराबर है और उससे लगता है की आने वाले समय में इससे भी बड़े एनपीए के नाम पर बड़े घोटाले सामने आयेंगे।

जब से नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से किया गया घोटाला सामने आया है तब से ही कांग्रेस और उसके मिडिया के टट्टू इस बात की डुग डिगी बजाने में लगे है की यह वर्तमान की नरेंद्र मोदी सरकार की यह बहुत बड़ी असफलता है। ये लोग यह बताने में लगे है की सरकार इस घोटाले पर चार वर्षों से चुप रही और नीरव मोदी को भारत से भागने दिया गया है। जबकि सत्यता यह है कि जो यह घोटाला पकड़ में आया है, यह सरकार द्वारा 2017 में, बैंकों के बकायेदारों के एकाउंट्स की कड़ाई और बारीकी से किये गये ऑडिट का परिणाम है। अब इस पर यह कहना की सरकार को 2016 में खबर हो गयी थी लेकिन सरकार ने कोई कुछ नहीं किया है, यह बिलकुल बेहूदा बात है। यह तो वही बात हुयी की एक दिन

आपको चोरी की खबर लगती है और चोरी करने वाले कथित चोर का नाम सामने आता है और अगले ही दिन उसको फांसी में चढ़ा देते है!

क्या यह औकात आपकी है?

यहां एक बात समझ लीजिये कि बिना ऑडिट के किसी भी वित्तीय अपराध को निर्धारित करना तो दूर, आप यह भी प्रमाणित नही कर सकते है की कोई अपराध हुआ है। अब केवल यह आरोप लगाना की आरोपी व्यक्ति देश छोड़ कर चला गया है और इसलिए सरकार इस घोटाले में शामिल है, यह दलील कानून रूप से न्यायालय में कोई भी मायने नहीं रखती है। मेरा अपना मानना है कि वर्तमान सरकार ने, यूपीए की सरकार की कार्य प्रणाली के विपरीत इस मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझते हुये, पूरी ऐतिहात बरती है और उन्होंने सारी प्रक्रिया को पूरी तकनीकी दायरे में, नियम कानून के अंदर पूरी की है, जिसका हमे कोई पता ही है। हमको इस के लिए सरकार की सराहन करनी चाहिए क्यूंकि यदि नीरव मोदी अपराधी है तो यह यकीन मानिये की वह सिवाय पाकिस्तान के कही भी बहुत देर तक छुप नहीं सकता है।

बहुत से लोग नीरव मोदी के बाहर भाग जाने पर विजय माल्या का उदाहरण दे कर फब्तियां कस रहे है लेकिन उस वक्त वह इस बात को न याद करते है और न ही बताते है की माल्या के ऊपर 1.5 बिलियन डॉलर का पुरे विश्व में उसकी सम्पतियों पर फ्रीजिंग आर्डर है, वो आजाद नहीं है बल्कि इंग्लैंड में 650,000 (छे लाख पचास हजार) पौंड के जेल बांड पर बाहर है, उसको सिंगापुर की बीओसी एविएशन को 90 मिलियन डॉलर जबरन देने पड़े है और अभी भी वो इंग्लैंड के कोर्ट में स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा निर्गत एक्सट्रडीशन वारंट के विरुद्ध केस लड़ रहा है।

जब हम कटाक्ष और नारे बाजी करने लगते है तब सब कुछ एक षड्यंत्र ही लगता है। राजनेता भ्रष्ट है, पुलिस जानबूझ कर देरी से पकड़ने पहुंची और उसे भाग जाने दिया गया, यह सब बहुत फिल्मी है और हम सिर्फ 2 मिनिट नूडल्स के तर्ज पर वही देख और समझ पाते है।

यदि आप तटस्थ हो कर इस सबको देखे तो आपको वर्तमान सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए क्यूंकि सरकार ने धैर्य पूर्वक भारत को एक आर्थिक आपदा से निकाला है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में यह कहा था की पब्लिक सेक्टर के बैंकों में एनपीए 36 प्रतिशत की जगह 82 प्रतिशत है और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को टूटने से बचाने के लिए उस पर चुप रहे तो यह शत प्रतिशत सही बात है। इन चार सालो में इस सरकार ने बैंको की यथास्थिति को उजागर करने और उनको कारगर बने रहने के लिये जो मेहनत की है वह स्पष्ट सामने दिख रही है। आपको अक्ल नहीं है तो यह बता दूं कि विश्व में कोई भी बैंकिंग सेक्टर 82 प्रतिशत की एनपीए ओढ़ कर जीवित नहीं रह सकता है। उसका दवालिया होना निश्चित है।

और जब किसी राष्ट्र के पब्लिक सेक्टर के बैंक दिवालिया होते है तो राष्ट्र दिवालिया हो जाता है। आज जब 4 वर्षों बाद स्थिति सरकार के हाथ में है तब जाकर पंजाब नेशनल बैंक अपने शेयरों में आयी गिरावट को झेल सका है। यही नीरव मोदी का मामला और 82 प्रतिशत की एनपीए भारत की जनता और देशी विदेशी निवेशकों को 2 /3 वर्ष पहले पता लगता तो जहाँ पंजाब नेशनल बैंक का दिवालिया होना तय था वही पर भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा कर 1991 से भी ज्यादा बुरी स्थिति में पहुँच जाती।

वर्तमान की सरकार को पूर्व की सोनिया गाँधी, मनमोहन सिंह, चिदंबरम और रघुराम राजन की भ्रष्ट यूपीए सरकार द्वारा निर्मित यह ऐसी वृहत वित्तीय घोटालो की समस्या मिली है जिससे मुक्त होने का सिर्फ एक ही उपाय था की प्रथमिकता के आधार पर एनपीए के पूर्ण सत्य का पता करना और एक एक वित्तीय अपराधी को कानून की हद में लाना है। जिस तरह से वर्तमान सरकार संभल संभल कर इन वित्तीय अपराधियों के खिलाफ मजबूत केस बना रही है, उससे मुझे तो यही आशा है कि आने वाले समय में और बड़े नाम/अनाम और बड़ी रकमों के साथ हमारे सामने आने वाले है। यह लेख Nilandri_Bose द्वारा लिखित अंग्रेजी में लिखे आलेख से प्रेरित लिखा है। ■

कांग्रेस, भा.ज.पा. और एनपीए

● कुमार पवन

कर्ज लेना और देना व्यक्तिक संव्यवहार (Private affair) माना जाता था। यद्यपि प्राचीन भारतीय शास्त्रकारों ने कर्ज के सम्बन्ध मे कुछ नियम बनाये थे जैसे दमदुपद का नियम और पुनीत दायित्व का नियम लेकिन कर्ज लेना और देना था व्यक्तिगत संविदा का ही विषय।

दमदुपद के नियम कर्जदार के संरक्षण के लिये था जिसके अनुसार कुल ब्याज की रकम मूल धन की दोगुना से ज्यादा नहीं हो सकती !

पुनीत दायित्व का नियम कर्ज देने वाले को सुरक्षा देने के लिये था जिसके अनुसार पिता के व्यक्तिगत कर्ज को चुकाना पुत्र , पौत्र और प्रपौत्र का पुनीत कर्म था।

इस्लामिक और अंग्रेजी शासन के दौरान भी कर्ज से सम्बन्धित भारतीय स्मृतिकारों के द्वारा प्रतिपादित इन नियमों का पालन न्यायालयों मे होता था।

अंग्रेजों ने संविदा अधिनियम 1872 व सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 बनाया।

कर्ज लेने व देने की संविदा भी इसी अधिनियम से शाषित होती थी। बंधक पर दिये जाने वाले उधार सम्बन्ध मे सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 मे प्राविधान बनाये गये थे। परंतु बंधक पर उधार लेना भी था संविदा (Contract) का ही विषय !

अगर कर्ज के भुगतान के लिये को प्रतिभूति (गारंटी) देता तो प्रतिभूति देने वाले (गारंटर) के अधिकार व कर्तव्य संविदा अधिनियम के प्रावधानों से ही शाषित होते थे।

गारंटर का कर्ज चुकाने का दायित्व द्वितीय (Secondary) था ..यानी मूल ऋणी के कर्ज चुकाने में असफल रहने पर ही गारंटर का दायित्व उत्पन्न होता है।

अगर ऋण दाता व मूल ऋणी कोई भी कर्ज की संविदा में परिवर्तन करते बिना गारंटर की सहमति के तो गारंटर अपने दायित्व से मुक्त हो जाता था।

एक बात और थी ..अगर ऋण दाता तीन वर्ष तक ऋण की राशि चुकाने के लिये ऋणी पर सिविल कोर्ट मे वाद नही लाता था ...तो वो कर्ज वसूली के लिये वाद लाने के अधिकार से वंचित हो जाता था ..!

और हाँ कर्ज दाता चाहे तो ऋणी को कर्ज चुकाने के दायित्व से मुक्त कर सकता था या पूरी राशि न लेकर कुछ भी स्वीकार कर संतुष्ट हो सकता था !

संक्षेप में कहे तो विधिक प्रावधानों के अनुसार कर्ज लेना व देना प्राईवेट संविदा थी! कर्ज देने वाले और कर्ज लेना वाले अपने हितों को ध्यान में रख कर विधि के नियमों की सीमाओ मे रह कर आपसी सहमति से करार कर के कुछ भी शर्ते तय कर सकते थे। जो शर्ते वो तय करते न्यायालय उन्ही के उनुसार व विधि की सीमाओ का ध्यान रख कर निर्णय देती थी !

इन्ही नियमो और सिद्धांतो पर बैंक भी कर्ज देते थे! बैंक अपने हितों का खुद ध्यान रखे! परिणाम स्वरूप बैंक के हितों मे बैंक के कर्मचारियों के हित जुडे हुये थे! बैंक अगर घाटे में जाता तो उसको चलाने वाले उसके कर्मचारी भी घाटा सहन करते! बैंकर अगर किसी को कर्ज देते तो उसके चरित्र और विश्वसनीयता को व्यक्तिगत स्तर पर जाँच -परख करते तभी कर्ज देते। बैंकार ईमानदारी की कद्र करते!

आजादी मिली संविधान लागू हुआ तो एक परिवर्तन देखने को मिला!

जैसे मैने कहा कि अंग्रेजों ने कुछ कानून जैसे संविदा अधिनियम व सम्पत्ति अंतरण अधिनियम तो जरूर बनाये परंतु भारतीय स्मृति कारों द्वारा प्रतिपादित कुछ सिद्धांतो (जिसे प्राचीन हिंदू विधि के सिद्धांत भी कह सकते है) को लागू करते रहे भारतीय बहुसंख्यक समाज मे। इनमे दमदुपद व पुनीत दायित्व का सिद्धांत भी था।

मजेदार बात ये है कि अंग्रेजो को प्राचीन भारतीय स्मृतिकारों के सिद्धांतों को लागू करने के लिये संस्कृति भाषा सीखनी या समझनी पढती ...और सीखते भी थे! अगर नही सीखते तो किसी संस्कृत के जानकारों से सम्पर्क करते!

संविधान लागू होने के बाद जो परिवर्तन भारत मे शुरू हुआ वो यह कि भारत मे सेकुलर सरकार व न्यायालय स्थापित होने लगी जो अंग्रेजो के बनाये हुये कानूनों को तो बढे गर्व से लागू करती लेकिन प्राचीन भारतीय स्मृति कारो के द्वारा बनाये गये सिद्धांतों तिलांजलि देने लगे! ये सिद्धांत धीरे धीरे साम्प्रदायिक नजर आने लगे! इन सिद्धांतो मे दमदुपद व पुनीत दायित्व का सिद्धांत भी था!

1975 में कुछ बैंको का राष्ट्रीय करण कर दिया गया। लोगों ने सरकारी कदम पर तालियाँ बजाई। अब बैंको तक सब की पहुंच हो गई।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया था, लेकिन कर्ज देने व लेने के नियम वही संविदा अधिनियम से शाषित होते रहे ..वो अंग्रेजो द्वारा बनाये गये संविदा अधिनियम व सम्पत्ति अंतरण अधिनियम से।

लेकिन अब बैंकों की स्थिति बदल चुकी थी! बैंक कर्मचारी अब सरकारी कर्मचारी बन चुके थे! बैंक कर्मचारियों का हित , बैंक के हित से अलग हो चुका था! बैंक चाहे मुनाफे मे हो

या घाटे में! बैंक चाहे दिवालिया होने के कगार पर ही क्यु न हो अब इसके कर्मचारियों की सैलरी पर कोई फर्क पढने वाला नही था! अब बैंक चाहे भले ही सारे ग्राहक खो दे, पर बैंक कर्मचारियों के ठेंगे से उनको कोई फर्क नही पडने वाला था।

बैंक चाहे घाटे मे हो लेकिन बैंक कर्मचारी सैंलरी व सुविधा को बढाने की मांग को लेकर हडताल करने से भी संकोच नही करते थे !

अब तो लोकतांत्रिक / संवैधानिक सरकार बेकार ही हो गई थी! लोकतांत्रिक सरकार की स्वयं तो आँख कान होता नही? जो सरकारी कर्मचारी दिखाये व सुनाये वही देख सुन पाती है! तो बैंक कर्मचारी अब कर्ज देते समय कर्ज लेने वाले की चरित्र और ईमानदारी की जाँच और परख मे व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया? कर्ज उसी को मिलता जो सरकारी बैंक कर्मचारी को खुश रखे। और ये जरूरी नही कि गैर-सरकारी ग्राहक की ईमानदारी और चरित्र सरकारी कर्मचारी को खुस रखने के लिये पर्याप्त हो ?

बैंक सरकारी तो हो गये .लेकिन बैंक के द्वारा कर्ज के आदान प्रदान मे वही कानून लागू होते जो दो गैर - सरकारी व्यक्तियों के बीच लागू होते थे।

संविदा अधिनियम इस सिद्धांत पर है कि संविदा के दोनों पक्षकार अपने अपने हितों को ध्यान मे रखते हुये ही संविदा करेंगे।

लेकिन बैंक कर्मचारियों का हित अब तो बैंक के हित से पृथक हो चुका था ? अब ये जरूरी नही कि जो सरकारी बैंक के लिये हितकारक हो उसके कर्मचारियों के लिये भी हितकारी हो? और जो बैंक कर्मचारी के लिये हितकारी हो वो जरूरी नही कि बैंक के लिये हितकारी हो? अब अगर किसी प्राईवेट ग्राहक से कर्ज देने के लिये संविदा करता तो ऐसी संविदा कर्मचारी के हित के लिये लाभकारी होके भी बैंक के लिये अहितकारी हो सकती थी!

और कर्ज की वसूली के लिये कर्मचारी का बिलकुल हित नही हो सकता था? कर्ज वसूली के लिए सिवल वाद ही लाना पडता जो शायद भारतीय न्यायालयो मे बीसियों साल लग जाते?

लिहाजा ऐसी स्थिति आने लगी कि बैंक

बैंक सरकारी तो हो गये .लेकिन बैंक के द्वारा कर्ज के आदान प्रदान में वही कानून लागू होते जो दो गैर - सरकारी व्यक्तियों के बीच लागू होते थे !

के कर्मचारी तो लाभ मे रहते और बैंक का दिया हुआ कर्ज डूबने लगता।

शोर शुरू हुआ कि NPA बढ़ने लगा।

तो नरसिम्हाराव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार Recovery of Debt Due to Bank & Financial Act 1993 बना कर लाई!

इसके द्वारा ये प्रयास हुआ कि कर्ज वसूली के जो केस सिविल न्यायालयो मे दाखिल करना पडता था ..उसके लिये Debt Recovery Tribunal और Debt Recovery Appellate Tribunal बना दिया। कांग्रेसी सरकार ये सोचा कि सिविल कोर्ट के बदले कर्ज वसूली के मुकद्मे Tribunal को सौप देने से कर्ज वसूली मे तेजी आयेगी ?

परंतु जैसी कांग्रेस की आदत है कि अपने जैसे संस्कार वालो के लिय कुछ न कुछ जरूर लूपहोल छोड देती है।

तो RDDB Act 1993 के साथ भी ऐसा हुआ कि चालाक कर्जदार जो पहले चार्वाक के चेले थे , अच्छे वकीलों के साथ मिल कर बैंक को Tribunal मे भी वर्षो चकमा देते रहे ..!

तो बैंको की सेहत मे ज्यादा सुधार नही हुआ ?

भाजपा की सरकार आयी। इसे व्यापारियों की सरकार कहाँ जाता था। लेकिन अटल जी की सरकार कुछ दूसरा सोच कर आयी थी। अटल के नेतृत्व वाली सरकार भी बढते एनपीए की चिंता करने लगी। तो भाजपा सरकार भी 2002 मे एक अधिनियम बना कर ले आयी जिसने कांग्रेस द्वारा छोड़े गये लूपहोल्स को भरने का प्रयास किया ?

इस अधिनियम का नाम था Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 संक्षेप मे SARFAESI Act .

इस अधिनियम के द्वारा बैंक और इसके ग्राहको के बीच जो संविदा विधि के सिद्धांत लागू होते थे .उसको बदलने का प्रयास किया गया।

मसलन जो गारंटर पहले मूल ऋणी के बाद दायी होता था उसे मूल ऋणी की तरह बना दिया गया। और बैंको को अधिकार दिया गया कि वो सीधे बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के ही कर्जदार द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति पर कब्जा कर सकते है और बेच सकते है।

तो जो लोन सिक्योर्ड है उनके लिये SARFAESI Act प्रभावशाली है।

अटल की सरकार बदली फिर कांग्रेस की आयी! अटल सरकार के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अच्छा खासा खजाना भर के गई थी तो मनमोहन सिंह की कांग्रेस कर्ज माफ भी कर्ज बाँटे भी। बड़े बड़े कर्ज।

जब बड़े कर्ज बाँटे तो एनपीए बढना ही था, तो इस बार कांग्रेस सरकार ने ज्यादा एनपीए न दिखाने की नीति अपनाई !?

खैर कांग्रेस सरकार गई और मोदी की सरकार आयी। मोदी सरकार ने रिजर्व बैंक की कुछ गाईडलाईन को लागू करने की नीति अपनाई !

तो ये पाया गया कि बहुत से ऐसे खाते जिन्हे PA दर्शाया जाता था ..वो तो वास्तव मे एनपीए है?

मोदी सरकार ने एक और बारीक चीज को पकड़ा ..कम्पनियों के बारे में, यह देखा गया कि कर्ज तो कम्पनी के नाम लिया गया। कम्पनी अपने को दिवालिया घोषित कराने का प्रयास कर रही है जबकि इसी कम्पनी के प्रमोटर धन दबाये बैठे है ? तो दिसम्बर 2017 मे मोदी सरकार कम्पनी के दिवालिया घोषित किये जाने वाले कानून मे संशोधन कर दिया। अब प्रमोटर भी जिम्मेदारी से बच नही सकते !?

ये थी एनपीए कांग्रेस - भाजपा की कथा ....। ■

विनीत
नारायण

क्या बैंक हमें लूटने के लिए हैं?

2015 में मैंने 'बैंकों के फ्राड' पर तीन लेख लिखे थे। आज देश का हर नागरिक इस बात से हैरान-परेशान है कि उसके खून-पसीने की जो कमाई बैंक में जमा की जाती रही, उसे मुट्ठीभर उद्योगपति दिन दहाड़े लूटकर विदेश भाग रहे हैं। बैंकों के मोटे कर्जे को उद्योगपतियों द्वारा हजम किये जाने की प्रवृत्ति नई नहीं है। पर अब इसका आकार बहुत बड़ा हो गया है। एक तरफ तो एक लाख रूपये का कर्जा न लौटा पाने की शर्म से गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ 10-20 हजार करोड़ रूपया लेकर विदेश भागने वाले नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक को अंगूठा दिखा रहे हैं।

उन लेखों में इस बैकिंग व्यवस्था के मूल में छिपे फरेब को मैंने अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों से स्थापित करने का प्रयास किया था। सीधा सवाल यह है कि भारत के जितने भी लोगों ने अपना पैसा भारतीय या विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है, अगर वे सब कल सुबह इसे मांगने अपने बैंकों में पहुंच जाएं, तो क्या ये बैंक 10 फीसदी लोगों को भी उनका जमा पैसा लौटा पाएंगे। जवाब है 'नहीं', क्योंकि इस बैंकिंग प्रणाली में जब भी सरकार या जनता को कर्ज लेने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो वे ब्याज समेत पैसा लौटाने का वायदा लिखकर बैंक के पास जाते हैं। बदले में बैंक उतनी ही रकम आपके खातों में लिख देते हैं। इस तरह से देश का 95 फीसदी पैसा व्यवसायिक बैंकों ने खाली खातों में लिखकर पैदा किया है, जो सिर्फ खातों में ही बनता है और लिखा रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक मात्र 5 प्रतिशत मुद्रा ही छापता है, जो कि कागज के नोट के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। इसलिए बैंकों ने 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कराकर आपके रूपए की ताकत खत्म कर दी। अब आप जिसे रूपया समझते हैं, दरअसल वह एक रूक्का है। जिसकी कीमत कागज के ढ़ेर से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस रूक्के पर क्या लिखा है, 'मैं धारक को दो हजार रूपए अदा करने का वचन देता हूं', यह कहता है भारत का रिजर्व बैंक। जिसकी गारंटी भारत सरकार लेती है। इसलिए आपने देखा होगा कि सिर्फ एक के नोट पर भारत सरकार लिखा होता है और बाकी सभी नोटों पर रिजर्व बैंक लिखा होता है। इस तरह से लगभग सभी पैसा बैंक बनाते हैं। पर रिजर्व बैंक के पास जितना सोना जमा है, उससे कई दर्जन गुना ज्यादा कागज के नोट छापकर रिजर्व बैंक देश की अर्थव्यवस्था को झूठे वायदों पर चला रहा है।

जबकि 1933 से पहले हर नागरिक को इस बात की तसल्ली थी कि जो कागज का नोट उसके हाथ में है, उसे लेकर वो अगर बैंक जाएगा, तो उसे उसी मूल्य का सोना या चांदी मिल जाएगा। कागज के नोटों के प्रचलन से पहले चांदी या सोने के सिक्के चला करते थे। उनका मूल्य उतना ही होता था, जितना उस पर अंकित रहता था, यानि कोई जोखिम नहीं था।

पर, अब आप बैंक में अपना एक लाख रूपया जमा करते हैं, तो बैंक अपने अनुभव के आधार पर उसका मात्र 10 फीसदी रोक कर 90 फीसदी कर्जे पर दे देता है और उस पर ब्याज कमाता है। अब जो लोग ये कर्जा लेते हैं, वे भी इसे आगे सामान खरीदने में खर्च कर देते हैं, जो उस बिक्री से कमाता है, वो सारा पैसा फिर बैंक में जमा कर देता है, यानि 90 हजार रूपए बाजार में घूमकर फिर बैंक में ही आ गए। अब फिर बैंक इसका 10 फीसदी रोककर 81 हजार रूपया कर्ज पर दे देता है और उस पर फिर ब्याज कमाता है। फिर वो 81 हजार रूपया बाजार में घूमकर बैंकों में वापिस आ जाता है। फिर बैंक उसका 10 फीसदी रोककर बाकी को बाजार में दे देता है और इस तरह से बार-बार कर्ज देकर और हर बार ब्याज कमाकर जल्द ही वो स्थिति आ जाती है कि बैंक आप ही के पैसे का मूल्य चुराकर बिना किसी लागत के 100 गुनी संपत्ति अर्जित कर लेता है। इस प्रक्रिया में हमारे रूपए की कीमत लगाकर गिर रही है। आप इस भ्रम में रहते हैं कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है। दरअसल, वो पैसा नहीं, केवल एक वायदा है, जो नोट पर छपा है। पर, उस वायदे के बदले (नोट के) अगर आप जमीन, अनाज, सोना या चांदी मांगना चाहें, तो देश के कुल 10 फीसदी लोगों को ही बैंक ये सब दे पाएंगे। 90 फीसदी के आगे हाथ खड़े कर देंगे कि न तो हमारे पास सोना/चांदी है, न संपत्ति है और न ही अनाज, यानि पूरा समाज वायदों पर खेल रहा है और जिसे आप नोट समझते हैं, उसकी कीमत रद्दी से ज्यादा कुछ नहीं है।

आज से लगभग तीन सौ वर्ष पहले (1694 ई.) यानि 'बैंक ऑफ इग्लैंड' के गठन से पहले सरकारें मुद्रा का निर्माण करती थीं। चाहें वह सोने-चांदी में हो या अन्य किसी रूप में। इंग्लैंड की राजकुमारी मैरी से 1677 में शादी करके विलियम तृतीय 1689 में इंग्लैंड का राजा बन गया। कुछ दिनों बाद उसका फ्रांस से युद्ध हुआ, तो उसने मनी चेंजर्स से 12 लाख पाउंड उधार मांगे। उसे दो शर्तों के साथ ब्याज देना था, मूल वापिस नहीं करना था - (1) मनी चेंजर्स को इंग्लैंड के पैसे छापने के लिए एक केंद्रीय बैंक 'बैंक आफ इंग्लैंड' की स्थापना की अनुमति

देनी होगी। (2) सरकार खुद पैसे नहीं छापेगी और बैंक सरकार को भी 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कर्ज देगा। जिसे चुकाने के लिए सरकार जनता पर टैक्स लगाएगी। इस प्रणाली की स्थापना से पहले दुनिया के देशों में जनता पर लगने वाले कर की दरें बहुत कम होती थीं और लोग सुख-चैन से जीवन बसर करते थे। पर इस समझौते के लागू होने के बाद पूरी स्थिति बदल गई। अब मुद्रा का निर्माण सरकार के हाथों से छिनकर निजी लोगों के हाथ में चला गया यानि महाजनों (बैंकर) के हाथ में चला गया। जिनके दबाव में सरकार को लगातार करों की दरें बढ़ाते जाना पड़ा। जब भी सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती थी, वे इन केंद्रीयकृत बैंकों के पास जाते और ये बैंक जरूरत के मुताबिक पैसे का निर्माण कर सरकार को सौंप देते थे। मजे की बात यह थी कि पैसा निर्माण करने के पीछे इनकी कोई लागत नहीं लगती थी। ये अपना जोखिम भी नहीं उठाते थे। बस मुद्रा बनायी और सरकार को सौंप दी। इन बैंकर्स ने इस तरह इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को अपने शिकंजे में लेने के बाद अपने पांव अमेरिका की तरफ पसारने शुरू किए।

इसी क्रम में 1934 में इन्होंने 'भारतीय रिजर्व बैंक' की स्थापना करवाई। शुरू में भारत का रिजर्व बैंक निजी हाथों में था, पर 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया। 1947 में भारत को राजनैतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन आर्थिक गुलामी इन्हीं बैंकरों के हाथ में रही। क्योंकि इन बैंकरों ने 'बैंक आफ इंटरनेशनल सैटलमेंट' बनाकर सारी दुनिया के केंद्रीय बैंकों पर कब्जा कर रखा हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था वहीं से नियंत्रित कर रहे हैं। रिजर्व बैंक बनने के बावजूद देश का 95 फीसदी पैसा आज भी निजी बैंक बनाते हैं। वो इस तरह कि जब भी कोई सरकार, व्यक्ति, जनता या उद्योगपति उनसे कर्ज लेने जाता है, तो वे कोई नोटों की गड्डियां या सोने की अशर्फियां नहीं देते, बल्कि कर्जदार के खाते में कर्ज की मात्रा लिख देते हैं। इस तरह इन्होंने हम सबके खातों में कर्जे की रकमें लिखकर पूरी देश की जनता को और सरकार को टोपी पहना रखी है। इस काल्पनिक पैसे से भारी मांग पैदा हो गई है। जबकि उसकी आपूर्ति के लिए न तो इन बैंकों के पास सोना है, न ही संपत्ति और न ही कागज के छपे नोट। क्योंकि नोट छापने का काम रिजर्व बैंक करता है और वो भी केवल 5 फीसदी तक नोट छापता है, यानि सारा कारोबार छलावे पर चल रहा है।

इस खूनी व्यवस्था का दुष्परिणाम यह है कि रात-दिन खेतों, कारखानों में मजदूरी करने वाले किसान-मजदूर हों, अन्य व्यवसायों में लगे लोग या व्यापारी और मझले उद्योगपति। सब इस मकड़जाल में फंसकर रात-दिन मेहनत कर रहे हैं। उत्पादन कर रहे हैं और उस पैसे का ब्याज दे रहे हैं, जो पैसा इन बैंकों के पास कभी था ही नहीं। यानि हमारे राष्ट्रीय उत्पादन को एक झूठे वायदे के आधार पर ये बैंकर अपनी तिजोरियों में भर रहे हैं और देश की जनता और केंद्र व राज्य सरकारें कंगाल हो रहे हैं। सरकारें कर्जे पर डूब रही हैं। गरीब आत्महत्या कर रहा है। महंगाई बढ़ रही है और विकास की गति धीमी पड़ी है। हमें गलतफहमी यह है कि भारत का रिजर्व बैंक भारत सरकार के नियंत्रण में है। एक तरफ बैंकिंग व्यवस्था हमें लूट रही है और दूसरी तरफ नीरव मोदी जैसे लोग भी इस व्यवस्था की कमजोरी का फायदा उठाकर हमें लूट रहे हैं। भारत आजतक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक उथल-पुथल से इसीलिए अछूता रहा कि हर घर के पास थोड़ा या ज्यादा सोना और धन गुप्त रूप से रहता था। अब तो वो भी नही रहा। किसी भी दिन अगर कोई बैंक अपने को दिवालिया घोषित कर दे तो सभी लोग हर बैंक से अपना पैसा निकालने पहुंच जायेंगे। बैंक दे नहीं पाएंगे। ऐसे में सारी बैंकिंग व्यवस्था एक रात में चरमरा जाएगी। क्या किसी को चिंता है?

नयी कार्यकारणी व नव मौलिक भारत का राष्ट्रीय

मौलिक भारत की स्थापना,व्यवस्था परिवर्तन, चुनाव सुधार, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ तमाम तरह के आंदोलनों का संचालन करने वाली बौद्धिक व सामाजिक संस्था मौलिक भारत का छठा स्थापना दिवस समारोह और द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दिनांक 3 फरवरी 2018 को अत्यंत गरिमापूर्ण वातावरण व सारगर्भित कार्ययोजनाओ पर चर्चा के साथ सम्पन्न हुआ। समारोह में संस्था के महासचिव श्री अनुज अग्रवाल ने गत दो वर्षो में संस्था द्वारा किये गए बीस बड़े कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। संस्था से जुड़े सदस्यों ने कई मुद्दों पर कार्य किया है और वे आज भी कर रहे हैं, श्री अनुज अग्रवाल ने संस्था के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कुछ वर्ष पूर्व जब पूरा देश यूपीए के द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों से त्रस्त था, देश में असंतोष बढ़ रहा था, और जनता अपनी जड़ों की तरफ लौटने की फिराक में थी, ऐसे में जब इतने आंदोलन हो रहे थे और कुछ आंदोलन विदेशी हितों से संचालित हो रहे थे। तब राष्ट्रवादी विचारों और राष्ट्रवादी उद्देश्यों को लेकर हमने मौलिक भारत की स्थापना की, समान विचार वाले लोग साथ आए और संस्था का जन्म हुआ। आयोजन में संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की पुस्तिका का अनावरण किया गया।संस्था के किये गए मुख्य कार्यों में हैं कैप्टन विकास गुप्ता द्वारा डीएनडी टोल ब्रिज को हटवाना, अनुज अग्रवाल और नीरज सक्सेना द्वारा चुनाव सुधारों के लिए संघर्ष, जिनमें अरविंद केजरीवाल द्वारा झूठा शपथपत्र दिया जाना हो, और चुनाव लड़ने वालों द्वारा गलत शपथपत्र भरे जाने के लिए संघर्ष, अश्वनी उपाध्याय द्वारा भ्रष्ट नेताओं के लिए 12 फास्ट ट्रैक न्यायालय, और हालिया मौलिक भारत के ट्रस्टी प्रशांत पटेल द्वारा आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कराने का मुकद्दमा हो। मौलिक भारत ने विकसित गांव और विकसित राष्ट्र की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। पूर्व सचिव भारत सरकार श्री कमल टावरी के मार्गदर्शन में यह अभियान अब एआईसीटीई के साथ विभिन्न राज्यों में संचालित हो रहा है। इसी प्रकार पिंकी चौधरी द्वारा सनातन संस्कृति की रक्षा हेतु हजारो युवकों को एकजुट करने का कार्य किया गया।आयोजन में नयी कार्यकारणी की भी घोषणा की गई।

राष्ट्रीय कार्यकारणी

- राष्ट्रीय संयोजक : पवन सिन्हा
- राष्ट्रीय अध्यक्ष : गजेंद्र सोलंकी
- राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष : कमल टावरी
- राष्ट्रीय संगठन मंत्री : विकास गुप्ता
- राष्ट्रीय महासचिव : अनुज अग्रवाल

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष :

- उमेश गौड़ (प्रशासनिक मामले),
- नीरज सक्सेना जी (घोटाला खोल एवं प्रशासनिक सुधार),
- श्रीमती उषा ठाकुर (महिला मामले),
- राकेश अग्रवाल, (दिल्ली बचाओ मोर्चा का समन्वय)
- डॉ. सुनील मग्गू , (संगठन विस्तार)

मुख्य सलाहकार

- कर्नल देवेंद्र सेहरावत जी (प्रशासनिक मामले)
- श्री प्रदीप गांधी, पूर्व सांसद(संसदीय

संकल्पों के साथ सम्पन्न हुआ अधिवेशन व स्थापना दिवस

मामले)

- श्री सुदेश अग्रवाल, (राजनीतिक मामले)
- अनंत त्रिवेदी जी ,(चुनाव सुधार , संगठन विस्तार)
- श्री ईश्वर दयाल कंसल (लोकपाल एवं मुख्य पर्यवेक्षक, कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण)
- **सचिव** : सुसज्जित कुमार
- **कोषाध्यक्ष :** श्री अमरनाथ ओझा
- **सह कोषाध्यक्ष :** राकेश सिंह
- **राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी :** प्रमोद सैनी
- **राष्ट्रीय कार्यालयप्रमुख :** गोपाल प्रसाद
- **राष्ट्रीय जनसंपर्क प्रमुख :** उषा शुक्ला
- **कानून एवं विधि सलाहकार :** राहुल राज मलिक एवं प्रशांत पटेल
- **आई टी एवं सोशल मीडिया:** शुभम मंगला , **सह संयोजक :** जतिन गोयल
- **धार्मिक मामले** : जितेंद्र खुराना
- **राज्य संयोजक** : रणवीर सिंह (हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश,), जितेंद्र तिवारी(दिल्ली), अश्वनी शंकर, अरविंद मोदी(बिहार एवं झारखण्ड), नाजरीन कृष्णामूर्ति (तमिलनाडु एवं केरल) रामस्वरूप रावत्सरे(राजस्थान), राजस्थान अध्यक्ष : मनोज यादव , संजीव चिकोटिया (मध्य प्रदेश), मनोज खंडेलवाल (उत्तर पूर्व), राजीव कुमार सिंह(पश्चिम बंगाल), हरियाणा प्रांत अध्यक्ष : प्रदीप पंवार,उत्तर प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष : अवनीश सिंह , महासचिव : पिंकी चौधरी, ,अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश: संजीव वर्मा
- **आरटीआई प्रकोष्ट**- संजीव गुप्ता
- **संयोजक** : महिला मोर्चा इंदु सिंह
- **संयोजक, युवा मोर्चा** : प्रशांत पटेल
- **महासचिव युवा मोर्चा:** एस पी सिंह

नवनिर्वाचित सभी सदस्यों ने संस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता हेतु शपथ भी ली।

आयोजन में संस्था से जुड़े हुए उन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जो मौलिक भारत के निर्माण में निरन्तर योगदान कर रहे हैं।

सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे

डॉ. कमल टाबरी, प्रशांत पटेल,अश्वनी उपाध्याय, विकास गुप्ता, पिंकी चौधरी, नीरज सक्सेना, संदीप देव।

इस अवसर पर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर परिचर्चा का आयोजन भी किया गया जिसमें संस्था के प्रमुख लोगो ने मिलकर आगे की कार्ययोजना का ढांचा प्रस्तुत किया।

भारतीय शिक्षा, संस्कृति व भाषाओं का संरक्षण कैसे हो

(प्रतिभागी-पवन सिन्हा, अमरनाथ ओझा, गजेंद्र सोलंकी, सीमा गुप्ता)

सुशासन, भ्रष्टाचार उन्मूलन व पारदर्शिता के लिए चुनाव सुधार

(प्रतिभागी- कैप्टन विकास गुप्ता, डॉ. सुनील मग्गू, राकेश अग्रवाल, संजीव गुप्ता, प्रशांत पटेल)

विकसित गाँव से कैसे होगा विकसित भारत?

(प्रतिभागी-डॉ कमल टावरी, गोपाल प्रसाद, , उमेश गौड़, अनुज अग्रवाल, सुसज्जित कुमार,)

संविधान की कथा सुनाने वाले पूर्व चीफ कमिश्नर आयकर श्री गिरीश पांडे जी के उदबोधन से सभी बहुत प्रभावित हुए। आयोजन में आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा, ओज के कवि श्री गजेंद्र सोलंकी, श्री राजेश गोयल, जितेंद्र तिवारी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ■

जीवन के स्वाध्याय का विज्ञान - आयुर्वेद

● सुरेश चंद्र

''अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ अपने जीवन की पुस्तक है''

डायलाग इंडिया के पिछले अंक में हमने स्वाध्याय के आध्यात्मिक पक्ष पर प्रकाश डाला था।

सामान्यत: स्वाध्याय का अर्थ निकाला जाता है वेदों, शास्त्रों एवं दर्शन का अध्ययन।

पतंजलि ने अपने योग सूत्रा में कहा है की स्वयं का अध्ययन करो, ईश्वर की प्राप्ति होगी। ओशो के अनुसार स्वाध्याय का अर्थ स्वयं का साक्षात्कार या अपने ही सामने खड़ा हो जाना है।

इस प्रकार का स्वाध्याय ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करना है।

आयुर्वेद में स्वाध्याय

किन्तु स्वाध्याय का एक और पक्ष भी है एवं जिसका सम्बन्ध हमारे शरीर एवं मन से है एवं जो आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। इस दृष्टिकोण से आयुर्वेद वास्तव में स्वाध्याय ही है जिससे हमें अपने जीवन के विषय में जानकारी मिलती है एवं इसी जानकारी के आधार पर हम ऐसी दिनचर्या अपना सकते हैं जो हमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगी।

आयुर्वेद ने जीवन के अध्ययन को सरल बनाने के लिए मनुष्य को तीन दोषों यानि व्यक्तित्वों में बांटा हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का निर्माण तीन व्यक्तित्वों के मिलने से होता है। इन तीन व्यक्तित्वों में एक व्यक्तित्व की प्रमुखता होती है एवं शेष दो प्रमुख व्यक्त्वि के सहायक की तरह काम करते हैं। ये व्यक्तित्व व्यक्ति की सहज प्रकृति की अभिव्यक्तियां हैं। इन तीन मूल व्यक्तित्वो को वात, पित एवं कफ का नाम दिया गया है। अपने व्यक्तित्व को जानने के लिए हमे अपनी देह, भावनाओं एवं विचारों का ज्ञान आवश्यक है अर्थात हमें अपने जीवन की किताब खोलकर उसका अध्ययन करना होता है जो वास्तव में स्वाध्याय है।

तीन व्यक्तित्वों के गुण

वात व्यक्तित्व :

वात व्यक्तित्व वाले लोग प्राय: ही दुबले, पतले होते हैं। उनकी त्वचा शुष्क एवं ठंडी होती है।

उनकी निद्रा गहरी एवं शांति पूर्ण नहीं होती एवं सपनों से भरी होती है। उनकी भूख अनियमित होती है एवं पाचन शक्ति कमजोर होती है। उनके शरीर का भार घटता-बढ़ता रहता है एवं वे ऊर्जावन नहीं होते। इसी कारण से शारीरिक श्रम में उनकी रूचि नहीं होती।

वात व्यक्तित्व वाले लोग स्वभाव से शर्मीले होते हैं, व्यग्र रहते हैं और चिंताओं में डूबे रहते हैं। उनका जीवन तनाव पूर्ण होता है किन्तु वे सर्जनशील होते हैं। यही कारण की इस प्रकृति के व्यक्तियों की लेखक, कवि, चित्रकार, वैज्ञानिक, संगीतकार एवं बनाने की पूर्ण संभावना रहती है।

असंतुलित वात

अगर किसी व्यक्ति में वात असंतुलित हो जाये तो वह भय एवं व्यग्रता से भर उठता है। उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, नींद कम हो जाती है एवं भूख कम लगती है। उसका वजन कम हो जाता है, ठण्ड लगती रहती है एवं वह अपने को ऊर्जा विहीन महसूस करता है। उसकी दिनचर्या अस्तव्यस्त हो जाती है।

वात को संतुलित कैसे करें?

वात व्यक्तित्व वालों के लिए नियमित एवं तनाव रहित जीवन एक आवश्यकता है। पर्याप्त नींद लेना एवं दोपहर को आराम करना उनके लिए आवश्यक है। उन्हें ऐसा भोजन करना चाहिए जो गर्म एवं तरह हो एवं जिसमें मीठे, खट्टे एवं नमकीन पदार्थों की अधिकता हो। हल्का व्यायाम, शांति देने वाले योगासन एवं प्राणायाम ऐसे लोगों के लिएए लाभकारी हैं। 15 से 20 मिनट ध्यान (मैडिटेशन) अत्यधिक वात को संतुलित करता है।

इन लोगों को ऐसा कार्य करना चाहिए जो बहुत लम्बे समय तक न चलें एवं तनाव रहित हो किन्तु जिसमे उनकी सर्जनशीलता को अभिव्यक्ति मिल सके।

जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसका वात भी बढ़ता जाता है।

पित्त व्यक्तित्व

पित्त व्यक्तित्व वाले लोग हृष्ट पुष्ट होते हैं। इनकी त्वचा में लालीपन और नमी होती है। देह में

गर्माहट, चलने में स्थिरता तथा चुस्ती होती है। ये लोग गहरी नींद सोते हैं एवं ऊर्जावान होते हैं जिसके कारण उनको व्यायाम में आनंद आता है। इनको भूख अधिक लगती है तथा पाचन शक्ति अच्छी होती है।

पित्त व्यक्तित्व वाले लोग जो भी काम करते हैं उसमें जोश होता है एवं इसी कारण ये लोग कर्मशील, उत्साही, निर्णय लेने वाले होते हैं एवं प्रत्येक क्षेत्र में लीडर बन जाते हैं। इन्ही गुणों के कारण ये समाज, व्यवसाय एवं राजनीति के क्षेत्रों में शीर्ष पर पहुँचते हैं और नए पथों को प्रशस्त करते हैं।

असंतुलित पित्त

असन्तुलित पित्त वाला व्यक्ति बेचैन रहता है एवं बात कर क्रोधित हो उठता है। उसके शरीर पर लाल चकते उभर आते हैं और पेट में पित्त अधिक बढ़ जाने के कारण छाती में जलन रहती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वह अनिद्रा का शिकार हो जाता है। किसी से मामूली अनबन होते ही वह प्रतिशोध की भावना से भर उठता है। यदि लम्बे समय तक पित्त असंतुलित दशा में चलता है तो डिप्रेशन का कारण बन जाता है।

पित्त को संतुलित कैसे करें?

असंतुलित पित्त को संतुलित करने के लिए व्यक्ति को पूरी नींद लेनी चाहिए। उसकी दिनचर्या में तनाव कम होना चाहिए और दूसरों से वादविवाद जंहा तक हो सके न हो तो बेहतर रहता है। अधिक खट्टे और मिर्च वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। चित को शांत रखने के लिए ठन्डे पदार्थ जो मीठे, कसैले या तिक्त स्वाद वाले हों का सेवन लाभकारी रहता है। नियमित व्यायाम, शांति प्रदान करने वाले योग आसन तथा ध्यान (मैडिटेशन) असंतुलित पित्त को संतुलित करते हैं। उन्हें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनमें उनकी नेतृत्व क्षमता, कर्मशीलता तथा निर्णय लेने की शक्ति का उपयोग हो सके। कफ प्रकृति वालों से मित्रता करना प्रकृति के व्यक्तियों को सदैव लाभदायक रहता हैं।

कफ व्यक्तित्व

कफ व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का शरीर भरा होता है और उनके चलने और बोलने में मधुरता एवं शिष्टता का आभास होता है। उनकी त्वचा, बाल और आँखों में उज्जवलता और चमक होती है। ये लोग गहरी और कम सपनों वालीर नींद सोते हैं। ये लोग खाने के शौकीन होते हैं किन्तु उनका पाचन कमजोर होता है। खाने में रूचि होने के कारण उनका वज़न जल्दी बढ़ता है और उसको कम करना मुश्किल हो जाता हैं यद्यपि उनकी स्मृति तीव्र नहीं होती किन्तु किन्तु एक बार यदि बात याद हो जाये तो आसानी से नहीं भूलती। अपने मधुर एवं शांत स्वभाव के कारण वे लोग सदा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। प्राय: ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका प्रचुर योगदान रहता हैं।

इनकी निर्णय लेने की क्षमता धीमी होती हैं किन्तु एक बार निर्णय ले लेने के पश्चात् ये उस पर अटल रहते हैं। कफ प्रकृति के व्यक्ति अच्छे अनुयायी होते हैं और किसी सन्देश या संस्था को लम्बे समय तक जीवित रखने में सक्षम होते हैं।

कफ व्यक्तित्व वाले लोगों में मित्र बनाने की सहज क्षमता होती है एवं उनके प्रगाढ़ सम्बन्ध लम्बे समय तक चलते हैं। जीवन साथी के रूप में कफ व्यक्तित्व वाले लोग सबसे उपयुक्त रहते हैं।

असंतुलित कफ

असंतुलित कफ वाले व्यक्ति के शरीर में पानी इको होना शुरू हो सकता है जिससे शरीर में सूजन आ जाती है तथा वजन बढ़ जाता है। परिणाम स्वरुप एवं ऊर्जा हीन हो जाते हैं। उनको जीवन नीरस लगने लगता है एवं वे निष्क्रिय हो जाते हैं। वे ज्यादा सोना शुरू कर देते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं।

कफ को संतुलित कैसे करें

कफ वाले व्यक्तित्व को संतुलित करने का सर्वोत्तम उपाय है शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्रय रहना। उनको अपनी दिनचर्या को इस प्रकार से ढालना चाहिए की मन और देह चुस्त रहें एवं ऊर्जा से भरे रहें। उन्हें नियमित रूप से भारी व्यायाम करना चाहिए। यदि वे रात में कम सोएं तो अच्छा है। उनका भोजन हल्का, मात्रा में काम एवं पौष्टिक होना चाहिए ताकि शरीर में भारीपन एवं सुस्ती न आ पाए। भोजन यदि सूखा एवं गर्म हो तो और भी अच्छा है। उन्हें मीठे एवं नमकीन खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए अन्यथा उनका वजन बढ़ सकता है।

कफ प्रकृति वाले के लिए बैठ कर करने वाला कार्य उपयुक्त नहीं होता। यदि ऐसा काम मिल जाये तो कोशिश करें की देह और मन सक्रिय रहे। ये लोग रात की शिफ्ट आसानी से कर सकते हैं।

अपने व्यक्तित्व के इन तीन रूपों को जानना जीवन की पुस्तक पढ़ने के समान है। जीवन की यह पुस्तक सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुन्दर है एवं इसे पढ़ना ही वास्तविक स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय से आत्मज्ञान होता है एवं एक संतुलित जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन मिलता है। जीवन का एक सुदृढ आधार मिलता है एवं जीवन की इमारत ऊँची बनती जाती है।

इस कारण से ही भारतीय मनीषियों ने आयुर्वेद का अविष्कार एवं विकास किया ताकि व्यक्ति तन एवं मन दोनों से ही सफल हो कर परम सत्य को प्राप्त कर सके। आयुर्वेद कपिल के सांख्य दर्शन से भी जुड़ा है एवं पतंजलि के योग का भी सहचर है। बिना आयुर्वेद के योग संभव नहीं है। जहाँ आयुर्वेद देह और मन को स्वस्थ रख सांसारिक सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है वहां योग आंतरिक यात्रा है और ध्यान से समाधि की ओर ले जाता है। ■

आधी आबादी की नई जंग

8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। विश्व भर में आधी आबादी के लिए यह दिन बहुत ही महत्वपुर्ण माना जाता है। इस दिन पूरे विश्व की महिलाएं स्वयं को एक व्यक्ति और अस्तित्व मानती हैं। इस दिन शायद पूरे विश्व में पूरे साल भर उनके साथ असहयोग का झंडा बुलंद करने वाले लोग भी समर्थन मं आते हैं। महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर हाल ही में सरकार ने कुछ कदम उठाए ह। इसके साथ ही पूरे विश्व में स्त्रियों के बीच अन्याय से लड़ने के लिए एक मुखर स्वर आ रहा है। क्या इसमें सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? पर अचरज है भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग बदलाव की इस बयार पर चुप है। लब हिल भी रहे हैं तो किंतु परंतु के साथ। बुद्धिजीवी व कार्यकर्ताओं का औरतों के विषय में भी अपनी विचारधारा देखकर संग आना चकित करता है। इसके साथ ही इस आन्दोलन की दिशा क्या होगी? ऐसे ही कई सवालों की पड़ताल करता हुआ **सोनाली मिश्रा** का यह आलेख।

एक तरफ खुला आसमान है और दूसरी तरफ उस खुले आसमान में भटक न जाने की आशंका है। एक तरफ स्वतंत्रता है, और दूसरी तरफ धर्म है। एक तरफ नियम है और दूसरी तरफ उन नियमों से परे होकर चलने की छटपटाहट, क्या किया जाए? स्त्रियों के लिए ऐसा समय है जहाँ पर चुनौतियां चौतरफा है और उसे उन चुनौतियों से पार पाना है, कुछ धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, जिनसे उसे जीतना है। कई परम्पराएं उसके लिए दम घोंटू हो गईं हैं, और जिनके खिलाफ वह आवाज उठा रही हैं। मगर महिलाओं के मुद्दे धर्म की चादर में लिपटे हुए मुद्दे हैं, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को उनके खास धर्म का बताकर बौद्धिक वर्ग में एक चुप्पी सी है,मगर महिलाएं शांत नहीं हैं। वे जहाँ मौका मिल रहा है अपनी आवाज उठा रही हैं, फिर चाहे भारत में एकबार में तीन तलाक बोल कर तलाक लेने की बात हो या फिर हज में यौन शोषण के खिलाफ अपना दर्द बयान करना। ऐसी ही एक जंग स्त्रियाँ सुदूर ईरान में लड़ रही हैं। वे खुद पर थोपी गयी धार्मिक कट्टरता का विरोध कर रही हैं। वे हिजाब के खिलाफ एक आन्दोलन चला रही हैं और इस आंदोलन में न केवल जेल जा रही हैं, बल्कि बिना डरे अपनी बात कर रही हैं।

इसी प्रकार अब तक मंदिरों में यौन शोषण की बात होती थी, मंदिरों में आने वाले लोगों द्वारा स्त्रियों का यौन शोषण किया जाता था, उसपर तमाम चर्चाएं होती थीं, और राहुल गांधी ने भी मंदिर जाने वालों को लड़कियां छेड़ने वाला बता दिया था, जबकि वही राहुल गांधी इस समय चुनाव जीतने के लिए मंदिर मंदिर चक्कर लगा रहे हैं। मंदिरों या कहें हिन्दू धर्म में कुरीतियों पर आवाज उठानी हो, तो यह दुनिया का सबसे सरल कार्य है। आप हिन्दू धर्म पर उंगली उठाकर सबसे प्रगतिशीलों की जमात में खड़े हो सकते हैं, और यदि आपको और प्रगतिशील बनना है तो आप मस्जिदों और मदरसों में होने वाले यौन शोषण के खिलाफ आँखें मूँद सकते हैं, और तीन तलाक मामले को मुस्लिमों का आपसी मसला बता कर हिन्दू धर्म की कुरीतियों पर ग्रन्थ रच सकते हैं और बौद्धिक विमर्श की पराकाष्ठा को छू सकते हैं। मगर जैसे ही पूरी दुनिया में इस्लामी महिलाओं के बीच सुधार की बात आए तो आप ये कहकर शांत हो सकते हैं कि स्त्री विमर्श महज स्टेटस सिम्बल नहीं है। यहाँ पर यह सवाल इन कथित बौद्धिक जमात वालों से पूछा जाना आवश्यक है कि स्त्री विमर्श स्टेटस सिम्बल नहीं है यह तभी क्यों याद आता है जब प्रश्न इस्लाम के स्त्रियों के प्रति कट्टर होने पर

होते हैं? या जब प्रश्न इस्लाम पर उठते हैं? सनातन धर्म अपने आप में प्रगतिशील धर्म है, वह अपनी सभी बुराइयों को स्वयं ही किनारे कर देता है, स्त्रियों के प्रति कट्टर सोच को कोई भी प्रगतिशील समाज स्वीकार्य नहीं कर सकता है और सनातन जैसा धर्म तो कतई नहीं और धीरे धीरे वह अपनी कुरीतियों से लड़कर स्त्रियों के प्रति स्वतंत्र समाज का निर्माण कर रहा है। हालांकि अभी भी कई कुरीतियाँ हैं जिनकी जंग स्त्री लड़ रही है, परंतु यह भी बात उतनी ही सच है कि जब भी कोई स्त्री आवाज उठाती है तो उसे समर्थन मिलता है और उसे यह कहकर बार बार हतोत्साहित नहीं किया जाता कि वह अपने धर्म को कमजोर कर रही है, क्योंकि धर्म इतना कमज़ोर है ही नहीं कि स्त्रियों द्वारा आवाज उठाए जाने पर डर जाए।

गिरता लिंगानुपात

फिर भी स्त्रियों को एक जंग लड़नी होती है, अभी भी अत्याचार हैं ही, अभी भी उनकी एक जंग जारी है, वह जंग कई स्तरों पर जारी है। हाल ही में जारी हुए लिंगानुपात के आंकड़े चौंकाने वाले हैं और भयावह हैं। देश के 21 बड़े राज्यों में से 17 राज्यों में जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गयी है। सबसे समृद्ध समझे जाने वाले गुजरात में प्रति हजार पुरुषों पर 53 महिलाओं की गिरावट दर्ज की गयी हैं, तो वहीं उसके बाद हरियाणा का नंबर है जहां पर 35 अंकों की गिरावट दर्ज की गयी है। नीति आयोग द्वारा जारी 'स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' नामक यह रिपोर्ट 2015-16 की अवधि के लिए तीन श्रेणियों बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर तैयार की गई है। यह रिपोर्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए प्रदर्शन का आकलन करने और उसे रैंक देने की केंद्र सरकार की एक कवायद है। इस रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात मामले में 10 या उससे ज्यादा अंकों की गिरावट होनेवाले राज्यों में से एक गुजरात में प्रति 1,000 पुरुषों पर 907 महिलाओं काअनुपात अब गिरकर 854 हो गया है। यहां साल 2012-14 (आधार वर्ष) से 2013-15 (संदर्भ वर्ष) के बीच 53 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है।

जिस देश में स्त्री को देवी मानकर पूजा जाता है, उस देश में महिला दिवस से पहले इस प्रकार के आंकड़े आना किसी भी प्रकार से शुभ संकेत नहीं है। इसी प्रकार स्त्री पर होने वाले अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। स्त्रियों के लिए न केवल सड़क पर चलना असुरक्षित हो रहा है बल्कि उसके साथ ही घर में रहना भी उतना भी कठिन हो रहा है। आखिर स्त्री को देखकर पुरुषों को ऐसा क्या हो जाता है कि वह आत्म नियंत्रण खो बैठता है, और वह न

हाल ही में जारी हुए लिंगानुपात के आंकड़े चौंकाने वाले हैं और भयावह हैं. देश के 21 बड़े राज्यों में से 17 राज्यों में जन्म के समय लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गयी है.

जाने भावनाओं के किस प्रवाह में बह जाता है कि वह न तो आठ वर्ष की मासूम पर तरस खाता है और न ही साठ वर्ष की वृद्ध स्त्री पर। यह प्रश्न विकट है क्योंकि एक तरफ लडकियां पैदा ही कम हो रही हैं, उन्हें इस दुनिया में आने के लिए जंग लड़नी पड़ रही है तो दूसरी तरफ जब वह आ जाती है तो उसे खुद को बचाए रखने के लिए एक जंग लड़नी पड़ती है।

डिजाईनर संघर्ष-

हाल ही में शिमला में हुए बलात्कार काण्ड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और कई सवाल पैदा किए थे। मगर एक और प्रश्न है जिससे स्त्रियों की अपनी जंग और कठिन हो जाती है। वह डिजाईनर संघर्ष! जी हाँ, डिजाईनर संघर्ष! जिस समय शिमला में एक चौदह वर्ष की लड़की के लिए न्याय के लिए पूरा पहाड़ उबल रहा था, उस समय दिल्ली में मैदानों में एकदम शान्ति थी। उस समय शिमला कांग्रेस शासित राज्य की राजधानी था, और स्त्री के लिए संघर्षों में उबाल तभी आता है जब वह अत्याचार भाजपा शासित किसी राज्य में हो। तो शिमला में इस जघन्य हत्याकांड पर दिल्ली में बैठे हुए बुद्धिजीवियों के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली और जिस दिन शिमला में लेखक समुदाय इस हत्याकांड के खिलाफ कांग्रेस से लड़ रहा था उन्हीं दिनों दिल्ली में हर छोटी मोटी बात पर अपने अवार्ड वापस करने वाले लोग दिल्ली की हिंदी अकादमी से सम्मान ले रहे थे।

ऐसा नहीं था कि उनकी कलम मौन थी, उनकी कलम दरअसल मौके की तलाश में थी। यह मौका मिला हरियाणा में वर्णिका कुंडू के मामले में। जैसे ही वर्णिका कुंडू की कार का एक भाजपा नेता के बेटे के द्वारा पीछा किए जाने का मामला आया वैसे ही स्त्री संघर्ष के सभी प्रतीक अपनी अपनी कलम लेकर बैठ गए और वर्णिका कुंडू के बहाने भाजपा और खास तौर पर हिन्दू धर्म को कोसने की एक लड़ाई हो गयी।

इसे डिजाईनर संघर्ष का नाम दिया जा सकता है, यह आधी आबादी की अपनी कोई जंग नहीं है। आज यदि देखा जाए तो समाज में अपना जीवन बचाने वाली गुडियाओं की तुलना में वर्णिका कुंडू जैसी स्त्रियों का प्रतिनिधित्व कितना है, यह भी विचारणीय है। स्त्रियों के लिए हर छोटे मोटे मुद्दे पर आवाज उठाने वाले कथित प्रगतिशील लोग भाजपा शासित राज्यों में किसी भी घटना के घटने की प्रतीक्षा करते हैं और वे अपने राजनीतिक आकाओं के राज्य में होने वाली हर घटना के प्रति एक शुतुरमुर्गी रवैया इख्तियार कर लेते हैं। जो अंततः केवल और केवल स्त्री की अपनी जंग के खिलाफ ही जाता है।

तीन तलाक के मामले पर रहस्यमयी चुप्पी-

भारत की स्त्रियों के लिए जो सबसे बड़ा कदम पिछले वर्ष

उठाया गया वह था एक बार में तीन तलाक बोले जाने को आपराधिक दंड की श्रेणी में लाने का प्रयास। पिछले कुछ समय से मुस्लिम समाज की स्त्रियाँ न जाने डरों की कितनी परतों में रहती थीं, और व्हाट्सएप और ईमेल के बाद तो जैसे पानी न देने तक जैसी छोटी बातों के लिए भी तलाक बोलकर छुटकारा पाने की प्रवृत्ति का विकास हो रहा था। अखबारों में रोज ही ऐसी कहानियां आ रही थीं कि शादी के बाद दुबई या किसी दूसरे देश या शहर से बाहर जाने पर पति ने अपनी पत्नी को फोन या एसएमएस से तलाक दे दिया। लड़कियां एक ऐसे डर में जिंदा थीं कि उन्हें न जाने कब घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। हालांकि कुरआन के अनुसार तलाक लेना इतना भी आसान नहीं है और उसके लिए तमाम तरह के नियम और कानून है जैसे कुरान पाक में तलाक़ की प्रक्रिया स्पष्ट तौर पर लिखी गई है, जो कि तीन तलाक़ के खिलाफ है। विशेष परिस्थितियों में तीन तलाक़ अपवाद की तरह होते हैं न कि रिवाज़ की तरह। तलाक़ मनमर्जी का मामला नहीं है। मगर ऐसा बहुत ही कम लोग मानते हैं, क्योंकि हाल ही में कई ऐसे मामले देखे गए जिसमें मनमर्जी से तलाक दे दिया गया जैसे अभी हाल ही में एक महिला ने अपनी विकलांग संतान के लिए पैसे मांगे तो उसे बदले में तीन तलाक मिल गया। ये मामले केवल नियम की गलत व्याख्या के कारण नहीं है बल्कि ऐसे सभी मामले स्त्री को वस्तु समझने की मानसिकता से प्रेरित हैं। उत्तर प्रदेश में एक पैर से विकलांग शबाना को सोते समय उसके पति ने तलाक दे दिया, जबकि उसकी शादी को महज एक ही साल हुआ था। अलगाव और मेल-मिलाप की कोशिशों के नाकाम हो जाने के बाद पुरुष और स्त्री दोनों को एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है जिसकी मियाद कम से कम तीन महीने (या तीन मासिक धर्म चक्र) की होती है। मगर एक बार में तीन तलाक बोलते समय ऐसी किसी भी शर्त का ध्यान नहीं रखा जाता। इस मुद्दे पर गाजियाबाद सें वकील शबनम का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का अभाव है जिस कारण उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके साथ आखिर हो क्या गया। इसी के साथ इस्लाम दो तरह के तलाक़ की बात करता है- एक 'खुला', जिसकी पहल पत्नी कर सकती है और दूसरा 'तलाक़' जिसकी पहल पति कर सकता है। मगर यदि आंकड़ों की बात करें तो खुला की प्रक्रिया ही इतनी जटिल है कि स्त्री अपनी तरफ से खुला मांग ही नहीं पाती। तीन तलाक़ पति द्वारा पहल किए गए तलाक़ का एक रूप है। अगर पति

महिलाओं का दर्द साझा है हिंदू मुस्लिम अलग नहीं

उषा ठाकुर, समाज सेविका एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मौलिक भारत (महिला मामले)

महिलाओं के अधिकारों पर तमाम बातें होती हैं, तमाम तरह की योजनाएं बनी हैं, महिला दिवस पर कई वादे और इरादे किए जाते हैं। मगर क्या वाकई महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, और सरकार द्वारा उठाए गए दमों का परिणाम क्या नीचे महिलाओं तक पहुँच रहा है, इन सब मुद्दों पर प्रख्यात समाज सेविका एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मौलिक भारत **श्रीमती उषा ठाकुर** से डायलॉग इंडिया की सह-संपादक **सोनाली मिश्रा** ने बात की।

मोदी सरकार द्वारा एक बार में तीन तलाक पर उठाए गए कदम पर आपकी क्या राय है? चूंकि आप महिलाओं के लिए कार्य करती हैं, तो क्या इसका फायदा समाज की उन महिलाओं तक पहुंचा है, जिन तक पहुंचना चाहिए था और दूसरा इस समय हर देश में स्त्रियाँ अपना स्वर मुखर कर रही हैं, फिर चाहे वह ईरान में हिजाब का विरोध हो या हज में यौन शोषण का, एक समाज सेविका के नाते इसे आप किस तरह से देखती हैं?

मुझे याद आता है कि एक महिला लेखिका ने कुछ समय पहले मुस्लिम जगत में सुधारों के लिए आवाज उठाई थी और उन्हें अपने ही देश से निष्कासित कर दिया गया था। तो स्वर उठते रहे हैं। और जहां तक बात है स्वतंत्रता की तो देखिये, महिलाओं को चाहिए ही स्वतंत्रता, कोई भी महिला हो उसे स्वतंत्रता चाहिए ही। वह बंधकर नहीं रहना चाहती। वह अपना अस्तित्व चाहती है। तो जो भी कोई आन्दोलन या लड़ाई है वह किसी स्त्री की लड़ाई न होकर एक अस्तित्व और व्यक्तित्व की लड़ाई होती है। आप किसी भी पेड़ की छत्रछाया के नीचे पनप नहीं सकते, जब तक आपका खुद का अपना अस्तित्व न हो। बहुत पहले कश्मीर की एक गायिका थी, जिसके गीत आज भी वादियों में गूंजते हैं, वह परितक्या थीं, खेत में काम कर करके गाना गाती थीं। तो एक युवक उसके गाने सुना करता था, तो एक दिन उस युवक ने उससे शादी का प्रस्ताव दिया। शादी करने के बाद उस युवक ने उस महिला के लिए सब तरह की सुविधाएं उसे दीं, मतलब गाने बजाने की, संगीत की और संगीतकारों से जुडी बातें दीं। और उसका नतीजा देखिये, तो आप एक महिला को थोडा संवार दीजिए मेरा यही कहना है। महिला महिला है, उसे हिन्दू और मुस्लिम में न बांटिये, कोई घुटन की जिन्दगी नहीं जीना

चाहता है। सभी को थोडा प्यार, थोड़ी हवा, थोड़ा स्नेह और शान्ति चाहिए, कि आप उन पर डांट फटकार न करें, क्योंकि आप देखिये कि महिलाएं स्रष्टि का ही दूसरा रूप हैं। प्रकृति और महिला समान हैं, आज नदियाँ सूख रही हैं, पर्यावरण एकदम बिखर रहा है। कारण यह है कि आज भी स्त्रियों पर अन्याय हो रहा है। तीस करोड़ से भी अधिक भ्रूण हत्याएं हो रही हैं देश में साल भर में, यह तो आंकड़ों की बात है, हकीकत तो इससे भी कहीं अधिक होगी। तो महिलाओं को पनपने दीजिए, फिर चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम हो। जो कि नहीं पनप रही हैं। आज ही मेरे पास एक केस आया है कि एक औरत के पति ने किसी दूसरी महिला को रख लिया है और पुलिस उस महिला की बात नहीं सुन रही है। चूंकि मुझे आज जरूरी काम से बाहर जाना है तो आकर मैं इस मामले को देखूंगी।

आज भी हिन्दू पुरुष किसी न किसी दूसरी स्त्री को रखे हुए है, तो बात केवल मुस्लिम महिलाओं की नहीं है, पूरी महिला कौम की है, कृपया महिलाओं को हिन्दू और मुस्लिमों में न बाँटें। आप देखिये जितना महिला सुरक्षा की बात बढ़ रही है, उतना ही महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है।

मगर मैडम, यह भी कहा जा रहा है कि अगर महिलाओं को आजादी दे दी तो वे भटक जाएँगी, आजादी का नाजायज फायदा उठाएंगी?

कैसे भटकेंगी? देखिये, अगर किसी लड़की को, मान लीजिये इंदिरा गांधी को बहुत प्यार से पाला पोसा, बेटे की तरह रखा, उसे हर तरह की आजादी दी, तो क्या वह भटक गई? मैंने देखा है कि जिस भी लड़की को पूरे प्यार से पाला पोसा जाता है, पूरी आजादी दी जाती है, वह कभी नहीं भटकेगी। मगर यदि आप महिलाओं को बहुत दबाएंगे तो महिलाएं सोच नहीं सकेंगी कि आखिर उन्हें करना क्या है? तो बहुत ज्यादा बंधन महिलाओं को अवसाद में ले जाता है। मैं लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ, और मैंने हमेशा गलत का विरोध किया। मेरे यहाँ कई नेता आते थे, मगर मैंने किसी को किसी के साथ बदतमीजी करते हुए नहीं देखा। मैं अपने मातापिता की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ी। मैंने अपनी आजादी का उपयोग औरतों के संघर्ष में किया। पहले लोग दीदी बोलते थे और आज माँ बोलते हैं, तो यह मर्यादा बनी। दुखद यह है कि समाजसेवा करने वाले लोग इस देश में आज हंसी का पात्र बनते हैं, जैसे महात्मा गांधी और मेरे जैसे लोग तो एकदम ही हंसी का पात्र बनेंगे क्योंकि आज इस देश में समाज सेवा से किसी को कोई मतलब नहीं है। जिस देश में पंद्रह लाख स्त्रियों के साथ बलात्कार होता है, लाखो बच्चे गायब हो रहे हैं, करोड़ों की संख्या में भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, तो ऐसे में देश क्या बदलेगा? इसीलिए हिन्दू हो या मुसलमान, हर एक नारी के अन्दर चेतना जाग्रत होनी चाहिए। हर स्त्री के भीतर ऐसी चेतना हो कि वह अपनी और आगे आने वाली संतति की लड़ाई लड़ सके। इतिहास के बहुत से उदाहरण हैं।

मगर फिर भी कहा जाता है कि महिलाओं को आजादी देने से उनके पर निकल आएँगे?

औरतों के पर निकलने चाहिए। औरतों के पर निकलेंगे तो वे अपनी उड़ान उड़ेंगे। वे समाज के लिए सार्थक करेंगे, क्योंकि स्त्री और प्रकृति दोनों एक ही हैं। जैसे आज पर्यावरण असंतुलन है ऐसे ही स्त्री के साथ अन्याय हो रहा है। कहीं न कहीं यह अत्याचार धरती भी नहीं सह पा रही है। दरअसल मैं स्त्रियों के लिए काम करती हूँ, तो मेरे अन्दर एक आग है। मुझे काम करना अच्छा लगता है। तो स्त्रियों को हिन्दू और मुस्लिमों में न बांटिये। उसे उसकी उड़ान भरने दें। महिला महिला है। और वही महिलाएं संतुलन कर काम कर पा रही हैं, जिन्हें स्वतंत्रता मिलती है। मेरा यही कहना है कि स्त्रियों को एक स्वतंत्रतापूर्ण माहौल मिलना चाहिए।

अपनी बीवी को तलाक़ देता है, तो उसे बीवी को मेहर चुकाना अनिवार्य है। मेहर वह रकम है जिसे निकाह के समय तय किया जाता है जो दूल्हा, दुल्हन को अदा करने का वादा करता है, या अदा करता है। हर निकाह के इक़रारनामे में मेहर की रकम साफ बताई जाती है। अगर बीवी खुला चाहती है, तो उसे मेहर पर से अपना हक़ छोड़ना पड़ता है क्योंकि निकाह को तोड़ने की पहल लड़की की तरफ से की जाती है।

अब प्रश्न यह उठता है कि जब तलाक के विषय में इतने नियम स्पष्ट हैं तो आखिर यह एक बार में तीन तलाक जैसा मामला क्यों उठा और क्या यह सभी मुस्लिम देशों में प्रचलित है? इस विषय में और अध्ययन से पता चलता है कि एक बार में तीन तलाक जैसी कुप्रथा को अधिकतर मुस्लिम देशों से समाप्त किया जा चुका है।

1. मिस्र दुनिया में तीन तलाक को प्रतिबंधित करने वाला पहला देश था। मिस्र में 1929 में मुस्लिम जजों की खंडपीठ ने सर्वसम्मति से तीन तलाक को असंवैधानिक करार दे दिया था।
2. वर्ष 1929 में ही मिस्र की ही परिपाटी पर चलते हुए सूडान की अदालत ने अपने देश में तीन तलाक को बैन कर दिया।
3. 1947 में आजाद हुए भारत और पाकिस्तान में पाकिस्तान किन्ही भी मामलों में पिछड़ा हुआ हो, मगत तीन तलाक को बैन करने में हमारा कट्टर दुश्मन हमसे कई कदम आगे है। पाकिस्तान में सन 1956 में ही तीन तलाक को बैन कर दिया गया था। इस के पीछे की कहानी है कि पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा ने 1955 में पहली पत्नी को तलाक दिए बिना अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली थी। इसी घटना के बाद देशभर की महिलाओं ने इस घटना का जम कर विरोध किया और तीन तलाक को प्रतिबंधित कराया।
4. भारत के एक ओर पड़ोसी देश श्रीलंका में तीन तलाक को कई विद्वानों ने एक आदर्श कानून करार

दिया है।

5. 1971 में पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश ने भी संविधान में संशोधन कर तीन तलाक को बैन कर दिया था।
6. साल 1959 में इराक दुनिया का पहला अरब देश बना था, जिसने शरिया कोर्ट के कानूनों को सरकारी कोर्ट के कानूनों के साथ बदल दिया। इसके साथ ही यहां तीन तलाक खत्म कर दिया गया।
7. इसी प्रकार सीरिया में तीन तलाक के कानून को इस तरह से तैयार किया गया है कि कोई भी पुरुष आसानी से पत्नी से अलग नहीं हो सकता है। यहां 1953 में जज के सामने तलाक का कानून आया।

इसी के साथ साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रूनेई मोरक्को, कतर और यूएई में भी तीन तलाक पर प्रतिबंध है।

भारत में आखिर क्यों है मुद्दा?

तो प्रश्न यह है कि जब पूरे विश्व में इस अमानवीय प्रथा पर एकमत हुआ जा सकता है तो भारत में आखिर यह मुद्दा इतना भटकाव लिए क्यों है, या स्त्रियों के पक्ष में आवाजें क्यों नहीं उठ रही हैं, यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या भारत का बुद्धिजीवी वर्ग मुस्लिम समाज में होने वाले सुधारों से खुश नहीं है? क्या वह नहीं चाहता कि मुस्लिम स्त्रियों को भी वह स्वतंत्रता प्राप्त हो जितनी हिन्दू या ईसाई महिलाओं को है? आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें इस महिलाओं के पक्ष में आने से रोकता है। इस विषय में साहित्यकार और आलोचक अर्चना वर्मा कहती हैं कि इसे बौद्धिक वर्ग की बेईमानी कह सकते हैं। वे इस मुस्लिम उथलपुथल को केवल भारतीय मुस्लिम के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं कि जो भारतीय मुस्लिम वर्ग चाहे वह करे, और शायद वह उनकी प्रगतिशीलता के अनुकूल है। एक बार में तीन तलाक के मुद्दे पर बुद्धिजीवियों के मौन पर उनका कहना है कि जिस प्रकार उन्हें लगता है कि हम अपने मुस्लिमों को खुद ही अगुआई का मौका दे रहे हैं, यही वे आतंरिक स्तर पर भी लागू कर रहे हैं कि उन्हें उनके मसले हल करने दिया जाए। और दूसरी बात उन्होंने भाजपा से बुद्धिजीवियों की दूरी करते हुए की कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम महिलाओं का साथ देना चाहिए तीन तलाक के मामले में, पर चूंकि यह बात भाजपा ने उठाई है और भाजपा द्वारा उठाई गयी कोई भी

इसी के साथ साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रूनेई मोरक्को, कतर और यूएई में भी तीन तलाक पर प्रतिबंध है।

बात, बिना सोचे समझे, यह बात तय है कि विरोध ही करना है। जबकि एक बार में तीन तलाक एक वर्ग के लिए चौबीसों घंटे एक ऐसे डर में जिंदा रहने जैसा है जिसमें आपको यह नहीं पता कि कब आप सड़क पर आ जाएं, कब आपका घर आपसे छूट जाए। तो एक बार में तीन तलाक के मुद्दे पर तो कम से कम स्त्रियों के पक्ष में नारीवादियों को आना ही चाहिए था, अब यह उनकी बौद्धिक बेईमानी को ही दिखा सकता है।

भाजपा पर स्त्रियों के प्रति पिछड़े विचार रखने के आरोपों पर भाजपा नेता और समाज सेवी रूमाना सिद्दीकी हंसती हैं और वे कहती हैं कि देखिये, स्त्रियों के लिए हक में भाजपा ने आवाज उठाई और उस पर ही पिछड़े होने का आरोप! इस पर तो हंसा ही जा सकता है।

इसी प्रकार इस मुद्दे पर खुलकर अपने विचारों को व्यक्त किया गाजियाबाद से वकील शबनम ने। उन्होंने साफ कहा कि एक बार में तीन तलाक पर कानून आना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एक बार में तीन तलाक से न केवल अनपढ़ औरतों बल्कि हम जैसी पढ़ी लिखी औरतों पर भी एक तलवार लटकी रहती है। अनपढ़ औरतों के लिए और समस्या है कि उन्हें एक तो समाज में सफाई भी देनी है कि आखिर उन्हें उनके पति से क्यों छोड़ दिया और दूसरी उनके सामने जीवन काटने की समस्या होती है। वे कहती हैं कि यदि किसी पढ़ी लिखी औरत को भी तलाक दे दिया जाए तो भी उसे रहना तो इसी समाज में है और वह कहाँ तक यह साबित करती रहेगी कि नहीं, वह खराब औरत नहीं है।

एक बार में तीन तलाक के मामले पर वे सवाल करती हैं, देखिये जब निकाह पढ़ा जाता है तो सबसे पहले किससे पूछा जाता है, औरत से ही न! पहले औरत हां करती है और फिर ही दूल्हा हाँ करता है, मगर तलाक देते समय केवल और केवल आदमी को अधिकार दे दिया कि जाओ और छोड़ दो। जब निकाह करते समय लड़की की रजा मंदी है तो तलाक एक तरफा क्यों? और इस कारण न जाने कितनी औरतें दबी घुटी सी जिन्दगी जी रही थीं, कम से कम एक उम्मीद तो जगी है उनके मन में कि अब आखिर उन्हें कोई ऐसे ही छोड़ नहीं देगा।

एक बार में तीन तलाक कानून का विरोध करने वाले बार बार इस बात पर अपना विरोध कर रहे हैं कि यदि तलाक देने वाला व्यक्ति जेल चला जाएगा तो परिवार का पालनपोषण कैसे होगा? इस विषय में शबनम का कहना है कि देखिये मैडम, जब उसने लड़की को छोड़ ही दिया है तो क्या फर्क पड़ता है कि वह जेल जाए या कहीं और! हकीकत तो यह है कि उसने एक बार में तलाक बोलकर लड़की से छुटकारा पा लिया है और वह अब अपनी जिन्दगी जीने के लिए आजाद है, जब वह लड़की को एक रुपया तक नहीं दे रहा तो आखिर उसे सजा क्यों न मिले? और देखिये जब तक सजा का डर नहीं होगा, तब तक यह सब नहीं रुकेगा! अब जब यह कानून बनने की बात हो गयी है तो अब सरकार को आगे बढ़कर इसे लागू करवाना चाहिए!

पेशे से ब्लोगर कायनात काजी इसे सामाजिक समस्या कहती हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार लता और प्रजा की प्रवृत्ति होती है संबल खोजकर आगे बढना, उसी प्रकार स्त्री भी संबल खोजकर आगे बढ़ती है, अब वह जिस माहौल में रह रही है, उसकी कंडिशनिंग

जिस माहौल में हुई है, वह उसी प्रकार सोचेगी। शादी तय हुई, और परिवार के हिसाब से शादी भी कर ली, तो किसी समस्या के मामले में सब उसके साथ हैं, मगर यदि जो लड़की समाज की बनी बनाई रेखा तोड़कर कोई भी कदम उठाएगी तो उसे सामाजिक एकाकीपन का डर दिखाया जाता है। यकीन मानिए आप एकदम अलग खड़े होंगे। आपके साथ कोई नहीं होगा. तो हमें उन लोगों का साथ देने की जरूरत है जो अलग कदम उठाती हैं, जो समाज की रेखा से आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश करती हैं.

भारत में बौद्धिक चुप्पी के प्रश्न पर निकट पत्रिका की सह संपादक प्रज्ञा पाण्डेय का कहना है कि एक समय था जब भारतीय संस्कृति में स्त्री सामाजिक दायरों में अपने मौलिक अधिकारों के साथ भागीदारी किया करती थी।भारतीय संस्कृति पर बाहरी हमलों और विदेशी आक्रमणों ने उस समाज को छिन्न भिन्न कर दिया जिसमें एक स्त्री सम्मान के साथ रहती थी। धर्म ने हमेशा स्त्री की आजादी छीनी है। चाहे वह हिन्दू धर्म ही क्यों न हो ।धर्म खासतौर पर स्त्री-हनन को सर्वोपरि धर्म मानता है। कुछ धर्म खुलेआम इस मंशा के साथ नियम बनाते है और कहते हैं कि औरत को पीटो बस इतना ध्यान रखो कि वह मरे नहीं और उसकी हड्डी न टूटने पाए। ऐसे में स्त्री की आवाज क्या उसकी चीख भी उसके भीतर दबी थी। यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि इस्लाम में औरतों की स्थिति दुनिया के किसी भी धर्म की तुलना में अधिक गंभीर रही है जहां उन्हें बंधक और गुलाम बनाकर रखा गया है। यह भी विडंबना है कि जब दुनिया को मंगल अभियानों पर जाने और वहां बस्ती बसाने की पड़ी है तब भी भारत में रह रहीं मुस्लिम स्त्रियां अपनी जिंदगी पर पड़े तलाक तलाक तलाक के मजबूत ताले को तोड़ने में लगीं हैं ।क्या यह वाकई सुखद है कि भारत की आजादी के लगभग सत्तर सालों बाद मुस्लिम स्त्रियों को सांस लेने के लिए थोड़ी सी हवा मिली? यह पहले क्यों नहीं हुआ? मौके तो बहुत आये । शाहबानो केस एक अच्छा अवसर लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के पास राजनीतिक साहस का अभाव था।

तथाकथित बुद्धिजीवियों के लिए यह भी एक विडम्बना ही है कि दक्षिणपंथी नीतियों के प्रति अपने झुकाव के लिए जानी जाती पार्टी से चयनित प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तीन तलाक को खत्म करने के लिए भारत में कड़ा कदम उठाते हैं और इस्लाम के कट्टर धर्मान्ध मौलवियों मुल्लों द्वारा बनाये गए निकाहनामे को चुनौती देकर उसे भारतीय संविधान के अंतर्गत लाने का निर्णय करते हैं।

यह वाकई दु:खद है तथा भारतीय राजनीति और तथाकथित बुद्धिजीवियों का दोहरा चरित्र भी है जो तीन तलाक के पक्ष में मुस्लिम स्त्रियों के खिलाफ जाकर यह दलील दे रहे हैं कि यह उनके इस्लाम का मामला है और इसे वे खुद ही सुलझाएं । सरकार उनकी धार्मिक संवेदनाओं को आहत न करे। ये लोग यह नहीं जानते कि इस मुद्दे पर अब तक तटस्थ रहने वाले, धर्म की मुखालफत करने का ढोंग करने वाले इन तथाकथित बुद्धिजीवियों को इतिहास माफ नहीं करेगा। ये बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोग तीन तलाक ही नहीं इस तरह हलाला के भी पक्ष में खड़े हैं और मुसलमान स्त्री की आजादी के धुर विरोधी साबित हो गए हैं।

स्त्रियां किसी भी धर्म की हों या किसी भी देश की सभी एक सी हैं। जब से मौजूदा मोदी सरकार ने तीन तलाक का मुद्दा उठाया है तब से जैसे एक हवा सी बह चली है। हज पर बिना पुरुष के स्त्रियों के अकेले जाने के लिए भी सरकार ने कदम उठाया है। मुस्लिम स्त्रियां अपनी आवाज उठा रहीं हैं जो सुनाई भी दे रही है। हज पर या मस्जिदों में उनका यौन शोषण होता रहा है ये मुद्दे अब सोशल मीडिया की सुर्खियां हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया भर में स्त्रियों के अच्छे दिन आ गए हैं। वे अपने मुद्दों को लेकर सड़क पर हैं । वे आंदोलन कर रहीं हैं।

> **हज पर या मस्जिदों में उनका यौन शोषण होता रहा है ये मुद्दे अब सोशल मीडिया की सुर्खियां हैं।**

बिना मेहरम के हज जाने की अनुमति

शबनम के अनुसार इस सरकार ने जो एक और अच्छा कदम उठाया है वह है बिना मेहरम के महिलाओं के हज में जाना। उनका कहना है कि पहले औरतें हज पर अकेले नहीं जा सकती थीं, न जाने कितनी औरतें हज पर जाने की इच्छा लेकर इस दुनिया से चली गईं, मगर इस सरकार ने औरतों की तरफ ध्यान दिया और बिना मेहरम के हज पर जाने के नियम को बदला। मेहरम के बिना औरतों के हज पर जाने की बात खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में की। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के फैसले के अनुसार 45 वर्ष से अधिक की मुस्लिम महिलाऐं अब चार के समूह में बिना मेहरम के हज पर जा सकेगी। मेहरम किसी महिला के पिता, पति, पुत्र और नवासे को कहा जाता है। ये वो खून के रिश्ते है जिनसे किसी महिला का विवाह नहीं हो सकता। तेरह सौ महिलाओं ने नए नियम के तहत हज यात्रा पर जाने के लिए आवेदन भी कर दिया है। इनमें सबसे अधिक आवेदन केरल से आए हैं। हालांकि इस कदम का भी कट्टरपंथियों के द्वारा विरोध हुआ, और इसे मुस्लिम महिलाओं का तुष्टिकरण कहा गया, मगर क्या समाज के एक बड़े तबके को अनदेखा किया जा सकता है?

वैश्विक स्तर पर आवाजें

ऐसा नहीं है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आवाजें केवल और केवल भारत में ही उठ रही हैं, बल्कि इस समय पूरा विश्व इन बदलावों को लेकर अपने से जूझ रहा है, जिसमें

महिलाएं चाहती हैं उनकी आवाज सुनने वाली सरकार हो:

रूमाना सिद्दीकी, सदस्य, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग

आधी आबादी की जंग अभी पूरी नहीं हुई है, वह अभी अपने कुछ हकों के लिए ल रही है. ऐसे में सरकार की क्या भूमिका है, सरकार के उठाए गए कदमों पर महिलाओं की क्या प्रतिक्रिया है, खास तौर पर तीन तलाक वाले मामले में, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. सरकार, समाज और स्त्रियों को लेकर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य **रूमाना सिद्दीकी** से बात की डायलॉग इंडिया की सह-सम्पादक **सोनाली मिश्रा** ने.

नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी एक बार में तीन तलाक पर जो फैसला लिया है, उस पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है?

देखिये, कोई भी महिला जिसे एक बार में तीन तलाक बोला जाएगा, और वह उसके बाद सड़क पर आ जाएगी और उसके बाद उसका कोई सहारा नहीं रहेगा, तो यह तो खराब है न, अगर सरकार ने उसके लिए यह कदम उठाया है तो यह तो उसके लिए फायदा है न, कि कोई भी उसे एक बार तलाक बोलकर उसे सड़क पर नहीं लाएगा। तो यह डर किसी के मन जाएगा तो वह किसी को एकदम से अपनी बीवी को घर से बाहर नहीं करेगा। और एक बार में तीन तलाक बोलना तो वैसे भी हमारे शरियत के अनुसार गलत है, किसी भी मैरिज एक्ट में होता है कि सुलह नामा की जगह होती है, जैसे आपके यहाँ तीन महीने का समय होता है, तो हमारे यहाँ भी तीन महीने का समय होता है। अगर इस समय में उन दोनों के बीच सुलह हो गयी तो वे फिर पहले की तरह रहेंगे, अगर एक ही बार में तीन तलाक दे देंगे तो क्या होगा? और जो कदम सरकार ने उठाया है वह बहुत सराहनीय है।

ग्राउंड पर बात करने पर तो लगता है कि औरतें इस कदम के समर्थन में हैं, फिर विरोध कहाँ हैं?

देखिये अभी कुछ लोगों ने कहना शुरू किया है कि अगर आदमी तीन तलाक देने के बाद तीन साल के लिए जेल चला जाएगा तो परिवार का क्या होगा? अरे भाई, जब उसने पहले ही परिवार को छोड़ दिया है। तो वह खर्चा पानी तो देना वैसे भी बंद कर चुका है, खर्चा पानी तो वह अपनी बीवी को दे नहीं रहा है। अब अगर सरकार ने जेल जाने की व्यवस्था की है, तो अगर वह जेल जाएगा तो कम से कम जेल जाने के डर से वह अपनी बीवी को छोड़ेगा तो नहीं। तो अगर उसका तलाक नहीं होगा, और वह घर में रहेगी तो उसका खर्चा पानी तो वैसे भी चल ही जाएगा।

तीन तलाक पर अपनी सबसे मुखर आवाज उठाने वाली इशरत जहां पर उसकी बेटी की आड़ लेकर ही चरित्र पर हमले हो रहे हैं कि बेटी के अनुसार माँ की ही गलती है, पिता ने कुछ नहीं किया। तो इस विरोध को कैसे देखा जाए?

अब ये क्यों उनकी बेटी क्यों ऐसा बोल रही है, यह भी देखना होगा। यह देखना होगा कि घर का क्या मसला है, क्या बेटी अपने पिता के साथ तो नहीं रह रही है, क्या बेटी किसी के बहकावे में तो आकर नहीं बोल रही है। जबकि उनकी यह लड़ाई तो अपनी बेटियों जैसी कई औरतों के हक की लड़ाई है, तो कई बातें हैं जो देखनी होंगी। कभी कभी तलाक हो जाता है और असली बात बच्चों को नहीं मालूम होती है। तो उस बच्ची को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पापा ने मम्मी को तलाक दिया है, क्या पता माँ की ही गलती हो। अब इस बात में क्या बोला जाए, मगर जैसा बाप उसके मन में भर रहा होगा वही वह बोल रही होगी। यह भी हो सकता है कि लड़की को किसी बात को लेकर डराया जा रहा हो, यदि ऐसा है तो लड़की को खुलकर सामने आना पड़ेगा।बहुत परिस्थितियाँ हैं, और जटिल हैं।

पूरे विश्व में इस समय महिलाएं खुद पर थोपे हुए मूल्यों का विरोध कर रही हैं, और खुद पर हुए यौन शोषण का विरोध कर रही हैं, फिर चाहे वह ईरान में हिजाब का विरोध करना हो या हज में हुए यौन शोषण पर बात करना, उनमें एक अपने आप सुधार की भावना बलवती हो रही है। इसे आप किस नजरिए से देखती हैं?

देखिये, आप किसी को हद से ज्यादा दबाएंगे तो विरोध होगा ही। यहाँ तक कि यदि आप घर पर ही अगर पति अपनी पत्नी को बहुत दबाएंगे या हम पेरेंट्स ही अपने बच्चों को बहुत हद तक दबाएंगे तो एक हद के बाद गुस्सा फूट कर बाहर आता है। एक छोटे बच्चे को भी अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा छेड़ेंगे तो एक हद के बाद वह भी मारने के लिए तैयार हो जाएगा। वही है कि महिला पर जब आप तमाम बंदिशें लादेंगे कि बुर्का पहनो, ये करो, वह करो तो वह कितने दिनों तक इन सबको देखेगी। हर किसी को लिबरल तरीके से जीने की आजादी होनी चाहिए, दबाने की राजनीति नहीं।

क्या वहां की इन आवाजों की गूँज का

असर हमें यहाँ की महिलाओं पर भी देखने को मिलेगा?

क्यों नहीं!

अब एक राजनीतिक सवाल। ऐसा क्यों होता है कि मुस्लिम सुधार की वकालत करने में बुद्धिजीवी वर्ग थोडा पक्षपाती है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि यदि मंदिरों में यौन शोषण की बात की जाए तो पूरा का पूरा स्कूल ऑफ थॉट विकसित हो जाता है, मगर इसकी तुलना में यदि ईरान में हो रहे विद्रोह और हज में यौन शोषण की घटनाओं पर बुद्धिजीवी वर्ग शुतुरमुर्गी रवैया इख्तियार कर लेता है। आखिर इन सबसे नुकसान तो महिलाओं का ही होता है न?

देखिये, सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे मुस्लिम समाज में स्त्रियों में शिक्षा की कमी है। और चूंकि वे शिक्षित नहीं होती हैं, और अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती हैं, तो वे डर जाती हैं। वे इस बात से डर जाती हैं, कि कल को हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हमें घर से निकाल दिया जाता है तो क्या होगा? आखिर हम क्या करेंगे? माँ बाप हैं तो क्या वे समर्थन करेंगे, और यदि नहीं हैं तो समाज कैसे इस विद्रोह को लेगा? बहुत समस्याएं हैं, तो पहले तो लडकियां ही अपना मुंह खोलने से डरती हैं। औरत के दिल में एक दर्द बैठ जाता है, और इसी डर के चलते वह किसी भी दूसरी महिला को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। चाहे वह दिल से कितना भी सपोर्ट क्यों न कर रही हो। आधा डर तो यही है कि अगर हमें घर से बाहर कर दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो जब समाज से ही आवाज नहीं उठेगी, तो उनके पक्ष में आवाज कैसे उठेगी। और समाज में लड़कियों को पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ अभी भी प्रतिशत कम हैं, जिस दिन हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ा लिखा दिया जाएगा उसी दिन से हमारे समाज में त्रुटियाँ कम होने लगेंगी। और फिर दुनिया भर में कहीं भी कोई रिवोल्ट होगा तो वे सपोर्ट करेंगी।

जो क्रांति और विरोध हो रहे हैं, वह तो ठीक है, मगर क्या यह विद्रोह सही दिशा में जाएगा? कई बार हमें न केवल लगता है कि विरोध दिशा बदल गया और कई बार लोग कहते हैं कि अगर लड़कियों को उनके मन का करने के लिए कह दिया गया तो वे बिगड़ जाएँगी? जैसा हमने स्त्रीवाद में देखा, कि पश्चिमी स्त्रीवाद ने हमारे स्त्रीवाद की दिशा को ही भटका दिया।

देखिये, जब हम विद्रोह की बात करते हैं, तो वह कुछ मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, विद्रोह यह न हो कि हम रिवीलिंग ड्रेस पहनेंगे, विद्रोह यह न हो कि जी हम तो कहीं पर भी खड़े होकर शराब पियेंगे। तो विद्रोह स्त्री की मूलभूत आजादी के लिए हो, कि उसके लिए एक सम्मानजनक माहौल हो, उसके लिए खुलकर काम करने की आजादी हो, वह बाजार के हाथ का खिलौना न बने। अगर हम सही कपड़े पहनते हैं, तो यह हमारे लिए भी अच्छा रहता है न, देखिये हर चीज की एक गरिमा होती है, आप इस गरिमा से परे तो नहीं जा सकते। आजादी के नाम पर अर्धनग्न वाले कपड़े न पहने जाएं, मतलब हर आन्दोलन की दिशा होनी चाहिए। तो मर्यादापूर्ण कपडे पहनने को पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं माना जाना चाहिए।

अभी गोवा के मुख्यमंत्री की इस बात पर बवाल हो रहा है कि अब तो लडकियां भी बियर पीने लगी हैं, तो समस्या बढ़ गयी है। अब इस बात के जबाव में लडकियां बियर के साथ सेल्फी लगा रही हैं। क्या इससे आंदोलन कमजोर नहीं होता है?

होता है क्यों नहीं होता है। देखिये, ड्रिंक करना या न करना आपकी अपनी चोइस है। मगर चूंकि श्री पर्रीकर जी ने एक राज्य का मुखिया होने के नाते यह बात की है तो मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर पीकर बवाल काटने के बाद नशे में यदि आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप किसे दोषी ठहराएंगी?

मुस्लिम महिलाओं के लिए जो तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं,क्या उसका फायदा मुस्लिम महिलाओं को मिल रहा है?

जरूर मिल रहा है, तभी मुस्लिम महिलाएं भाजपा की तरफ आकर्षित होकर आ रही हैं। उज्जवल योजना आदि योजनाएं समाज के हर वर्ग की जरूरत पूरी कर रही है।

अब अंतिम और सबसे जरूरी सवाल, भाजपा पर महिला विरोधी पार्टी होने का टैग है, इसे दूर करने का क्या प्रयास किया जा रहा है?

इस बात पर केवल हंसा जा सकता है। भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के लिए काम करती है, महिलाओं का आदर करती है। आप देखिये कितनी योजनाएं महिलाओं के लिए इस सरकार के द्वारा बनाई जा रही हैं और उन्हें जमीन तक पहुंचाया भी जा रहा है।

सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है। हाल ही में #metoo के नाम से उन स्त्रियों ने हैशटैग चलाया था, जिनका यौन शोषण हुआ था। और देखते ही देखते पूरी दुनिया भर की स्त्रियाँ इस अभियान से जुड़ गईं और कई स्त्रियों ने खुलकर अपने साथ हुए यौन शोषण की घटना को बताया। अब झिझक टूट रही हैं, परतें टूट रही हैं। मगर यह बहुत ही दुखद है कि उसके बाद शुरू किए गए हैशटैग #mosquemetoo की शुरुआत कुछ साहसी स्त्रियों ने की, तो भारत में इसे एकदम अनदेखा कर दिया गया। स्त्रियों ने उस तरफ झांकना मुनासिब न समझा। क्योंकि उन्हें यह पता है कि हिन्दू कट्टरपंथियों की तुलना में मुस्लिम कट्टरपंथियों से वे पंगा नहीं ले सकती हैं, और इस असहिष्णुता का पता युवा महिला कार्यकर्ता शेहला राशिद को तब लगा जब उन्होंने दिल्ली में अंकित की सरे आम हत्या के बाद मुस्लिम समुदाय से यह अपील की कि वे अपनी लड़कियों की शादी हिन्दू लड़कों से करने दें क्योंकि इससे प्रेम को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि शहला ने बाद में एक समाचार पत्र से बात करते हुए कहा महिलाओं को समुदाय और विश्वासों के जरिए बंधक बना लिया गया है और यह पुरुषों का धर्म है जो उनकी पसंद को निर्धारित करता है।

मगर हर मुद्दे पर खुलकर बात करने वाली शहला भी इस मुद्दे पर चुप हैं, शायद उन्हें भी बोलने से भय लगता है। इस अभियान की शुरुआत पत्रकार और लेखिका मोना एल्ताहवी ने अपने साथ हज यात्रा के समय हुई यौन उत्पीड़न की घटना के बाद की थी। मोना एल्ताहवी के

द्वारा इस घटना को उजागर करने के बाद उनके पास लोगों के मैसेज आने लगे। ट्विटर पर अपने ट्वीट में मोना कहती हैं कि मेरी कहानी पढ़ने के बाद एक मुस्लिम महिला ने अपनी मां के साथ हज यात्रा के समय हुई यौन उत्पीड़न की घटना को विस्तृत रूप से लिखकर मुझे मेल किया था। मोना के साहस की जहां तारीफ होनी चाहिए थी, वहीं मोना के खिलाफ लोग खड़े हो गए और उनका विरोध शुरू हो गया। मगर मोना ने हार नहीं मानी और उन्होंने इसे बंद करते हुए जारी रखा। इसके बाद से ही दुनिया भर से मुस्लिम पुरुष और महिलाएं इस हैशटैग का इस्तेमाल करने लगे और 24 घंटे के अंदर यह 2000 बार ट्वीट हो गया। यह फारसी ट्विटर पर टॉप 10 ट्रेंड में आ गया। ट्विटर पर अपना अनुभव शेयर करने वाली महिलाओं ने बताया कि उन्हें भीड़ में ग़लत तरीके से छुआ गया और पकड़ने की कोशिश की गई। मस्जिदों में महिलाओं के साथ हुए घटनाओं को उजागर करने वाले इस कैंपेन के लिए ट्विटर पर @reallyHibbs हैंडल से लिखा गया कि जब मैं जामा मस्जिद में गई तो एक व्यक्ति ने मेरी छाती पर हाथ मारने का प्रयास किया था। उस समय उन्होंने इस संबंध में किसी से भी बात नहीं की थी क्योंकि लोगों को उस समय लगता कि मैं इस्लामोफोबिया का समर्थन कर रही हूं।

इस्लामोफोबिया एक ऐसा शब्द है जिससे हर उस व्यक्ति को भयभीत किए जाने का प्रयास होता है जो इस्लाम की कट्टरपंथिता के खिलाफ कुछ बोलना चाहता है। यही वह हिचक है जो बुद्धिजीवियों को इस्लाम के कट्टरपंथ का विरोध करने से रोकती है, और यही वह हिचक है जो उन्हें रोकती है कि वे अपनी बात कह सकें। इस्लामोफोबिया शब्द को इजाद करने वाले लोग शायद यह जानते भी नहीं होंगे कि अनजाने ही सही उन्होंने मानवता को कितनी हानि पहुंचाई है। मगर अब लोग इस इस्लामोफोबिया होने के भय से बाहर आ रहे हैं और पूरे विश्व में स्त्रियाँ धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ अपना मुंह खोल रही है। ट्विटर पर @djenanggulo हैंडल के साथ एक महिला ने लिखा कि सऊदी अरब में स्थित मस्जिद नवाबी से कुछ फीट की दूरी पर ही एक व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया था।@NewtmasGrape हैंडल से लिखा कि जब वह मात्र 10 साल की उम्र में थीं तब एक मस्जिद में एक व्यक्ति ने पीछे से उनके अंगों को बुरी तरह से छुआ था । तो वहीं एक यूजर एंगी लेगोरियो ने ट्विट किया, मैंने #MosqueMeToo के बारे में पढ़ा। हज 2010 मैंने ऐसा कुछ देखा भी था। लोग सोचते हैं कि मक्का मुस्लिमों के लिए एक पवित्र जगह इसलिए वहां कोई कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है।

हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इसे केवल सस्ती लोकप्रियता कह रहे हैं। एल्ताहवी ने ट्विटर पर कहा कि जब उन्होंने पहली बार इस विषय में अपनी बात कही थी तो मुस्लिम महिलाओं ने उन्हें चुप रहने की सलाह दी या उनसे कहा कि इससे मुसलमानों को बुरा लगेगा। इसी तरह, सोशल मीडिया पर आलोचकों ने उन महिलाओं को सलाह दी है कि वे Mosquemetoo के झांसे में न आएं क्योंकि यह इस्लामोफोबिया या पश्चिमी प्रचार के उपकरण हैं। हालांकि इस अभियान के समर्थकों का कहना है कि मुस्लिम महिलाएं चुप नहीं रह सकती हैं और मुसलमानों को नकारात्मक छवियों से बचाने के लिए और दब कर नहीं रहा जा सकता है। (ट्विटर और इंटरनेट के स्रोतों के आधार पर)

मंदिरों में भी इस प्रकार के यौन शोषण की बातें अधिकतर उठती रहती हैं और यही कारण है कि अधिकतर मंदिरों और मस्जिदों में महिलाओं के लिए कुछ खास प्रकार के वस्त्रों को पहनने की हिदायत होती है, मगर क्या केवल वस्त्रों पर रोक लगाकर स्त्रियों के ऊपर होने वाले शोषण से बचा जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि इन स्थानों पर जहां स्त्री का ध्यान केवल और केवल अपने और अपने परिवार के कल्याण की तरफ होता है वहीं कुछ पुरुषों का ध्यान होता है, उनकी तरफ।

इसी प्रकार ईरान में जब इस्लामिक क्रान्ति का आगाज हुआ था तो उस क्रान्ति में मुस्लिम महिलाओं ने भी अपनी आवाज उठाई थी, मगर आज ईरान में जबरन थोपे हुए ड्रेस कोड अर्थात हिजाब के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। ईरान में हिजाब पहनने की अनिवार्यता के खिलाफ महिलाओं का विरोध बढ़ता ही जारहा है। महिलाएं सड़कों पर आ गई हैं और अपने हिजाब उतार कर फेंक रही हैं।तेहरान पुलिस ने 29 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है जो बिनाहिजाब पहने सार्वजनिक जगहों पर घूम रही थीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन महिलाओं का विरोध 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद महिलाओं के लिए लागू किए इस्लामिक ड्रेस कोड के खिलाफ था। महिलाओं नें अपने अपने हिजाब उतार कर सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर कीं। ईरान में यह विरोध आज की बात नहीं हैं, वहां पर अधिकतर ये विरोध होते रहते हैं क्योंकि वहां की स्त्रियाँ स्वभाव से मुखर होती हैं। आन्दोलन में शामिल महिला दंत चिकित्सक डॉ. समर कहती हैं, हर किसी को यह अधिकार होना चाहिए किवह क्या पहने और क्या नहीं? मुझे नहीं लगता कि सिर के खुले बाल किसी को उत्तेजित कर सकते हैं।

कुछ ऐसा ही विचार गाजियाबाद की महिला वकील शबनम के हैं, उनका कहना है कि आप किसी को कितना दबा सकते हैं, धर्म के नाम पर आप किसी को कितना नियमों में

बांधेंगे? जब शोषण की अधिकता होगी तो विरोध होगा ही।

क्या अंतर्राष्ट्रीय विरोध भारत को प्रभावित करेगा?

वैश्विक स्तर पर किया जा रहा यह विरोध कितना सार्थक होगा, यह तो समय के गर्भ में है। मगर यह तो बात सच है कि इस समय पूरी दुनिया में स्त्रियाँ बने बनाए नियमों के खिलाफ एक जंग लड़ रही हैं, वे इस जंग में खुद पर वार खाने से भी नहीं डर रही हैं। वर्णिका कुंडू को भी राजनीतिक रूप से या कहें नैतिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, मगर वह नहीं डरी। तीन तलाक के खिलाफ अपनी आवाजें उठाने वाली इशरत जहां पर तो उनकी बेटी के माध्यम से ही हमला हो रहा है। इशरत की किशोर बेटी के माध्यम से यह बात बार बार स्थानीय मीडिया कह रहा है कि कहीं न कहीं केवल और केवल इशरत की गलती है। इसी प्रकार जब मोना ने आवाज उठाई तो उन्हें इस्लामोफोबिया से पीड़ित बताया, यही नहीं आशाराम का विरोध करने वाली लड़कियों को भी समाज के विरोध का सामना करना पड़ा था। मगर फिर भी लडकियां खुद पर हुए शोषण का विरोध कर रही हैं, तमाम तरह के हैशटैग आ रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार का सहयोगी रुख भी इसमें जिम्मेदार है। नाम न छापने की शर्त पर एक स्थानीय मुस्लिम महिला ने कहा कि दीदी, जो भी दुनिया में हो रहा है, वह सही ही हो रहा है। हम खुद के बारे में लिए गए फैसलों से बहुत खुश हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए सही कदम उठाएगी।

> **इस्लामोफोबिया शब्द को इजाद करने वाले लोग शायद यह जानते भी नहीं होंगे कि अनजाने ही सही उन्होंने मानवता को कितनी हानि पहुंचाई है।**

शबनम का कहना है कि पूरे विश्व में होने वाली घटनाओं को मीडिया के माध्यम से हम औरतों के सामने लाया जाना चाहिए, जिससे हमें भी और बातें पता चल सकें। कायनात के अनुसार बदलाव की बयार को आप रोक नहीं सकते, मगर कैसा बदलाव, प्रश्न यहीं पर आएगा! पहचान के लिए स्त्रियों को केवल बुर्के और हिजाब में कैद कर देना बदलाव नहीं है, मगर लड़कियों को यही एक समय के बाद अच्छा लगने लगता है।

वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हमें स्त्रियों के विषय में सोचते समय धर्म को एक तरफ रख देना चाहिए। चाहे धर्म कोई भी हो कुरीतियाँ सभी धर्मों में स्त्रियों के लिए एक समान हैं। दहेज से होने वाली हत्याएं आज भी बदस्तूर जारी हैं, आज भी सम्मान के नाम पर लड़कियों को मारा जाना जारी है, तो धर्म से न जोड़कर हमें समस्याओं को केवल स्त्री के नजरिए से देखा जाना चाहिए। महिला की स्थिति हर धर्म की कुरीतियों से प्रभावित होती है, आंकड़े हर धर्म की औरतों के बारे मं निष्पक्ष बोलते हैं और वे अभी भी चीख चीख कर कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार और एक चुपचाप सी चली आ रही कुप्रथा महिलाओं के खतने के बारे में गवाही दे रहे हैं। स्त्रियां अभी भी खुद को एक वस्तु और उपभोग के रूप में न देखे जाने की लड़ाई लड़ रही हैं, वहीं यजीदी लड़कियां दुर्दांत आतंकियों से बचने के लिए खुद को आग के हवाले कर रही हैं। समय आ गया है कि स्त्रियों के वास्तविक मुददों को समझ कर आगे बढ़ा जाए और उनकी आवाज छद्म आंदोलनों की बलि न चढ़ जाए। उषा ठाकुर के ही शब्दों में कि हमें हिंदू और मुस्लिम या धर्म में न बांटें, औरतों का दर्द साझा है। ■

Subscription Request

DIALOGUE INDIA — डायलॉग इंडिया

Option	Period	Issues	Tick (✓) One	You Pay
1.	1 Year	12 issues		Rs. 360.00*
2.	2 Year	24 issues		Rs. 720.00*
3.	3 Year	36 issues		Rs. 1080.00*

*including Postal Charges

Yes, I would like to subscribe Dialogue India

Name : Mr/Ms

Address :

Pin

Ph (O) (R) E-mail

Please find enclosed DD / Pay Order / Cheque No. Drawn on bank

Dated For Rs. favouring 'Dialogue India' payable at Delhi.

Date

Please mail this form (or photocopy) with your remittance to:
Dialogue India 301/A-37-38-39, Ansal Building, Commercial Complex, Mukherjee Nagar, Delhi-110009, Ph. : 011-27652829, Fax : 27654568

Signature

व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की उपयोगिता बढ़ाने के पांच सूत्र

● अजय सिंह एकल

देश की उन्नति के लिए तमाम चिंताओं में एक चिन्ता व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की उपयोगिता एवं गुणवत्ता बढ़ाने की है। समय – समय पर इस के लिए प्रदेश एवं केंद्र सरकार के स्तर पर अनेक प्रयास हुए है इसमें कुछ सुधार भी हुआ है। अब तक जो हुआ है उसे और बेहतर करने हेतु निम्न सुझावों पर अमल करने से अच्छे परिणाम आ सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास है

1. पाठ्यक्रम उद्योगों की जरुरत पूरी करे

वर्तमान स्थिति

विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद् में उद्योग के ज्यादातर प्रतिनिधी होने वाली बैठकों में व्यस्तता के कारण अनुपस्थित रहते है अत: उनके द्वारा दिया जाने वाला मार्गदर्शन प्राय: मिल नहीं पाता। प्रतिनिधियों का चुनाव उनकी ब्रांड वैल्यू के आधार पर अथवा व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर किया जाता है। ज्यादातर प्रतिनिधी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी और उसके पूरा न होने से समाज के नुकसान के बारे में उदासीन रहते है। जिम्मेदारी स्वीकार करने का कारण व्यक्तिगत और संस्थागत ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का होता है। उसके पूरा न होने पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता इसलिए लोग पद स्वीकार करते है और समय की कमी का बहाना बना उससे बचते रहते है।

क्या करे

विद्वत परिषद् में चयन उनलोगों का हो जो उद्यमी हो और सामाजिक सरोकार जिनके जीवन का हिस्सा हो जो उसे रोज जीते हो। इस सम्बन्ध में खुला विज्ञापन दे कर निमंत्रित किया जाये। चयन समिति के लोग भी विद्वान् होने के साथ सेवाव्रती हो ताकि उनका किया चुनाव उद्देश्य की पूर्ति कर सके। प्रतिनधियों की कम्पनियो के नाम विश्वविद्यालय परिसर एवं वेब साइट पर प्रदर्शित हो और प्रतिनिधियों के योगदान की सराहना बार बार की जाये।
ऐसे उदयमी जिनके प्रतिनिधि अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो उन्हें सरकारी कामो में कुछ रियायतें भी दी जा सकती है। जैसे जमीन, बिजली इत्यादि में छूट अथवा अन्य प्रकार का लाभ दिया जा सकता है।

2 . अध्यापको को योग्य बनाना

वर्तमान स्थिति

आमतौर पर व्यसायिक एवं तकनिकी शिक्षा देने के लिए आने वाले अध्यापक किसी बेहतर विकल्प के न होने के कारण शिक्षक बनने का निर्णय करते है। अच्छे शिक्षक बनाने के लिए विषय की जानकारी के अलावा स्वप्रेरणा का अभाव ,पढ़ाने की आधुनिक तकनीक का प्रयोग न करना ,उद्योगों के साथ लगातार संपर्क न रखना एवं विद्यार्थियों के साथ ठीक सम्वाद स्थापित न कर पाने के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते है।

क्या करे

बीस से पच्चीस प्रतिशत अध्यापक उद्योगों से पढ़ाने के प्रतिनियुक्ति पर आये तो उद्योग एवं शिक्षण संस्थान का लगातार संपर्क रहेगा। उद्योगों में आने वाले परिवर्तन अथवा नयी मांग के अनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करना संभव हो सकेगा। उद्योगों में काम करने वाले लोगों की और शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले लोगो के वेतन में अंतर को उद्योग अपने सी एस आर फंड्स से पूरा कर सकते है। अथवा उद्योगों के लिए अनुसंधान शिक्षण संस्थाओं में हो और प्रति नियुक्ति पर आये हुये लोग अनुसन्धान के प्रबंधन का काम भी करे तो उद्योग अतरिक्त खर्च को अपने वार्षिक लाभ हानि के साथ समाहित कर सकेंगे.

अन्य अध्यापको के लिए छह माह में तीन-पाँच दिन की आवश्यक ट्रेनिंग की व्यवस्था हो जो उसके विषय के अतिरिक्त अन्य कुशलताओं के लिए हो।

3. विद्यार्थियों की योग्यता एवं झुकाव का आकलन

वर्तमान स्थिति

किसी विषय में प्रवेश अभी प्रवेश परीक्षा का प्राविधान है इसको पास करने से योग्यता के अनुसार कालेज में चयन होता है। लेकिन इसके बाद सिवाय विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार विशेष योग्यता का विषय चुन सके और कोई तरीका नहीं है। ज्यादातर केस में विषय रुचि के बजाय या तो माता पिता ,बड़े भाई- बहन,मित्र या परिवार में चल रहे व्यापार की जरूरतों को ध्यान में रख कर विषय का चुनाव होता है। बहुत से उद्धरण ऐसे है जिनमें माता पिता डॉक्टर होने के कारण बच्चे को डॉक्टर ही बनाना चाहते है जबकि बच्चे में इस विषय के लिए न तो योग्यता होती है न रूचि। परिणाम स्वरुप बच्चा विषय में प्रवेश लेकर भी कुछ खास उपलब्धि नहीं करता इस कारण कई बार तो आत्महत्या तक की नौबत आ जाती जाती है। भारत का दुनिया के देशों की लिस्ट में प्रसन्नता सूचकांक 2016 के अनुसार 170 वा नंबर है इसकी एक वजह व्यक्ति का अपनी योग्यता एवम रूचि के स्थान पर न पहुँच पाना भी है।

क्या करे

अब टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका समाधान उपलब्ध है। 12वी कक्षा की परीक्षा के साथ ही झुकाव का ज्ञान होना विद्यार्थी, अभिभावक एवं समाज के लिए बहुत उपयोगी होगा। अत:

वेंटिलेटर पर देश के तकनीकी संस्थान व शिक्षा

युं तो यह खबर उत्तर प्रदेश की है कि वहाँ के 32 इंजनियरिंग व मैनेजमेंट कॉलेज बंद हो रहे हैं, मगर कुछ ऐसी ही खबर देश के प्रत्येक राज्य में छप रही हैं। इसवर्ष एआईसीटीई से सम्बद्ध 10,300 कॉलेजो में से दस प्रतिशत यानि एक हजार से ज्यादा बंद हो रहे हैं। डायलॉग इंडिया ने अपने निजी संस्थानों के वार्षिक सर्वेक्षण : 2017 में यह खुलासा किया भी था कि अगले चार वर्षों में आधे से ज्यादा तकनीकी संस्थान बंद होने वाले हैं। सच्चाई यह है कि देश के लगभग 4000 तकनीकी शिक्षा संस्थान बंद होने के कगार पर है किंतु उनमें पढ़ रहे प्रथम , द्वितीय व तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का कोर्स बाकी है, इसलिए एकदम से बंद नहीं कर सकते। फिर सवाल सरकार की इज्जत का है। ऐसा इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व रोजगार न दिला पाने के कारण भी हो रहा है। (देश के निजी विश्विद्यालयों ने भी परिदृश्य बदला है और इनमें से 5 लाख सीटे के भागीदार वे भी हैं और 2 से 3 लाख रोजगार भी।) वहाँ भी दिए जाने वाले रोजगार के मुकाबले दुगनी सीटें उपलब्ध हैं। एआइसीटीई खुद मानती है कि उससे संबद्ध संस्थानों में 37 लाख सीटें है किंतु प्रवेश केवल 20 लाख ही हो पाते हैं। ये भी माल कमाने के लालच में बच्चो व माता पिता को बहला फुसला कर, सब्जबाग दिखलाकर। इसी कारण अयोग्य विद्यार्थी प्रवेश तो ले लेता है किंतु कुछ समय बाद ही पढ़ाई छोड़ देता है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 7 लाख प्रतिवर्ष है यानि कुल प्रवेश का 35 प्रतिशत। अंदाजा लगाइए कितने बड़े सुनियोजित धोखे व लूट होती हैं नयी पीढ़ी के साथ। जैसे तैसे जो 13 लाख लोग डिग्री ले भी पाते हैं उनमें से आधे यानि 6 से 7 लाख नौकरी लायक नहीं होते और बेरोजगार रह जाते हैं। जिन 6-7 लाख विद्यार्थियों को नौकरी मिलती भी है उनमें से 1 से 2 लाख ही जॉब सेटिस्फेक्शन महसूस कर पाते है और बाकी कुढ़ते जलते संघर्ष करते रहते हैं। यह सरकारों के नीतिकारों पर बड़ा प्रश्नचिन्ह है कि जब देश को 6 से 7 लाख ही इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट पास लोग चाहिए तो 37 लाख सीटों का ढांचा जो लाखों करोड़ रुपये खर्चकर क्यों तैयार किया गया? फिर इतने संसाधनों व समय, धन व युवाओं की ऊर्जा क्यो बर्बाद की जा रही है? किसकी जबाबदेही है इस सुनियोजित सिंडिकेट की लूट व षड्यंत्र की? मजेदार बात यह है कि देश के हर नेता, नौकरशाह, उद्योगपति व व्यापारी की इन संस्थानों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पत्ती यानी हिस्सेदारी है। कितनी हास्यास्पद बात है कि हमारे देश मे एक करोड़ लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और देश का दो तिहाई हिस्सा आज भी अत्यधिक पिछड़ा है। बिना शिक्षा के भारतीयकरण के शोध, इन्नोवेशन, इंट्रप्रेनेरशिप, औद्योगिकरण के अभाव के आयात आधारित अर्थव्यवस्था का यही हाल होना ही है। मोदी सरकार लाख मेक इन इंडिया का घंटा बजाती रहे।

अनुज अग्रवाल

32 इंजीनियरिंग कॉलेजों का बंद करने के लिए आवेदन

उत्तर प्रदेश में 32 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने इस बार बंद करने के लिए अपना आवेदन किया है। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) से संबद्ध इन इंजीनियरिंग व मैनेजमेंट कॉलेजों ने विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम होने के कारण यह कदम उठाया है। फिलहाल एकेटीयू जल्द ही कॉलेजों को बंद करने का प्रस्ताव शासन को भेजेगा। इसमें से दो इंजीनियरिंग कॉलेज राजधानी के भी हैं। यूपी में जिन 32 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने बंद होने के लिए आवेदन किया है उनमें लखनऊ के ज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी व अंसल टेक्निकल कैंपस शामिल हैं।

वहीं हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आगरा, तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, आइईसी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट गौतमबुद्ध नगर, दीन दयाल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट मुजफ्फरनगर, रामा इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, राजकुमार गोयल इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, सुंदर दीप कॉलेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गाजियाबाद, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाजियाबाद, गाजियाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, रुड़की इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मुजफ्फरनगर, बून महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज मथुरा, विद्या भवन कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, वूमेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीतापुर, ट्रीडेंट एजुकेशन ट्रस्ट ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशन फैकल्टी आफ इंजीनियरिंग गाजियाबाद, एचआर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज गाजियाबाद, महाराजा अग्रसेन कॉलेज बरेली, एशियन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट सहारनपुर, शाकम्बरी कॉलेज सहारनपुर, इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज सहारनपुर, संस्कृति इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी मथुरा, एचआर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गाजियाबाद, आइडियल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, साईं एजुकेशन मेरठ, जीएनआइटी मैनेजमेंट स्कूल, संस्कृति स्कूल आफ बिजनेस मथुरा, संस्कृति इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट मथुरा और संस्कृति इंजीनियरिंग कॉलेज मथुरा शामिल हैं। फिलहाल अब एकेटीयू 32 कॉलेजों द्वारा बंद किए जाने को लेकर भेजे गए प्रस्ताव को शासन को भेजेगा और फिर इस पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।

इसका प्रबंध करना चाहिये। तत्पश्चात व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा के बाद जब प्रवेश मिलजाए तो फिर प्रतिवर्ष रुचि जानने का प्रबंध करने से विद्यार्थी की पूरी क्षमता का विकास भी होगा और उसकी प्रतिभा का लाभ व्यक्तिगत एवं समाज को मिल सकेगा। धीरे धीरे योग्य व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार व्यावसायिक स्थानों पर पहुंच कर अचंभित करने वाले कार्य कर सकेंगे। ऐसे टेस्ट जो रुचियों को बता सके और व्यक्तिगत क्षमताओ का सही आकलन कर के दिशा दे सके अब देश में उपलब्ध है और इनका व्यापक प्रयोग किये जाने की जरुरत है।

इस विधा का उपयोग यदि और अधिक आक्रामकता के अनुसार नियोजित करे तो यह टेस्ट 2-3 साल की आयु से शुरू होकर हर तीन साल पर होने चाहिये। यह बच्चों की रूचि और योग्यता के अनुसार अवसरों के उपयोग करना सुनिश्चित करेगा। इससे बच्चों के भविष्य की दिशा शुरू से निश्चित हो सकेगी और उस पर ठीक से काम हो तो इंजीनियरिंग ,मेडिकल ही नहीं ओलम्पिक के लिए भी प्रतिभा की खोज करना सम्भव होगा और 15-20 वर्षो के बाद की विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में देश अपना स्थान बनाने में सफल हो सकेगा।

4 . देश सेवा के लिए विशेष प्रशिक्षण

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में एन सी सी और एन एस एस जैसी ट्रेनिंग कुछ स्कूल एवं कालेजों में करवाई जा रही है। यह अनिवार्य न होकर ऐच्छिक है। इसको करने वाले बच्चों को कही -कही वरीयता भी मिलती है , लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।

क्या करे

सरकारी अध्यादेश निकाल कर जो लोग सरकारी नौकरी में जान चाहते है उनके लिए कम से कम तीन माह की ट्रेनिंग किसी आर्मी की ट्रेनिंग जैसी करवानी चाहिये जो इनकी दिमागी स्थित को मैं , मेरा, मुझे से हटा कर देश और समाज की समझ एवं हम उसका हिस्सा है इसलिए इससे केवल लेने की बात न सोच कर मुझे देश समाज को कुछ देना चाहिये इस विचार को मन में जगह दे सके तो वर्तमान नजरिये में परिवर्तन संभव हो सकता है। इसके शुभ परिणाम 3-5 वर्षों में आने की सम्भावना रहेगी।

5. स्थानीय उद्यमों में रूचि उत्पन्न करना

वर्तमान स्थिति

व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को पूरा करने के लिए तीन से छह माह का प्रशिक्षण किसी उद्यम अथवा व्यसायिक प्रतिष्ठान में जा कर करना होता है। वस्तुस्थित यह है कि ज्यादातर बच्चे तो बिना वहां गए ही सर्टीफिकेट प्राप्त करलेने की कोशिश करते है। कुछ लोगो ने इसे व्यवसाय बना लिया है जो फीस लेकर कुछ सीखा देते है और इससे परीक्षा की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। परन्तु जिस कारण से यह नियम पूर्व में बनाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति न हो कर महज खाना पूर्ति होती है।

व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी इसमें बहुत ज्यादा रुच नहीं दिखते है क्योकिं उन्हें पता है की इस सामाजिक दाईत्व को पूरा न करने का न तो कोई सामाजिक प्रतिष्ठा पर और न ही आर्थिक लाभ पर कोई असर पड़ने वाला है इसलिये इसको अनदेखा करने की प्रवृत्ति रहती है।

क्या करे

विद्यार्थियों एवं अध्यापको के लिए यह आवश्यक हो कि पूरे पाठ्यक्रम की अवधि में एक बार टीम माह अथवा छह माह के स्थान पर हर साल कम से कम छह से आठ सप्ताह किसी एक उद्यम अथवा प्रतिष्ठान से जुड़ना अनिवार्य हो। और जुड़ने से उद्यम को गुणवत्ता अथवा वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ अथवा तकनीक सुधार इत्यादि का लाभ सुनिश्चित करना चाहिए तो काम करने वाले विद्यार्थियों और अध्यापको एवं उद्यम तीनो के लिए लाभ की स्थिति बन सकती है और इसमें उनकी रूचि सुनिश्चित हो जाएगी. यह स्थानीय कालेजों के द्वारा स्थानीय उद्यमों के लिए हो तो अपने पास की चीजों की परवाह करने का मनोभाव बनेगा। और केवल जहाँ है वहां की परवाह न करने की आदत से छुटकारा मिलेगा। फाइनल परीक्षा में उद्यम से जुड़े हुए व्यसाइयों के द्वारा दी गई राय एवं अंक को 50प्रतिशत वेटेज दिया जाने से विद्यार्थी ,अध्यापक एवं उद्यम तीनो संजीदा रहेंगे और जिम्मेदारी का एहसास होगा।

इस तरह से उद्यम को होने वाले अतरिक्त आय में इन विद्यार्थियों एवं अध्यापकों पर होने वाले व्यय को समाहित किया जा सकता है ताकि उनपर अतरिक्त आर्थिक बोझ का नुकसान न हो। आवश्यक होने पर कार्य कर रहे अध्यापकों के अलावा अवकाश प्राप्त लोगों का सहयोग लेने से उनके लिए भी समाज में अपने योगदान का फक्र होगा व्यस्त रहने से स्वस्थ एवं मानसिक स्थिति भी बेहतर रहेगी।

शिक्षा : वैश्विक सूची में भारत नदारद ?

● राकेश दुबे

एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग सूची 2018 में भारत के लिए कुछ सुखद संकेत मिले हैं। 350 विश्वविद्यालयों की इस सूची में भारत के 42 विश्वविद्यालयों को इस बार स्थान मिला है। रैंकिंग के 13 आधारों में से 12 पर भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी स्थिति बेहतर बनाई है। विश्व स्तर पर विश्वविद्यालयों की रैंकिंग ऐसा मुद्दा है, जिसके भारत जैसे विकासशील देशों को होने वाले नफा-नुकसान पर बहुत तीखी बहस होती है। विश्व स्तर पर इन रैंकिंग को चलाने वाली तीनों एजेंसियां विश्व के श्रेष्ठतम 500 से 1000 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग हर साल जारी करती हैं। अक्सर इन रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की अनुपस्थिति से हमारी उच्च शिक्षा के बारे में निराशा का दौर शुरू हो जाता है।

वैश्विक रैंकिंग में इस बार चीन की शिंहुआ यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर और पीकिंग यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर आई हैं। क्या कारण है कि चीन के विश्वविद्यालय, जो 1950 तक भारतीय विश्वविद्यालयों से पीछे थे, 21 वीं सदी में काफी आगे

निकल गए? क्या भारतीय विश्वविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के लिए जरूरी मानकों के प्रति जागरूकता का अभाव है? क्या हमारी उच्च शिक्षा सिर्फ कक्षा और परीक्षा तक सिमटकर रह गई है, और शोध व अनुसंधान में हम फिसड्डी बनते जा रहे हैं?

रैंकिंग में भारत और चीन की तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन करें, तो वे कारण मालूम पड़ सकते हैं, जो चीन की तुलना में भारतीय विश्वविद्यालयों की खराब स्थिति के लिए उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। यह रैंकिंग सूची भी 13 मानकों के आधार पर तैयार की जाती है, जो मोटे तौर पर शिक्षण,रिसर्च, रिसर्च की उत्पादकता, अंतरराष्ट्रीयकरण और यूनिवर्सिटी को उद्योगों से ज्ञान के हस्तांतरण से होने वाली आय से जुड़े हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों के पिछड़ेपन का एक मुख्य कारण प्रकाशित शोध-पत्रों का अच्छा साइटेशन न होना है। यानी प्रकाशित शोध-पत्र को विश्व स्तर पर कितनी बार दूसरे शोधकार्यों में उद्धृत किया जाता है।

भारतीय विश्वविद्यालयों को यह सोचना चाहिए कि आखिरकार वे क्या कारण हैं कि शिक्षाविद्, शिक्षक और शोध-छात्र विश्वस्तरीय रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमारे शिक्षक, शोध-छात्र, प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय विश्वस्तरीय अनुसंधानों को संचालित करने के लिए सक्षम हैं? क्या विश्वस्तरीय शोध-कार्यों के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा विश्वविद्यालयों को समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं? क्या हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों के समुदायों में देश-विदेश का समुचित प्रतिनिधित्व रहता है या हम क्षेत्रीयतावाद के शिकार हैं? क्या हम विश्वस्तरीय सम्मेलनों और कार्यशालाओं में अपने शिक्षकों व शोध-छात्रों को समुचित संख्या में भेज पाते हैं? इन सवालों के ठोस हल ढूंढे बिना भारतीय विश्वविद्यालयों से विश्वस्तरीय प्रतिष्ठा या रैंकिंग पाने की अपेक्षा करना बेमानी होगा।

सही मायने में भारत को विश्वव्यापी ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी के लिए कुछ विश्वविद्यालयों को शोध-विश्वविद्यालय का दर्जा देना होगा। अमेरिका, जर्मनी व जापान की औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं की सफलता का राज विश्वविद्यालयों के संचालन का हुम्बोल्ट मॉडल है। हुम्बोल्ट मॉडल के विश्वविद्यालय नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद की बजाय गुणवत्ता के सिद्धांत का अक्षरश: पालन करते हैं।

वर्ष 2016 के केंद्रीय बजट में 20 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई थी। पिछले साल मानव संसाधन मंत्रालय की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इसके नए रेग्यूलेशंस को स्वीकृति मिली है। इनका नाम अब वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से बदलकर 'इंस्टीट्यूट ऑफ ऐमीनेंस' कर दिया गया है। आवेदनकर्ता विश्वविद्यालयों में कम से कम 15 हजार विद्यार्थी पढ़ रहे हों और शिक्षक व विद्यार्थी का अनुपात 1:15 हो। इन संस्थानों को यूजीसी के शिकंजे से मुक्त कर अधिकतम स्वायत्तता दी जाएगी। इसी प्रकार वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भी 'प्रधानमंत्री रिसर्च फैलोज' योजना घोषित की गई है। इन सबके परिणाम प्रतीक्षित हैं।

भारतीय स्नातकों का रोजगार स्तर सुधार की ओर

● **राकेश दुबे**

ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज और यूनाइटेड नेशंस डिवेलपमेंट प्रोग्राम जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के अलावा दो स्वतंत्र एजेंसियों पीपलस्ट्रांग और वीबॉक्स के संयुक्त सर्वेक्षण का निष्कर्ष है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के नए स्नातकों में रोजगार योग्यता (इम्प्लॉएबिलिटी) ठीक-ठाक बढ़ी है। यह सर्वेक्षण 120 कंपनियों और 510000 छात्रों के बीच किया गया। रोजगार योग्यता या नियोजनीयता मैनेजमेंट की भाषा में हाल में ही शामिल हुई एक अवधारणा है।

1997में सबसे पहले सुमंत्र घोषाल ने इसे पेश किया था। इसका अर्थ है मूल्य उत्पादक कार्य करना, इसके जरिए धन अर्जन करना और काम करते हुए अपनी क्षमता बढ़ाना ताकि भविष्य में और बेहतर काम मिल सके। भारत में तकनीकी शिक्षा को छोड़कर बाकी अनुशासनों को इसके दायरे से बाहर माना जाता था। यानी इनसे आए ग्रैजुएट सरकारी नौकरियों के सांचे में भले ही फिट हो जाएं, पर उत्पादक कार्यों के लिए वे उपयोगी नहीं होते। बहरहाल, यह सर्वेक्षण बताता है कि अभी हर तरह के स्नातकों में कॉरपोरेट नौकरियों के लायक योग्यता पैदा हुई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल इसमें काफी वृद्धि देखी गई है। जैसे, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में2015-16 इम्प्लॉएबिलिटी 41.69 प्रतिशत थी, 2016-17 में 50.69 प्रतिशत थी, जो 2017 -18 में 51.52 प्रतिशत हो गई। फार्मास्युटिकल्स में यह पिछले साल 42.3 प्रतिशत थी, जो इस साल 47.78 प्रतिशत हो गई। सबसे आश्चर्यजनक उछाल कंप्यूटर ऐप्लिकेशंस में देखा गया, जहां यह 31.36 प्रतिशत से बढ़कर 43.85 प्रतिशत हो गई। बीए में यह 35.66 प्रतिशत थी जो 37.39 प्रतिशत हो गई। एमबीए और बीकॉम की रोजगार योग्यता में गिरावट आई है। इसमें उछाल 2014 से आना शुरू हुआ, जब यह कुल मिलाकर 34 प्रतिशत से 46 प्रतिशत पर पहुंच गई थी।

सर्वे बताता है कि हर दो नए स्नातकों में से एक रोजगार देने लायक है। इंजीनियरों के बारे में रतन टाटा ने कहा था कि उनमें ज्यादातर रोजगार के लिए अपेक्षित पात्रता नहीं रखते, लेकिन इस सर्वे के अनुसार उनमें से 52 प्रतिशत रोजगार के लायक हैं। सर्वेक्षणकर्ताओं का मानना है कि इधर कई संस्थानों ने बदलते वक्त को पहचान कर अपने कोर्सेज का ढांचा बदला है,इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा है और अपने स्टूडेंट्स को एंप्लॉएबल बनाने के लिए लीक से हटकर प्रयास किए हैं। इससे सरकार के सामने चुनौती भी बढ़ गई है, क्योंकि एक निपुण वर्कफोर्स बेरोजगारी को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाएगी। फिर भी बहुत खुश नहीं होना चाहिए यह प्रतिशत और सुधरना चाहिए।

इनोवेशन एण्ड एन्टरप्रेन्यॉरशिप डेवलपमेंट सेंटर से स्वरोजगार स्थापित करेंगे जीएलए के छात्र

[illegible]

सेन्टर का शुभारंभ करते हुए कुलाधिपति नारायण दास अग्रवाल ने बताया कि आम आदमी की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने एवं स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जीएलए के छात्रों द्वारा 'इनोवेशन एंड एन्टरप्रेन्यॉरशिप डेवलपमेंट सेन्टर न्यूजैन (आईईडीसी) प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए विभिन्न संसाधन छात्रों को उपलब्ध कराये गये हैं। जिसकी तय समय सीमा पांच वर्ष रखी गयी है।

कुलपति प्रो. दुर्ग सिंह चौहान ने कहा कि रोजगार और स्वरोजगार में बहुत अंतर है। उद्यमिता वहां शुरू होती है जहां हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। खासकर हमारे गांवों में नवोन्मेष की जरूरत है। भारत में जन्मे छात्र तो विश्व के विभिन्न हिस्सों में पहुंच गए हैं। भारत में उत्पादित चीजों को विश्व में पहुंचाना है। जो अनंत ज्ञान हमारे देश के युवाओं में है वो सिर्फ देश तक ही सीमित न रहकर विश्व में जन-जन तक पहुंचे।

न्यूजैन आईडीसी के मुख्य समन्वयक एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. मनोज चौबे ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने करीब तीन करोड़ की धनराशि तय की है, जिसमें से कुछ धनराशि जारी हो गई है। इस प्रोजेक्ट को बीटेक, बीबीए, एमबीए, एमटेक, बीसीए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के छात्रों द्वारा तैयार किया जा रहा है। इससे पहले छात्रों को प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा छात्रों को जरूरतमंद पहलुओं से अवगत कराया गया है।

इस मौके पर प्रतिकुलपति प्रो. आनंद मोहन अग्रवाल, निदेशक प्रो. अनूप कुमार, कुलसचिव अशोक कुमार सिंह, प्रमोद जोशी, प्रो. अनिरूद्ध प्रधान, प्रधानाचार्य डॉ. विकास षर्मा, डॉ. दिवाकर भारद्वाज आदि उपस्थित रहे।

भारत बुनियादी अनुसंधान के क्षेत्र में शीर्ष स्थल के देशों में से एक है। अब समय आ गया है कि भारतीय विज्ञान विशेष रूप से उभरते परिदृश्य और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में वृद्धि और विकास के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक माना जाए। यह हमारे लिए आवष्यक है। भारत की अर्थव्यवस्था को बनाये रखने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने देष के नामचीन संस्थानों के छात्रों को प्रोजेक्ट के माध्यम से स्वरोजगार बनने का मौका दिया है। इसके लिए जीएलए विश्वविद्यालय, मथुरा में ''इनोवेशन एण्ड एन्टरप्रेन्यॉरशिप डेवलपमेंट सेंटर' का फीता काटकर शुभारंभ कुलाधिपति नारायण दास अग्रवाल ने किया।

प्रतिवर्ष 20 छात्र करेंगे प्रोजेक्ट पर कार्य

'इनोवेशन एंड एन्टरप्रेन्यॉरशिप डेवलपमेंट सेन्टर न्यूजैन (आईईडीसी) प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को मौका मिलेगा। प्रतिवर्ष प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए 20 छात्रों को चयनित किया जायेगा। हर छात्र अपने आइडियाज के द्वारा इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर स्वरोजगार स्थापित करेंगे और अन्य छात्रों को रोजगार देने में अहम भूमिका निभाएंगे।

[illegible]

कमांडर
वीके जेतली
शैक्षिक एवं प्रेरक वक्ता

आंतरिक बनाम बाहरी बाधातत्व

एक बार ट्रैकिंग के दौरान एक बहुत ही छोटा कंकड़ मेरे दाहिने जूते में घुस गया और मेरे लिए चलना एकदम नामुमकिन हो गया। वह ढाबा जहां हमें दोपहर के भोजन के लिए रुकना था, शायद100 मीटर हीदूर था। मैंने इस छोटे से कंकड़ के साथ ही उस सौ मीटर का सफर तय करने का सोचा, मगर मैं कुछ कदम भी नहीं चल सका। चावल के आकार जितना छोटा कंकड़ मेरे चलने में इतनी परेशानियां ला रहा था कि मेरे पास रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं और मेरी टीम के तीन सदस्य रुके जिससे मैं अपने जूते से उस नन्हे अपराधी को बाहर फेंक सकूं। हमने फिर से कंकड़ और पत्थरों से भरे उस रास्ते पर सफर शुरू कर दिया, जिनमें कई पत्थर तो उससे बहुत ही बड़े थे, मगर सौभाग्य से, हमें किसी और समस्या का सामना नहीं करना पड़ा और हम बहुत ही जल्द मुंह में पानी लाने वाले भोजन के लिए ढाबे तक पहुँच गए।

पेट में भरपूर भोजन के बाद मेरा दिमाग फिर से उसी छोटे कंकड़ की तरफ मुड़ गया, जिसने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया था जबकि संख्या में अधिक बड़े और बहुत नुकीले पत्थर ऐसा करने में असफल रहे। हैरानी की बात है, बड़े पत्थर उस छोटे कंकड़ के मुकाबले एकदम बेकार/अर्थहीन से रहे थे। इसी तरह किसी भी संगठन में हमारे आसपास कई लोग होते हैं जो हमेशा परेशानी ही पैदा करते रहते हैं। जो संगठन के बाहर हैं और आपके लिए बाधा पैदा कर रहे हैं उनसे निपटना आसान होता है, उन लोगों से निपटने की तुलना में जो संगठन के अंदर बैठे हैं। मेरे अनुसार यह नियम सामान्य रूप से सभी संगठनों और सभी स्तरों के लिए सच है।

मुझे यह मानने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं अपने प्रधान मंत्री का बहुत बड़ा प्रशंसक तब से हूँ जब से वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसलिए, जब वह प्रधान मंत्री बने, मुझे बहुत खुशी हुई कि भारत को एक महान नेता मिला है। एक नेता जो मुख्य रूप से ईमानदार है और जिसका दिल अपने देश के करोड़ों नागरिकों के लिए धड़क रहा है, उसके पास उन सब समस्याओं के प्रति एक स्पष्ट सोच है जो हमारे देश को परेशान कर रही हैं, और उनके बड़े से बड़े आलोचक भी काम के मामले में उनकी तारीफ करते हैं।

मगर अब अगर मैं उनसे पूछूं कि आखिर चार वर्षों के अंत में आकर वे कैसा महसूस करते हैं, तो उनका भी जबाव यही होगा कि उन्हें कंकडों से निपटने में बहुत समय लग जाता है। कंकड़ जो समय समय पर पैदा हो जाते हैं और उनके बढ़े कदमों को रोकने के लिए तैयार होते हैं। मोदी जी बाहरी एजेंसियों द्वारा पैदा की गयी सभी समस्याओं का प्रबंधन कर सकते हैं या कभी-कभी उन्हें अनदेखा भी कर सकते हैं। लेकिन अंदरूनी सूत्रों द्वारा बनाई गई समस्याओं के बारे में क्या? अंदरूनी सूत्र जो घोंघे की गति से ठेठ बाबू शैली में काम करते हैं और मोदी के कामकाज के साथ कदमताल करने के लिए तैयार नहीं हैं।

मोदी को एक ऐसी व्यवस्था विरासत में मिली है जो 1947 से इस तरह से काम कर रहे हैं। इस बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करना असंभव है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ 20प्रतिशत लोगों के साथ ही काम करना है और इसी के साथ उन्हें आलसी 80प्रतिशत की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसे लोगों की एक टीम की जरूरत है, जो 80/20 वाले अनुपात को 80 प्रतिशत काम करने वाले और 20 प्रतिशत आलसी में बदल सकें। इसी तरह, बाजार में प्रतिद्वंद्वियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से पहले, किसी भी नए सीईओ पर अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए काफी तनाव होता है।

अगर हम दुनिया के इतिहास या यहां तक कि भारत में थोड़ा पीछे हटते हैं, तो यह उन कहानियों से भरा है जहां कुछ अंदरूनी सूत्र साम्राज्य के पतन या राज्य के लिए जिम्मेदार थे। रावण की लंका के पतन के लिए विभीषण को अंदरूनी सूत्र माना जा सकता है, राजा अंबिसार सिकंदर के पक्ष में हो गए जिसके परिणामस्वरूप पोरस की हार हुई और इसी प्रकार जयचंद दिल्ली में अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान की हार के लिए जिम्मेदार बना. मीर जाफर एक अंदरूनी सूत्र ही था जिसने बंगाल के नवाब सिराज-उद-औला के खिलाफ अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी।

यह महत्वपूर्ण है कि हम एक राष्ट्र के रूप में, एक संगठन के रूप में या एक समाज के रूप में मजबूत हों जहां सभी अंदरूनी तत्व एकजुट हों और अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ बुने हुए हों। वे एक सामान्य लक्ष्य को समझते हों और इतना एक दुसरे को जानते हों कि उनमें से कोई भी बाहरी लोगों के साथ मिलकर अपने लोगों के प्रति घात करने की हिम्मत न कर सके। इस तरह के राष्ट्र, संगठनऔर समाज इस दुनिया के इतिहास में महान स्थान धारण कर लेतेहैं। हमें अपनी आंतरिक कमजोरियों को बाहर निकाल कर शारीरिक, मानसिक और यहां तक कि आध्यात्मिक स्तर पर मजबूत होना होगा। तो बाहर की सेना हमें क्षति पहुंचाने या हमें नष्ट करने की हिम्मत नहीं करेगी। यहाँ तक कि एक आदमी भी केवल बाहरी वायरस के आक्रमण के कारण ही बीमार पड़ता है, और इसके साथ ही जब हमारी आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली बाहरी वायरस से लड़ने में कमजोर हो जाती है, तो हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आइए हम अपनी आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि बाहरी वायरस के किसी भी हमले को तुरंत पलट दिया जाए और हम हमेशा ही सेहतमंद बने रहें।

यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने संगठन के लोगों पर ध्यान केंद्रित करें। सुनिश्चित करें कि वे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से परे होकर संस्थान की निरंतर वृद्धि के लिए सोच सकें। कोई भी बाहरी प्रोत्साहन या कोई भी बड़ी राशि उन्हें उनके कदमों से डिगा न सके।

याद रखें कि बाजार में उपलब्ध जूते आपको आराम से सडकों पर और यहाँ तक कि पहाड़ी क्षेत्रों पर भी जाने में मदद करेंगे, मगर यदि आपके जूते में एक छोटा सा कंकड़ भी घुस गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको रुकना होगा, उस छोटे कंकड़ को हटाना होगा और फिर ही आप अपनी आगे की यात्रा को पूरा कर पाएंगे।

लेखक एक प्रेरक वक्ता, एक सलाहकार, एक कोच और एक लेखक है और उनसे jaitly.iit@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है ■

उपभोकता जागरूकता से ही बदलेगी स्वास्थ्य सेवा की तस्वीर

● आशुतोष कुमार सिंह

अपने अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति जागरुक समाज ही खुद को बेहतर तरीके से विकसित कर सकता है। इस दिशा में भारत भी अग्रसर है। सभी क्षेत्रों के साथ-साथ अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरुकता बढ़ने लगी है। सरकारी-गैरसरकारी दोनों स्तरों पर भरपूर काम हो रहे हैं। इस आलेख का विषय है स्वास्थ्य क्षेत्र में उपभोक्ता जागरुकता। सबसे पहले हम जागरुकता शब्द को समझने का प्रयास करते है-

जागरुकता से अभिप्राय

जागरुकता शब्द प्रयोग करते ही दो प्रमुख बाते सामने आती है। जो हम खरीद रहें हैं, उसको लेकर हम कितने जागरुक हैं दूसरी बात यह कि खरीदने के बाद गर धोखाधड़ी के शिकार होते हैं तो इसके खिलाफ फरियाद करने का कोई अधिकार हमें हैं या नहीं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो खरीदार हैं वो उपभोक्ता है और जो बेच रहा है वो विक्रेता। ऐसे जब हम उपभोक्ता जागरुकता की बात करते हैं तो दो पक्ष सामने आते हैं एक खरीदने वाला और दूसरा बेचने वाला। ऐसे में उपभोक्ता वह व्यक्ति है, जो वस्तुओं अथवा सेवाओं को अपने अथवा अपनी ओर से अन्य के प्रयोग अथवा उपभोग के लिए खरीदता है। वस्तुओं में दैनिक उपभोग की तथा स्थायी वस्तुए सम्मिलित है। जबकि सेवाएं जिनके लिए भुगतान किया जाता है, में यातायात, बिजली, फिल्म देखना इत्यादि शामिल हैं। दूसरे अर्थों में उपभोक्ता को इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति, जो वस्तुओं एवं सेवाओं का चयन करता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए पैसा खर्च करता है तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उनका उपयोग करता है उपभोक्ता कहलाता है। भारत में उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण देने के लिए 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 लेकर आई। उपभोक्ताओं के अधिकार देने के संबंध में यह अधिनियम मिल का पत्थर साबित हुआ। इस कानून ने उपभोक्ताओं को अपने अधिकार के प्रति जागरुक करने का काम किया। बाद में सरकार के स्तर पर भी जागो ग्राहक जागो कैंपेन शुरु किया गया। जिसके तहत सरकार ने प्रिंट, श्रव्य एवं दृश्य माध्यमों से लोगों को उनके अधिकारों में बारे में जागरुक करना शुरू किया।

स्वास्थ्य सेवा एवं उपभोक्ता संरक्षण

आयुर्वेद की जननी भारत भूमि का इतिहास बताता है कि यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को प्राचीन काल में परोपकार के नजरिए देखा जाता था। जब तक वैद्य परंपरा रही तब तक मरीज एवं वैद्य के बीच सामाजिक उत्तरदायित्व का बंधन रहा। लेकिन आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था के उदय के बाद चिकित्सा एवं इससे जुड़ी हुई सेवाओं को क्रय-विक्रय के सूत्र में बांध दिया गया। चिकित्सकीय सेवा देने वाले एवं मरीज के बीच में उपभोगीय समझौते होने लगे। जैसे अगर आपको हर्निया का ऑपरेशन कराना है तो इतना हजार रुपये लगेगा, डिलेवरी कराना है तो इतना हजार रुपये। मरीज से कॉन्ट्रैक्ट फार्म पर हस्ताक्षर कराए जाने लगे। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बाजार आधारित हो गईं। यहां पर लाभ-हानी की कहानी गढ़ी जाने लगीं। ऐसे में यह जरूरी हो गया कि इन सेवाओं को कानून के दायरे में लाया जाए ताकि खरीदार को कोई बेवकूफ न बना सके, उनसे ओवरचार्ज न कर सके। गलत इलाज न कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय न्यायालय ने समय -समय पर दिए अपने आदेशों में यह स्पष्ट कर दिया है कि चिकित्सा संबंधी जितनी भी सेवाएं हैं उसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 के सेक्शन 2 (1) के तहत अनुबंधित सेवा माना जायेगा। इस तरह स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं कानून के दायरे में आ गईं। इसके इतर भी कुछ प्रमुख कानूनी अधिकार हैं, जो हमें स्वास्थ्य के अधिकार की ओर लेकर जाते हैं। ये अधिकार निम्न हैं-

- मानसिक स्वास्थ्य एक्ट, 2017
- एचआईवी एड्स एक्ट-2017
- खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट-2006
- ट्रांस्पलाटेंशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट-1994
- उपभोक्ता संरक्षण एक्ट- 1986
- ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट-1940

स्वास्थ्य सुरक्षा की जरूरत आखिर क्यों

राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण के चेयरमैन ने सरकारी वेबसाइट पर दिए अपने संदेश में लिखा है कि भारतीय अंग्रेजी दवा

व्यापार का वार्षिक टर्नओवर 1 लाख 28 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का हो गया है। जबकि भारत में 82 हजार करोड़ रुपये की दवा की खपत सिर्फ भारतीय बाजार में हैं। यानी हम भारतीय सिर्फ दवा पर एक वर्ष में 82 हजार करोड़ रुपये खर्च करते हैं।1 इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुरक्षा की कितनी जरुरत है।

सच्चाई यह है कि किसी भी राष्ट्र-राज्य के नागरिक-स्वास्थ्य को समझे बिना वहां के विकास को नहीं समझा जा सकता है। दुनिया के तमाम विकसित देश अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से चिंतनशील व बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रयत्नशील रहे हैं। नागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य राष्ट्र की प्रगति को तीव्रता प्रदान करता है। इतिहास गवाह रहा है कि जिस देश के लोग ज्यादा स्वस्थ रहे हैं, वहां की उत्पादन शक्ति बेहतर रही है। और किसी भी विकासशील देश के लिए अपना उत्पादन शक्ति का सकारात्मक बनाए रखना ही उसकी विकसित देश की ओर बढ़ने की पहली शर्त है। ऐसे में भारत को पूरी तरह कैसे स्वस्थ बनाए जाए यह एक अहम् प्रश्न है। अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय नागरिकों को पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य-सुरक्षा कैसे दी जाए आज भी एक यक्ष प्रश्न है। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि 2008 में रिसर्च एजेंसी अर्नेस्ट एंड यंग व भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत के लोग अपने स्वास्थ्य बजट का 72 प्रतिशत दवाइयों पर खर्च करते हैं। इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया था कि महंगी दवाइयों के कारण प्रत्येक वर्ष भारत की 3 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से ऊबर नहीं पाती। इसका अर्थ यह हुआ कि देश की लगभग 4 करोड़ आबादी प्रत्येक वर्ष इसलिए गरीब रह जा रही है, क्योंकि उसके पास महंगी दवाइयां खरीदने की आर्थिक ताकत नहीं है। ऐसी स्थिति में गरीबों को दिए जाने वाला स्वास्थ्य कवरेज गरीबी को कम करने का एक ताकतवर साधन भी सिद्ध होगा, ऐसा समीक्षकों का मानना है।2

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

भारत के गरीब जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की थी। लेकिन इस योजना को धरातल पर लाने में पूर्ववर्ती सरकारें सफल नहीं हो पायीं। आंकड़ों की माने तो 31 अगस्त 2015, तक इस योजना के अंतर्गत 40,430,289 स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं जबकि 10,630,269 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। इसी सुरक्षा को आगे बढ़ाते हुए इस सरकार ने बीपीएल परिवार को 1 लाख रूपये का स्वास्थ्य

बीमा देने का निर्णय किया है। आज के समय में जब स्वास्थ्य सेवा इतनी महंगी होती जा रही है स्वास्थ्य बीमा एक जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है। इसके लिए देश के तमाम सरकारी-गैरसरकारी बीमा कंपनियां नई-नई स्कीमों के साथ बाजार में है। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति लोगों के मन जागरुकता भाव ही उन्हें बीमा कराने के लिए प्रेरित कर सकता है।

बचाव ही ईलाज है

किसी भी बीमारी से बचाव की पहली कसौटी यह होती है कि उस बीमारी के बारे में हम कितना जानते हैं। अगर हम उस बीमारी के बारे में जागरुक होंगे तो निश्चित रुप से उस बीमारी से बचाव आसान हो जाता है। यहीं कारण है कि भारत सरकार बीमारियों से बचाव के लिए समय-समय पर जागरुकता कार्यक्रम चलाती रही है। आइए इनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करें-

मलेरिया

मलेरिया परजीवी से फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है। मच्छरों की 9 प्रमुख प्रजातियां मलेरिया कारण बनती है। 1940-50 के दशक में मलेरिया ने भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। यहीं कारण है आजादी के बाद भारत सरकार ने 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान लोगों को मलेरिया के बारे में जागरुक किया जाता रहा। डीटीडी का छिड़काव भी होता रहा और अगले 5 वर्षों में मलेरिया से मरने वालों की संख्या में काफी हत तक कमी आई। 1958 में सरकार ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम का दायरा बढ़ाते हुए इसका नाम मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम रखा। वर्तमान में मलेरिया से होने वाली मौतों पर हम रोक लगाने में भारत लगभग सफल हो चुका है। अब प्रति 1000 व्यक्ति पर मलेरिया से पीड़ितों की संख्या से 2 से भी कम है। 3

फाइलेरिया

लिम्फौटिक फाइलोरिएसिस एक ऐसी गंभीर बीमारी हे, जो शरीर के अंगों को काफी कमजोर और अयोग्य बना देती है। यह बीमारी क्यूरलेक्सस म्क्वीरनक्यू फेसीएटम नाम विषाणु से फैलती है। मच्छर इस विषाणु के वाहक हैं। वर्ष में एक बार सामूहिक रूप से फाइलेरिया निरोधी दवा पिलाकर विश्व स्तर पर 2020 तक इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है।4

डेंगू बुखार-वर्तमान समय में डेंगू बुखार से दिल्ली सहित भारत के कई क्षेत्र परेशान हैं। इससे बचाव एवं रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार बड़े-बड़े होर्डिंग्स एवं बैनरों तथा अखबारों में विज्ञापन देकर लोगों को जागरुक करने का प्रयास कर रही हैं। इस बीमारी की पहचान 60 के दशक में कोलकाता परिक्षेत्र में हुई थी। चूंकि डेंगू का कोई विशेष उपचार अभी तक आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के पास नहीं है अत: इससे बचाव ही इसका ईलाज है। और बचाव के लिए जागरुकता जरूरी है।

चिकनगुनिया -यह भी मच्छर जनित बीमारी है। अत: इससे बचने के लिए भी मच्छरों बचने का सुझाव सरकार देते रहती हैं।6

जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई)-अभी हाल ही में जापानी इंसेफलाइटिस एवं एक्यूट इंसेफलाइटिस से भारत के उत्तरप्रदेश राज्य के गोरखपुर में हजारों बच्चों की जान गई है। जिसकी चर्चा मीडिया में की खूब हुई। इस बीमारी से 1952 में भारत में इस बीमारी का पहला मामला आया था। तब से लेकर अब तक इस बीमारी ने बहुत तबाही मचाई है। इसको लेकर सरकार प्रभावित क्षेत्रों में जागरुकता अभियान चलाते रहती हैं। लेकिन जबतक सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी (सलाह)

को हम नहीं मानेंगे इस तरह की बीमारियों से बचाव आसान नहीं है।7

कालाज़ार-इस बीमारी से निजात पाने के लिए सरकार ने वर्ष 1990-91 में कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूवात की है। सरकार की ओर से डीटीटी का छिड़काव कराने के साथ-साथ गहन सामाजिक जाकरुकता पर सरकार का बल है।8

क्षयरोग (टीवी) -भारत में टीवी यानी क्षय रोग एक गंभीर समस्या है। आज भी इस बीमारी से सालाना लाखों लोगों की मौत हो रही है। इस बीमारी से निजात पाने के लिए सरकार 1962 से लगी हुई है। इस वर्ष राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगर इस बीमारी का उन्मूलन नहीं हो पाया है इसका मतलब यह है कि इसके प्रति लोगों के बीच में जागरुकता का अभाव है।9

अस्वच्छता जनित बीमारियां

साफ-सफाई की कमी के कारण भी तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए स्वस्थ रहने की पहली कसौटी है कि साफ-सफाई। इस दिशा में भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के अंतर्गत सरकार ने प्रत्येक भारतीयों को स्वच्छता के फायदे बताने का काम कर रही है। स्वच्छ भारत अभियान बीमारियों से बचाव की दिशा में उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा कैंपेन है।10

सोशल मीडिया में स्वास्थ्य संबंधी जागरुता

सोशल मीडिया के प्रभाव का असर स्वास्थ्य जागरुता पर भी पड़ा है। स्वास्थ्य संबंधी जागरुता में फेसबुक, यूट्यूब, स्वास्थ्य वेब पोर्टलों ने अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी है। अगर फेसबुक ट्वीटर की बात करें तो दर्जनों हैशटैग ऐसे हैं जिनके माध्यम से आम लोगों को जागरुक किया जा रहा है। उनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं-

- स्वच्छ भारत अभियान
- स्वस्थ भारत अभियान
- स्वस्थ भारत
- हेल्थी इंडिया
- सेकेंड ओपिनियन
- नो योर मेडिसिन
- नो योर फार्मासिस्ट
- कंट्रोल मेडिसिन मैक्सिमम रिटेल प्राइस
- #PMBJP (Pradhanmantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana) (पीएमबीजेपी)
- स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज

टीवी शो/फिल्म/यात्रा से स्वास्थ्य जागरुकता

देश के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरुक करने के लिए कई स्तरों पर जागरुकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसे टीवी शो, फिल्म एवं यात्राओं का भी योगदान है। दूरदर्शन पर चलने वाला स्वस्थ भारत कार्यक्रम देश के दर्जनों भाषाओं में बीमारियों के बारे में लोगों को जागरुक करता रहा है। 11

मेडिकल साइंस में सेकेंड ओपिनियन का बहुत बड़ा महत्व है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एबीपी न्यूज ने सेकेंड ओपिनियन नामक सत्य घटनाओं पर आधारित कार्यक्रम दिसंबर, 2012 में दिखाया था।12

इसके अलावा सरकारी गैरसरकारी स्तर पर लोगों को जागरुक करने के लिए यात्राएं भी निकाली जाती रही हैं। हाल ही में भारत के कुछ युवाओं ने 21000 किमी की स्वस्थ भारत यात्रा निकाली थी। इसमें उन्होंने देश भर में घूमकर लोगों को स्वास्थ्य-चिंतन के बारे में जागरुक किया। 20 सदस्यों का एक यात्री दल मानसिक स्वास्थ्य को लेकर देश भ्रमण पर निकला हुआ है। इसी तरह पिछले दिनों 'अंकूर अरोड़ा मर्डर केश' नामक एक हिन्दी फीचर फिल्म प्रदर्शित हुई थी, जिसमें मेडिकल निगलीजेंस को फिल्माया गया था। सत्यमेव जयते में आमीर खान ने जेनरिक मेडिसिन पर लोगों को जागरुक करने वाले कार्यक्रम किए। इसी तरह रांची से निकलने वाला दैनिक पत्र प्रभात खबर ने 'डॉक्टर कथा' नाम से कई स्टोरी प्रकाशित की थी ताकि लोगों को उनके स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के प्रति सचेत किया जा सके। www.swasthbharat.in एवं www.medicarenews.in जैसे वेब मंच लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरुक करने लिए निजी रुप से लगे हुए हैं। सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण पिछले पांच वर्षो में स्वास्थ्य रिपोर्टिंग में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

उपभोक्ता-उत्तरदायित्व

उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकारें लगातार उपाय करती रही हैं। लेकिन यहां पर यह भी जरूरी है कि उपभोक्ता अपने उत्तरदायित्व को भी समझे। इसे निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है।

स्वयं सहायता का दायित्व: ग्राहकों को कोई भी सामान खरीदने के पूर्व उससे संबंधी जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। दुकानदार को अंतिम सोर्स मानने की भूल ग्राहक को नहीं करनी चाहिए। शुरू से ही जागरूक हो जाना एवं अपने आपको तैयार कर लेना हानि होने अथवा क्षति पहुंचाने के पश्चात उसका निवारण करने से, सदा श्रेष्ठ होता है।

लेन-देन का प्रमाण: उपभोक्ता का दूसरा दायित्व क्र य का प्रमाण एवं स्थायी वस्तुओं के क्रय से संबंधित प्रपत्रों को प्राप्त करे एवं उसे सुरक्षित रखे। जैसे अगर आपने कोई दवा खरीदी है तो उसका पक्का बिल जरूर लें ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर आप कंपनी अथवा दुकानदार को उपभोक्ता फोरम में चैलेंज कर सकें।

उचित दावा:उपभोक्ता का एक और दायित्व, जो उसे मस्तिष्क में रखना चाहिए, है कि शिकायत करते समय एवं हानि अथवा क्षति होने पर उसकी पूर्ति का दावा करते समय अनुचित रूप से बड़ा दावा नहीं करें। कभी-कभी उपभोक्ता अपने निवारण के अधिकार का उपयोग न्यायालय में करता है। ऐसे भी मामले सामने आये हैं जिनमें उपभोक्ता ने बिना किसी उचित कारण के क्षतिपूर्ति की बड़ी राशि का

दावा किया है।13

स्वास्थ्य संबंधी सूचना के विभिन्न सरकारी मंच

सरकार ने विभिन्न माध्यमों से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहुंचाने के प्रयास किए हैं। मोबाइल एप, वेबपोर्टल एवं टोल फ्री नंबरों के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुनने एवं उसके समाधान के दिशा में सरकार के ये प्रयास बेहतरीन है। इसे आप भी जानें-

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल - भारत सरकार ने राष्टीय स्वास्थ्य पोर्टल की शुरूआत की है जहां पर स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही है। इतना ही नहीं यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई जानकारी प्राप्त करनी हैं तो राष्ट्रीय हेल्प लाइन संख्या-1800-180-1104 पर संपर्क किया जा सकता हैं। अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, बांग्ला एवं गुजराती भाषा में यहां से सूचना प्राप्त की जा सकती है। 14
- अगर स्टेंट की कमी का मामला कहीं सामने आता हैं तो आप सीधे इसकी सूचना/शिकायत 1800-111-255 पर दी जा सकती है।15
- फार्मा संबंधी समस्याओं की शिकायत करने के लिए भारत सरकार के रसायन मंत्रालय के अधिन आने वाले राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण ने फार्मा जन समाधान कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत आप 1800-111-255 पर फोन कर के अपनी समस्या जैसे दवा नहीं मिलना, दवाइयों पर ओवरचार्जिंग जैसे मुद्दों को पंजीकृत करा सकते हैं।16
- स्वस्थ भारत मोबाइल एप- भारत सरकार ने एक एप बनाया है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सुझाव एवं बीमारियों के लक्षणों को बताया गया है। इस एप को आप इस लिंक (https://www.nhp.gov.in/mobile-app-swasth) पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अथवा गुगल प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है।17
- फार्मा सही दाम- राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने फार्मा सही दाम के नाम से एक सर्च इंजन (http://nppaindia.nic.in/nppa-price/pharmasahidaamweb.aspx) बनाया हैं जहां पर आप जाकर दवाइयों के राष्ट्रीय मूल्य को जान सकते हैं। इसी नाम से मोबाइल एप भी बनाया गया है जिसे इस लिंक (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nic.app.searchmedicineprice) से डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार आपसे तय मूल्य से ज्यादा कीमत वसूली जाती है। ऐसे में यह ऐप बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है।18
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन- भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों के हनन के संबंध में शिकायत करने के लिए जागो ग्राहक जागों कैंपेन के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन शुरु किया है। कोई भी उपभोक्ता जिसे लगता है कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है वो 1800-11-4000 इस नंबर पर शिकायत कर सकता है। 19

अन्य महत्वपूर्ण हेल्पलाइन्स (20)

- नेशनल टोबैको क्वीट लाइन-1800-11-2356
- किलकारी एमहेल्थ सेवा-1800-3010-1703। ध्यान रहे झारखंड, उडीसा, उत्तरप्रदेश उत्तराखंड एवं मध्यप्रदेश तथा राजस्थान के कुछ जिलों में ही यह सेवा अभी लागू है।
- आशा मोबाइल अकादेमी-1800-3010-1704। ध्यान रहे यह न. झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखंड के लिए ही वैध है)
- टीबी कंट्रोल प्रोग्राम मिस्ड कॉल सेंटर-1800-11-6666। यह न. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एवं दिल्ली के लिए वैध है।
- एड्स हेल्पलाइन-1097
- एंटी प्वाजन हेल्प लाइन-1066
- एंबुलेंस हेल्पलाइन-102

निष्कर्ष

स्वास्थ्य का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इस क्षेत्र में आर्थिक लेन-देन का दायरा भी व्यापक है। ऐसे में जब तक उपभोक्ता अपने अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति जागरुक नहीं हो जाता है, तब तक भारत में स्वास्थ्य की स्थिति में बेहतर सुधार की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। बीमार होने से अच्छा है की बीमार न पड़े इसके लिए काम किए जाएं। ऐसे में अगर हम सभी अपने-अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरुक हो जायेंगे तो निश्चित रूप से हम गांधी के स्वस्थ भारत के सपने को पूर्ण कर पाएंगे। दरअसल स्वास्थ्य केवल सरकार का मसला नहीं है बल्कि यह हम सबका अपना मामला है। स्वास्थ्य को प्राथमिक स्तर से एक विषय के रूप में गर पढ़ाना शुरू किया जाए, तो यह स्वास्थ्य जागरुकता एवं स्वास्थ्य उपभोक्ता जागरुकता की दिशा में एक सार्थक पहल सिद्ध हो सकता है।

संदर्भ-

1- http://www.nppaindia.nic.in/
2- www.swasthbharat.in
3, 4, 5, 6, 8, 9 - https://archive.india.gov.in/hindi/sectors/health_family/index.php?id=8
7,10-www.swasthbharat.in
11- https://www.youtube.com/watch?v=YclpJWSmUb0
12-http://swasthbharat.in/category/sba-videos
13https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE
14-https://www.nhp.gov.in/national-health-helpline-toll-free-number-1800-180-1104-nhp-voice-web_pg
15 - http://www.newsbharati.com/Encyc/2017/5/4/Stents-Shortage
16-http://www.nppaindia.nic.in/
17- https://www.nhp.gov.in
18-http://www.nppaindia.nic.in/
19-http://www.nationalconsumer-helpline.in/online-complaint-system.aspx
20- https://www.nhp.gov.in/national-help-lines-_pg

नेपाल के अरबपति बिनोद चौधरी की आत्मकथा का विमोचन

नेपाल के विश्वविख्यात उद्योगपति और सांसद बिनोद चौधरी की आत्मकथा एक ऊँची उडान का विमोचन एक भव्य समारोह के बीच इंडिया इंटरनेशनल सेण्टर नई दिल्ली में किया गया! राजपाल एंड संस द्वारा प्रकाशित यह आत्मकथा अंग्रेजी में बेस्टसेलर मेकिंग इट बिग का हिंदी संस्करण है! इस आत्मकथा के माध्यम से बिनोद चौधरी ने आम लोगों को अपने जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से जोड़ने और प्रेरित करने का भरपूर प्रयास किया है ! एक सामान्य स्तर से विश्व के प्रभावशाली उद्यमियों के बीच शुमार होने का यह सफर तमाम रोमांच से भरपूर है ! अद्भुत प्रतिभा के धनी बिनोद चौधरी की जीवन यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है जो हर मोड़ पर आपको रोमांचित करती है और भरपूर प्रेरणा देती है !

इस कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ संपादक एवं पत्रकार दीपक चौरसिया ने किया ! आत्मकथा का विमोचन एशियन हेरिटेज फाउंडेशन के संस्थापक एवं पद्मभूषण अवार्डी श्री राजीव सेठी, पूर्व सांसद पवन वर्मा, वरिष्ठ राजनैतिक संपादक प्रशांत झा, पूर्व भारतीय राजदूत श्री राकेश सूद द्वारा किया गया!

कार्यक्रम में राजनैतिक, सामाजिक, औद्योगिक एवं पत्रकारिता जगत के विशिष्ट लोगों की विशेष सहभागिता थी !

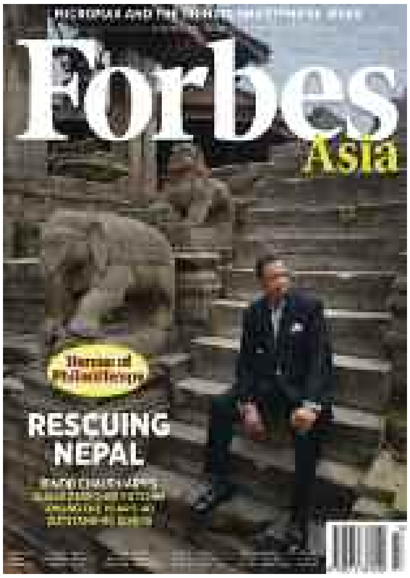

लेखक एवं पुस्तक का संक्षिप्त परिचय

एक ऊँची उडान नेपाल के पहले अरबपति की ऐसी प्रेरक आत्मकथा है जो आपको यह इस कथन को स्वीकार करने पर मजबूर कर देगी की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ! 30 से भी अधिक देशों में तेजी से फैलता सी डी कोर्प ग्लोबल का व्यवसाय एवं विश्व भर में युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा वाय वाय नूडल्स उसी कोशिश का जीवंत उदाहरण है ! इन सभी त्वरित सफलताओं के पीछे एक आदमी की अद्भुत इच्छाशक्ति और दिन रात का परिश्रम है जिसने उन्हें एक आम आदमी से नूडल किंग के रूप में मशहूर किया और आज नेपाल के इकलौते अरबपति के रूप में पहचाना जाता है ! बिनोद चौधरी एशिया के सबसे प्रमुख एवं प्रभावशाली व्यवसायियों में से एक है, जिन्होंने फूड, एफमसीजी, बैंकिंग, बीमा, वित्त, इन्फ्रा, होटल और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्र में निवेश किया है ! 2013 में वह फोर्ब्स द्वारा डॉलर अरबपति के रूप में सूचीबद्ध होने वाले पहले नेपाली उद्यमी बने। कठोर चुनौतियों का सामना करते हुए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उनका जुनून, प्रेरणादायक है इसलिए अनके नजदीकी लोग उन्हें आपदाओं को अवसरों में परिवर्तित करने वाले जादूगर कह कर संबोधित भी करते हैं ! उनकी सफलता और संघर्ष के अनेक प्रेरणादायक बिन्दुओ को समेटे हुए, पहले से ही नेपाल में एक विशाल बेस्टसेलर बन चुकी , बिनोद चौधरी की कहानी उन्ही की जुबानी अब हिंदी में भी उपलब्ध है !

हिन्दी 'साहित्य'
IAS / PCS
2017
2018
PRELIMS/MAIN'S
PRE CUM MAINS
SANSKRIT 'LITT'
संस्कृत 'साहित्य'
by
Dr. R. Singh
G.S. & ESSAY
सा. अध्ययन एवं निबंध
Career Plus
EDUCATIONAL SOCIETY
HEAD OFFICE
Centralised Enquiry : 09013060629
GS & CSAT
PUBLIC ADMN.
HISTORY
GEOGRAPHY
POL. SCIENCE
हिन्दी साहित्य
RAHUL PANDEY
ROHAN JHA
DEEPAK SHUKLA
PRABHAT KUMAR
CHINMAY ANAND JAIN
MODASSAR SHAFI
SUBHANSHU SHARMA
EHTESHAM WAQUARUR
BALAJI K.
PATNIKAR ANAND A.
SHASHANK TRIPATHI
NIDHI GUPTA
RAHUL RAJ
ROHINI (OUTER DELHI)
ALLAHABAD
NOIDA
RAIPUR
HALDWANI
REWA

This issue Published on 1st March, 2018 Postal Registration No. G-3/DL (N)/252/2017-19, Postal dt. 1st & 2nd Every Month

R.N.I. No. - DELHIN/2009/30089